हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 02.00 बजे अपराह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

30.03.2026/1400/RKS/DC-1

अध्यक्ष : प्रश्नकाल आरम्भ।

प्रश्न संख्याः 4182

श्रीमती कमलेश ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, देहरा विधान सभा क्षेत्र में मछुआरों की काफी संख्या है और उनकी आजीविका पूर्णतः मछली पालन पर निर्भर है। ये मछली पालक एक विशेष जाति से संबंधित हैं जिन्हें दरियाई या मछुआरा कहा जाता है। देहरा विधान सभा क्षेत्र में नंदपुर, हरिपुर और देहरा, तीन सहकारी सभाएं कार्यरत हैं। इन सहकारी सभाओं के अंतर्गत लगभग 1400 शेयरधारक और एक हजार लाइसेंसधारक शामिल हैं। महोदय, जब से पौंग डैम का निर्माण हुआ है तब से इस क्षेत्र के लोग विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यहां के लोगों की आय के मुख्य साधन मछली पालन तथा नाव संचालन जैसे छोटे व्यवसाय हैं। बरसात के मौसम या बाढ़ की स्थिति में पौंग डैम का पानी पीछे की ओर फैल जाता है जिससे मछुआरे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। वर्ष 2023 व वर्ष 2025 में जब इस क्षेत्र में बाढ़ आई थी तो उस समय इन लोगों के व्यवसाय में काफी प्रभाव पड़ा था। देहरा में जो पंजाब सरकार के समय पुल बना था वहां तक सिल्ट भर गई है। इस जगह के लगभग 10-15 किलोमीटर दायरे में मछुआरे रहते हैं। सिल्ट के कारण मछलियों की फिश ब्रीडिंग प्रभावित हो रही है तथा मछलियों की मूवमेंट में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। सामान्यतः मछलियां बहते हुए पानी में रहती हैं किंतु सिल्ट के जमाव के कारण उनकी मृत्यु हो रही है जिससे मछुआरा समुदाय काफी प्रभावित हो रहा है। एक दिन जब मैं उस क्षेत्र का दौरा कर रही थी तो मैंने देखा कि वहां साथ ही बी.बी.एम.बी. क्षेत्र में पिछले लगभग 50 वर्षों से एक छोटी-सी हट बनी हुई है जिसका आकार लगभग 10×10 फुट है। तूफान या बारिश के समय वहां मछुआरों के लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। जब मैं वहां से गुजर रही थी तो मैंने 5-6 मछुआरों से पूछा कि आपने आज कितनी मछली पकड़ी है?

श्री बी0एस0द्वारा जारी

30.03.2025/1405/बी.एस./डी.सी.-1

प्रश्न संख्याः 4182 क्रमांगत...

श्रीमती कमलेश ठाकुर जारी...

सर, मैं उनकी व्यथा सुनके बहुत प्रभावित हुई और मुझे बड़ा दुख हुआ कि यह सिर्फ इसी पर आधारित है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और बी0बी0एम0बी0 से भी बात करें कि जो सिल्ट है उसको उठाया जाए और उसको उठाने से सरकार को बहुत बड़ा लाभ होगा और उस पुल का भी बचाव होगा और हमारे जो मछुआरे लोग हैं उनका काफी आय का साधन बड़ेगा, धन्यवाद।

अध्यक्ष : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है वह सारा क्षेत्र बी0बी0एम0बी0 का है और बी0बी0एम0बी0 से जो परमिशन की बात है, वैसे ड्रेनेज के लिए और अपने वेल्थ के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है परंतु हमने ड्रेनेज पॉलिसी के तहत अभी कुल्लू में स्टार्ट किया तो निश्चित रूप से जहां नदियों में सिल्ट बहुत ज्यादा होगी या रेत बहुत ज्यादा हो गया है वहां सिर्फ माइनिंग हो रही है ड्रेनेज नहीं हो पा रही है और उसमें ड्रेजिंग की भी बहुत जरूरत है। हमारी सरकार ने अभी पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुल्लू में स्टार्ट किया है फिर मनाली में कर रहे हैं और फिर देहरा क्षेत्र और जहां भी हमारी नदियां बहती हैं, वहां ड्रेनेज करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा और उसकी ड्रेजिंग की जाएगी।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मछली उत्पादकों से संबंधित हमारी सरकार गंभीर है जो भी नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, चाहे देहरा है, चाहे बिलासपुर है, चाहे फतेहपुर है, मण्डी का क्षेत्र है, धर्मपुर है, जो भी नदी के किनारे हैं उनके लिए हमारी सरकार इस बजट में बहुत योजना लेकर आई है और उनके आय के साधन को सुनिश्चित करने के लिए भी हमने कहा कि जब दो महीने में मछली नहीं पकड़ी जाएगी उसमें हम हर परिवार को 3500 रुपया देंगे। एक तो उनकी आय को सुनिश्चित करना और जितनी मछली का उत्पादन होना चाहिए उस उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से भी बजट में प्रावधान किया है। हमने प्राइवेट पार्टीज को भी

लाने का प्रावधान किया है और मछली बहते हुए पानी में हो क्योंकि सिल्ट भर जाएगी तो निश्चित रूप से मछलियों को नुकसान होता है। इन सब चीजों का हमारी सरकार ने इस बजट में भी ख्याल रखा है और जो माननीय सदस्य ने कहा उस पर भी भविष्य में गौर किया जाएगा, धन्यवाद।

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है और मैं सबसे पहले तो मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो हमारी मछुआरा कम्युनिटी है उसके लिए मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी बजट में इतनी स्कीम्ज आई होंगी। तो उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन जो सवाल ड्रेजिंग का उठाया गया है, यह न केवल मत्स्य पालन बल्कि फ्लड कंट्रोल से भी सीधा संबंधित है।

सर, एक एडवांटेज यह है कि अनलाइक कुल्लू और बाकी जो हमारी नदियां हैं जहां पर हमको फॉरेस्ट की परमिशन और क्लीयरेंस चाहिए, अच्छी बात यह है कि जो हमारा लोअर बेल्ट है जो लोअर व्यास का एरिया है जिसके अंदर फतेहपुर, इंदौरा और बाकी जो ज्वाली और देहरा का एरिया है, यहां पर फॉरेस्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है जैसा कि आप एक पायलट प्रोजेक्ट अलरेडी कर रहे हैं। आपसे निवेदन यह है कि आप डी0सी0 महोदय को एक बार इंस्ट्रक्शन देकर कि क्या हम इसकी मैपिंग कर सकते हैं? तकि जिला कांगड़ा के लिए हमें जो मैपिंग और ग्राउंड वर्क करना है वह हम पहले से ही कर चुके हों।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमें मैपिंग करना जरूरी है कि कहां हमने ड्रेजिंग करनी है। मेरा मानना है कि हम इसमें माइनिंग और फोरेस्ट विभाग से कॉआर्डिनेशन करके आगे मैपिंग भी करेंगे और डिप्टी कमिश्नर को बोलेंगे कि जहां पुल के नजदीक बहुत ज्यादा सिल्ट भर चुकी है, उससे पुल को भी भविष्य में नुकसान न हो। भविष्य में इन सब चीजों पर विस्तृत विचार करने की जरूरत है। पहले भी हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट, जिसकी एफ0सी0ए0 वन हो चुकी है वह सफल हो जाए उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया में बढ़ेंगे। परंतु हम मैपिंग जरूर करेंगे, जैसा आपने कहा और लोकल एम0एल0ए0 को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा क्योंकि उन्हें ज्यादा

जानकारी होती है। डिप्टी कमिश्नर, लोकल एम0एल0ए0, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसमें आगे बढ़ा जाएगा।

30.03.2025/1405/बी.एस./डी.सी.-3

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से भी संबंधित है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

30.03.2026/1410/DT/HK -1

प्रश्न संख्या 4182 जारी...श्री जीत राम कटवाल जारी...

भाखड़ा डैम कि जो गोविंद सागर लेक में है उसका 60% एरिया मेरा चुनाव क्षेत्र में पड़ता है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे बताया कि एक मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस का एक नया सिस्टम लाया गया है, यह अच्छी बात है और हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो मछुआरों की फैडरेशन की इंकमम का कांसेप्ट है या इस पर बेस्ड कम्युनिटी जो गोविंद सागर लेकर किनारे या किसी अन्य जलाश्य के किनारे रहती हैं, उनके बारे में सरकार यह देखे कि जो फेडरेशन बनी हुई है, जो पहले डिफॉल्ट फेडरेशन्ज थी वही दोबारा टेकओवर कर गई और उन फेडरेशन्ज ने जो पहले लोगों के पैसों का गमन किया था या उस पैसे को मिसएप्रोप्रिएट किया थ ायह इशू अभी भी लोागों के मन में है। जिन लोगों ने ऐसा किया था वही लोग दोबारा ऐसी फडरेशन्ज में आ गये हैं। इन्हें भी मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस सरकार देने जा नही है जो अच्छी बात है लेकिन अगर इसका काम उन फेडरेशन्ज के थ्रू होगा इससे लागों को असुविधा ही नहीं बल्कि नुकसान ही होगीा इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सरकार की तरफ से इसका आबंटन सरकार की ओर से उचित ढंग से होना चाहिए। यह राशि उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो इसके अधिकारी है उनको ही मिले, सरकार क्यास इस प्रकार की व्यवस्था करेगी? मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यही जानना चाहूंगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कोऑपरेटिव फेडरेशन की बात की है जो पहले लिक्विडेट हो चुकी थी और दोबारा से फिर वह एक्टिव हुई है। फेडरेशन को तो

कोऑपरेटिव सोसाइटी ही देखेगी लेकिन जो भी यह गलत बात हुई होगी या जो भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि किस प्रकार से वही फेडरेशन्ज दोबारा से आ गई है तो मैं **इन सब चीजों का ध्यान रखूंगा और कॉपरेटिव डिपार्टमेंट को बोलूंगा कि जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसकी इंक्वारी करके मैटर को सरकार के सामने लाया जाए।**

30.03.2026/1410/DT/HK -2

श्री इंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती कमलेश ठाकुर ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया ह। जहां तक मुछआरों की बात है मेरे विधानसभा क्षेत्र से लेकर मंडी तक हमारे मछुआरे मछली मारते थे और उसके साथ जो सिल्ट आती है तो मछली तो मरती ही मरती है लेकिन उसके कारण लोगों के खेतों का भी नुकसान हो रहा है, उससे भी लोगों को आर्थक नुकसान काफी हो रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि जो सिल्ट डैक्टर है उसकी जो सिल्ट आती है उस सिल्ट की कोई न कोई व्यवस्था करके उस को दुरूस्त किया जाए क्योंकि लोगों के घ्झरों में जो पानी आता, कई बार तो मरी हुई मछलियां भी आ जाती है, इसलि उस सुकेती खड्ड का चैनलाइजेशन किया जाए, तभी उस सिल्ट को बाहर निकाला जा सकता है और मुछआरों को भी लाभ मिल सकता है। यही मेरा कहना है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सिल्ट की जो बात की है, यह समस्या हर जगह पर है। यह समस्या नदियों में है, खड्डों में है, इस दिशा में हम आगे बढ़ें हैं और निश्चित रूप से सिल्ट हटनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम भी करेगी। यदि अभी हमारा कुल्लू वाला पायलट प्रोजेक्ट अगर सफल होता है, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कई अड़चनें होती है जैस लीगल प्वाइंट ऑफ व्यू से कुछ अड़चने आती हैं। इस प्रकार की सभी अड़चनों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ा जा सकता है।

30.03.2026/1410/DT/HK -3

प्रश्न संख्या : 4183

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क है-सोलन-मिनस-राजगढ़ रोड, की स्थिति के बारे में है। यह सड़क मात्र एक मार्ग नहीं बल्कि हमारे सिरमौर, सोलन और शिमला के लाखों लोगों की यह जीवन रेखा है। मैं माननीय लो निर्माण मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि जो इस सड़क की स्थिति है वह बड़ी दयनीय है। लेकिन लोक निर्माण विभाग से जो उत्तर आया है उसमें कहा गया है कि इसकी स्थिति बहुत अच्छी है या रोड अच्छा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मैं माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार इस मार्ग को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अथवा किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत शामिल कर सकती है?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस सड़का का जिक्र माननीय सदस्या श्रीमती रीना कश्यप सजी ने किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, इस बात से मैं इत्फाक रखता हूं। लेकिन यह सत्य नहीं है कि सोलन-मिनस- राजगढ़-नौराधार-हरिपुर-रोहनाहाट मार्ग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। सोलन मिनस मार्ग-एम0डी0आर0-2 और इसकी कुल लंबाई 128 किलोमीटर है जिसका भाग जीरो से 9 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मंडल सोलन के अंतर्गत आता है जो की ठीक अवस्था में है। इस सड़क के भाग में किलोमीटर 9 से 24 छैला-नेरीपुल-ओछघाट-

श्री एन0जी0 द्वारा जारी.....

30.03.2026/1415/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या-4183.....जारी लोक निर्माण मंत्री..... जारी

-कुमारहट्टी पर जुलाई 2025 में Performance-Based Maintenance Contract (PBMC) के अंतर्गत पांच साल तक के रख-रखाव का कार्य सम्पन्न हुआ है और वर्तमान में सड़क की हालत संतोषजनक है। उक्त सड़क का भाग किलोमीटर 24/00 से 61/00

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, राजगढ़ मण्डल के अधीन आता है, किलोमीटर 61/00 से 110/00 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, संगड़ाह मण्डल के अधीन आता है और किलोमीटर 110/00 से 128/00 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिलाई मण्डल के अधीन आता है। इसका रख-रखाव हमने बीच-बीच में अलग-अलग मदों से करवाया है। ए0एम0पी0 के माध्यम से आर0डी0 62/00 से 65/00 यानी 3 कि0मी0 वर्ष 2024-25 में और इसी वित्तीय वर्ष में आर0डी0 98/00 से 102/00 यानी 4 कि0मी0 का कार्य करवाया है। इसी प्रकार पैच वर्क्स के तहत कुल 22 किलोमीटर का कार्य वर्ष 2023-24 व वर्ष 2024-25 में करवाया है। इसका जो भाग शिलाई मण्डल के अंतर्गत आता है, उसमें ए0एम0पी0 के तहत कुल 3 किलोमीटर का कार्य वर्ष 2023-24 व वर्ष 2025-26 में करवाया है। इसी प्रकार वर्ष 2025 में शिलाई मण्डल के तहत पैच वर्क्स का कुल 3 किलोमीटर का कार्य करवाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वूपर्ण सड़क है क्योंकि यह उत्तराखण्ड राज्य के इलाके को भी जोड़ती है। **अभी वर्तमान में इसको हमने पी0एम0 गति शक्ति पोर्टल में नहीं डाला है लेकिन आने वाले समय में यह हमारा प्रयास रहेगा और यह हमारी व सरकार की कमिटमैंट भी है।** हिमाचल प्रदेश में जो भी स्ट्रेटिज़िक रोड्स व इकोनोमिकल वाइबल रोड्स हैं, इस प्रकार की पांच सड़कों को हमने पहले चरण में केन्द्र सरकार को भेजा है। पहले यह कार्य Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) द्वारा करवाया जाता था, जिसके मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी हैं।

30.03.2026/1415/एच.के.-एन.जी./2

अब यह अलग विभाग है जिसे इकोनोमिक अफेयर कहते हैं और अब उसके पोर्टल पर इन रोड्स को अपलोड करना पड़ता है। हमने प्राथमिकता पर पांच रोड्स को लिया है। हम सभी जानते हैं कि पहले हिमाचल प्रदेश में 70-75 नेशनल हाइवेज़ घोषित हुए थे और वे अभी तक नहीं हो पाए हैं। उसके बाद वे कम होकर 25 और उसके बाद 20 रह गए थे। अब

हमने पांच रोड्स की प्राथमिकता भेजी है और उनकी स्वीकृति आनी अभी शेष है। **जैसे ही इनकी स्वीकृति प्राप्त होती है तो उसके बाद हम इस सड़क को भी प्राथमिकता पर पी0एम0 गति शक्ति पोर्टल में डालने का पूरा प्रयास करेंगे।**

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री से जानना चाहता हूं क्योंकि यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और जिला सिरमौर के तीन विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ते हुए उत्तराखण्ड की सीमा में लगती है। अनेक स्थानों पर इसकी चौड़ाई बहुत कम है और कई स्थानों पर तो सिंगल गाड़ी को क्रोस करने की भी जगह नहीं है। ए0एम0पी0 के तहत कार्य करने से इस सड़क का कुछ बनने वाला नहीं है। मेरा माननीय लोक निर्माण मंत्री से आग्रह है कि इंटर स्टेट कनैक्टिविटी के तहत इस सड़क को बनाया जाए। राजगढ़ से लेकर रोहनाट तक यानी तीन विधान सभा क्षेत्रों में इसकी लम्बाई लगभग 104 किलोमीटर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सड़क को सी0आई0आर0एफ0 के तहत डालने का आश्वासन देगी ताकि सड़क की चौड़ाई को भी बढ़या जा सके? इस सड़क की बहुत कम चौड़ाई है जिस कारण काफी दुर्घटनाएं होती हैं।

30.03.2026/1415/एच.के.-एन.जी./3

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी प्राथमिकता रहती है कि जितनी भी सड़कें, खासकर जो हमारे प्रदेश को अन्य राज्यों के साथ जोड़ती हैं, उनको कनैक्ट करवाना हमारी प्राथकिमता रहती है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री के सहयोग से उसी क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जोकि छैला-यशवंत नगर-नैरीपुल आदि को जोड़ती है, उसको हमने सी0आई0आर0एफ0के तहत डाला है। इस सड़क की ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें केन्द्र सरकार से कुछ समय के भीतर मिल जाएगी। क्योंकि सी0आई0आर0एफ0 के तहत जो पैसा हिमाचल प्रदेश या लोक निर्माण विभाग को मिलता है, वह पैट्रोल-डीजल पर जितना सैस लगता है व जितनी

कंजम्पशन है, उसके बेसिस पर यह पैसा प्रदेश को मिलता है। उसके अनुसार हमे जो सलाना एलोकेशन होती है, वह लगभग 150 करोड़ रुपये है। इस फण्ड के अगेंस्ट सैंक्शन्ज़ तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं लेकिन उतना पैसा नहीं मिल पाता। फिर भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि यह महत्वपूर्ण सड़क है और हम इसे आने वाले समय में पी0एम0 गति शक्ति में डालने का प्रयास तो करेंगे ही

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

30.03.2026/1420/वाई0के0/ए0पी0-01

प्रश्न संख्या 4183 जारी .....लोक निर्माण मंत्री जारी .....

लेकिन आने वाले साल में सी0आर0एफ0 में भी प्रपोजल बन सकता है। वहां पर भी इसे डालने का प्रयास किया जाएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड यह बात कह रहा हूं कि प्रदेश को जो एलोकेशन मिलता है और डीजल व पेट्रोल पर जो हमारा सेस है, उसी के आधार पर यह मिलता है। इसलिए हमें इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को भी समझना होगा। प्रदेश का जितना कोटा है, उतनी ही सड़कों को हम प्रस्तावित करके केन्द्र को भेज सकते हैं। उसी के अंतर्गत सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा।

30.03.2026/1420/वाई0के0/ए0पी0-02

प्रश्न संख्या : 4184

श्री चन्द्र शेखर (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय , मेरे सहयोगी आदरणीय श्री भुवनेश्वर गौड़ जी पारिवारिक स्थिति के कारण हाउस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ से यह सवाल माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रख रहा हूं। इस पर मैडम श्रीमती कमलेश ठाकुर जी ने जो शुरुआत में सवाल रखा था उसमें भी काफी कुछ माननीय मुख्य मंत्री जी ने कवर किया है। चूंकि यह पायलट आधार पर चलाया गया है और अभी तक इसे कुल्लू क्षेत्र में ही कंफाइन किया गया है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि ब्यास नदी का नेरो

हिस्सा जो मनाली की तरफ है। हाल ही में मनाली पिछले दो बरसातों में बड़े डिजास्टर का विटनेस रहा है। जिससे वहां पर काफी मलबा रुका हुआ है। उस क्षेत्र में ब्यास नदी दोनों तरफ अपना प्रभाव बदलती रहती है। जिससे वहां की कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या बरसात से पहले हम इस स्थिति में होंगे कि मनाली को राहत मिल पाए, ताकि जो ड्रेजिंग का कार्य मनाली की तरफ से भी शुरू हो सके। क्योंकि हम स्टेज-वाइज चल रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस बार भी हम मनाली में ही फंस जाएं और वहां की जनता को बड़ा नुकसान उठाना पड़े। मैं अपने आपको भी इस प्रश्न में शामिल कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी तीन खड्डे ऐसी हैं। जहां तीन बड़े पुल इस समय इसकी जद में हैं। क्योंकि पूरा मलबा उन पुलों के आसपास पहुंच चुका है। उनको हटाने के लिए जैसा कि माननीय सहयोगी सदस्यों ने कहा कि वन विभाग और खनन विभाग दोनों को मिलकर कुछ प्वाइंट चिन्हित करने चाहिए ताकि बरसात से पहले उन कार्यों को निपटाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। यह मेरा कंसर्न भी है, जिसे मैं माननीय श्री भुवनेश्वर गौड़ जी के सवाल के साथ जोड़ता हूं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं।

30.03.2026/1420/वाई0के0/ए0पी0-03

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी कुल्लू में ड्रेजिंग का काम चल रहा है। यदि इस वर्ष यह कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद मनाली को प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी वहां काफी नुकसान हुआ था। इसके अलावा मंडी क्षेत्र भी है। अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां से ब्यास, सतलुज और यमुना नुकसान करती हैं, वहां भी हमारी सरकार ड्रेजिंग करने में विश्वास रखती है। लेकिन इसके लिए एफ0सी0ए0 लेना पड़ता है। जब तक एफ0सी0ए0 की परमिशन नहीं मिलती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए माइनिंग विभाग और फॉरेस्ट विभाग दोनों को यह जिम्मेदारी दी गई है। जैसे ही कुल्लू में यह काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद मनाली हमारी प्राथमिकता में होगा। कुल्लू जिले में 42

साइट्स चिन्हित की गई हैं। जिनमें से 3 पर काम शुरू कर दिया गया है और इन 42 साइट्स में मनाली भी शामिल है।

श्री रणवीर सिंह (निक्का) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चक्रवती नदी, जो चुवाड़ी से होकर पंजाब की ओर जाती है। एक बहुत बड़ा दरिया है। उस खड्ड की आज तक कभी भी ऑक्शन नहीं हुई है और सारा मटीरियल बहकर पंजाब चला जाता है। हाल ही में नूरपुर में डी0जी0पी0 साहब ने आदेश दिया है कि कमर्शियल ट्रैक्टरों का चालान न किया जाए, बल्कि उन्हें जब्त किया जाए। इससे हमारे किसान भाइयों को परेशानी हो रही है। क्योंकि चक्की खड्ड का मटीरियल वही गरीब व्यक्ति उठाता है, जिसे ग्रांट से घर बनाना होता है या रास्ता बनाना होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा दरिया होने के बावजूद न तो सरकार को इसका रेवेन्यू मिल रहा है और सारा मटीरियल बहकर पंजाब चला जाता है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

30.03.2026/1425/AT/ YK/01

प्रश्न संख्या 4184 जारी....श्री रणवीर सिंह निक्का जारी...

हमारा यह एरिया चंबा जिले से होते हुए काफी लंबा क्षेत्र है और यह कांगड़ा जिला फॉरेस्ट एरिया में नहीं आता है। इसलिए इस पर फॉरेस्ट एक्ट भी लागू नहीं होता, जैसे चंबा, हमीरपुर और ऊना में होता है। मैं चाहता हूं कि ड्रेजिंग में इस चक्रवर्ती नदी को भी शामिल किया जाए ताकि लोगों को लीगल मटेरियल मिल सके। ट्रॉली वालों के पास कोई खास रोजगार नहीं है इसलिए अगर सरकार उस खड्ड की ऑक्शन करती है तो लोगों को लीगल मटेरियल मिलेगा और सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। यही बात मैं कहना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे और सुझाव लेने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ मिलकर आप इन्हें सुझाव दें। निश्चित रूप से जिस चक्रवर्ती नदी का आपने उल्लेख किया है अगर उससे सरकार को रेवेन्यू मिल सकता है और ऑक्शन करना उचित है तो उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक

और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ट्रैक्टर वाले हैं वे रोज़ कमाने वाले लोग हैं। हमारी सरकार इस पर विचार करेगी कि उन्हें छोटे-छोटे परमिट कैसे दिए जाएं ताकि वे अपना काम कर सकें। इससे सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा और वे चालान से भी बच सकेंगे। अभी स्थिति यह है कि पुलिस द्वारा अधिकतम पेनल्टी तीन या चार हजार रुपये निर्धारित है लेकिन कई बार पुलिस इसे लेने के बजाय छोड़ देती है। मेरा मानना है कि इन ट्रैक्टर वालों को कोई परेशान न करे और वे अपनी जीविका कमा सकें। इसके लिए ऐसा तरीका निकाला जाए कि वे पुलिस और माइनिंग विभाग से भी परेशान न हों और नदी से मटेरियल निकाल सकें। **हमारी सरकार जल्द ही इस संबंध में एक नीति लाएगी।**

Speaker : This is a very exhaustive reply by the Hon'ble Chief Minister. अब इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है।

30.03.2026/1425/AT/YK/02

श्री केवल सिंह पठानिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि कांगड़ा में पिछले चार-पांच दिनों से ट्रैक्टर यूनियन के लोग स्ट्राइक पर थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि डीजी द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई थी, जिसका ज़िक्र माननीय निक्का जी ने भी किया। पहले इनसे 4700 रुपये लिए जाते थे और महीने में तीन-चार चालान काटे जाते थे। अब ऐसी स्थिति है कि 22 ट्रैक्टर, जिनमें मनोहर लाल का ट्रैक्टर भी शामिल है, उसने 19 दिन बाद कोर्ट में जाकर उन्होंने यह ट्रैक्टर छुड़ाया है। एक ट्रैक्टर से पांच लोगों का परिवार चलता है। ड्रेजिंग की बात इस सदन में हो रही है तो मेरे इलाके में जैसे गज और बराल क्षेत्रों में बहुत सारा मटेरियल बाड़ग के कारण आया है। मैं इंडस्ट्री विभाग से भी हस्तक्षेप चाहता हूं कि जब ट्रैक्टर वालों ने ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के लिए खरीदे हैं। यहां सबसे बड़ा लिगल प्वाईंट यह है कि जब माननीय मुख्य मंत्री इंटरवैंशन करें कि तब पुलिस यह कहकर रोकती है कि आपने सब्सिडी ली है और यह ट्रैक्टर खेती करने के लिए लिए हुए हैं। जब वे अपनी आर0सी0 दिखाते हैं, तब भी पुलिस 4700 रुपये का चालान कर देती है। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जैसे सिरमौर, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर में जहां भी ट्रैक्टर हैं उनमें से लगभग 90 प्रतिशत एग्रीकल्चर के लिए गए हैं। इस पर सरकार और इंडस्ट्री विभाग मिलकर कोई

नीति बनाएं। अगर उनसे 100 या 200 रुपये लिए जाएं तो भी सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और अगर एक महीने में उनका 15000 रुपये चलान आएगा और 4700 रुपये चलान का रेट रखा जाएगा तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के लिए लिए गये हैं तो वह भी उन लोंगों के लिए एक रोजगार है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चहुंगा क्योंकि यह मनाली और कुल्लू में शुरू हो चुका है। मैं चाहता हूं कि यह हमारे इलाके में भी बहुत है। यह प्रदेश के अंदर हो पोंग के अंदर भी हो, मैं चाहता हूं कि ट्रैक्टर एग्रीकल्चर हैं उस पर कमेटी बनाई जाए इस पर तब राहत होगी चाहे 100 रुपये रखे या 200 रुपये रखे। इससे हिमाचल प्रदेश की सरकार को रेविन्यू आएगा। और बार-बार ट्रैक्टर वालों को पुलिस वाले भी परेशान नहीं करेंगे। यह मैं माननीय मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करता हूं।

30.03.2026/1425/AT/ YK/03

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को फॉरेस्ट एरिया में ड्रेजिंग के लिए अधिकृत कर दिया है। और फेजड मैनर में सब जगह जैसे एफ0सी0ए0 होगा। हम आगे माइनिंग विभाग के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। हमारी सरकार ट्रैक्टर वालों के लिए एक व्यापक नीति पर विचार कर रही है। हाल ही में विधायक दल की बैठकों में भी कई विधायकों ने यह मुद्दा उठाया कि ट्रैक्टर वाले गरीब लोग होते हैं और उनकी आजीविका इसी पर निर्भर होती है। कई बार एग्रीकल्चर के लिए लिया गया ट्रैक्टर माइनिंग में उपयोग हो जाता है, जिसके कारण पुलिस कार्रवाई करती है। नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में 4700 रुपये का चालान किया जाता है।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....

30-03-2026/1430/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या : 4184 जारी -- मुख्य मंत्री जारी ---

कई बार एग्रीकल्चर वालों का ट्रैक्टर माइनिंग के लिए चला जाता है और माइनिंग करता है। रूल्ज़ में ऐसा प्रोविज़न है कि उसका चालान काटते हैं और चालान भी 4700 रुपये

कटता है। ट्रैक्टर वालों को किसी प्रकार से कोई तंग ना करें, वे अपनी आय भी बढ़ाएं, माइनिंग भी करें और खेती-बाड़ी भी करें ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत हो इसलिए मैं इस 4700 रुपये के चालान में भी बदलाव करने जा रहा हूं। **हम इस दिशा में एक नीतिगत फैसला करेंगे और जहां माइनिंग के लिए रूल को चेंज करना होगा, चेंज करेंगे।** ट्रैक्टर वाला सुबह उठकर कमाई करता है और अगर उसको कोई पुलिस वाला मिल जाए तो उसकी कम से कम 5 दिन की कमाई चली जाती है। तो **हम ट्रैक्टर वालों को ढील देंगे और नियमों में परिवर्तन करेंगे। हमारी सरकार इसके लिए कृत संकल्प है।**

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि बरसात के मौसम में ब्यास नदी और सतलुज नदी में हर बार नुकसान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप ब्यास नदी की चैनलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि यह फेज्ड मैनर में करना होगा क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और वह एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट बनेगा। लेकिन स्थिति यह आ गई है कि मनाली से ले कर आगे तक जहां तक ब्यास का प्रवाह रहता है, बहुत सारी बस्तियां उसकी जद में आ चुकी हैं, उनको बचाना बहुत मुश्किल है। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि फेज्ड मैनर में, जहां-जहां घनी बस्तियां हैं, जहां इसके कारण घरों और जमीन को ज्यादा नुकसान हो रहा है और नेशनल हाईवे को नुकसान हो रहा है, उन प्वाइंट्स को प्राथमिकता के आधार पर ले कर इसकी डी0पी0आर0 बनाकर केंद्र के साथ मैटर टेकअप करेंगे? क्योंकि यह स्थिति स्टेट के बस की तो नहीं है। दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वर्ष 2025 में जो आपदा आई थी, जिसके कारण बहुत नुकसान हो गया था। उसके बाद जब सड़कें टूटीं और ब्यास नदी ने अपना नेचुरल कोर्स बदल दिया, उस हालात में जो बहुत सारा मलबा और रेत-बजरी इधर-उधर इकट्ठी हो गई थी, उसको हटाने के लिए क्या सरकार ने वहां पर जो मशीनें लगाई थीं, क्या उनकी प्रॉपर एफ0सी0ए0 की परमिशन थी? यदि हां, तो वह मलबा कहां

30-03-2026/1430/केएस/वाईके/2

गया? सच्चाई यह है कि दर्जनों मशीनें अपनी सुविधानुसार मनाली के नीचे ब्यास में, कुल्लू से ले कर नीचे तक बेतहाशा एक्सकेवेशन करने में लगीं। रात-दिन काम किया लेकिन अभी तक यह मालूम नहीं है कि वे लोग कौन थे जिन्होंने बड़े-बड़े पोकलेन, जे0सी0बी0 और बड़ी-बड़ी गाड़ियां, ट्रक लगाकर वहां से मटेरियल उठाया? क्या सरकार को उसकी रॉयल्टी प्राप्त हुई है और क्या उस सारी चीज के लिए सरकार की अनुमती थी? अभी तक यह मालूम नहीं हो पाया है कि वे कौन लोग थे,उन्होंने वहां से कितना मटेरियल निकाला और क्या उसकी परमिशन थी और क्या उसकी रॉयल्टी आपको प्राप्त हुई तथा क्या वह नियम के मुताबिक हुई? अगर नहीं हुई, तो क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम चैनलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ड्रेज़िंग की बात कर रहे हैं। ड्रेज़िग के लिए हमने कहा है कि फेज्ड मैनर में किया जाएगा और जब आपदा आती है, वैसे तो माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है परंतु अगर इन्होंने पूछा है तो बताना चाहूंगा कि आपदा के समय किसी भी सरकार की यही कोशिश होती है कि घरों को बचाया जा सके और उनको नुकसान ना हो, उस दृष्टिकोण से मशीने लगती हैं और उसके बिल बनते हैं। अभी मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

30.03.2026/1435/av/as/1

प्रश्न संख्या : 4184---------- क्रमागत

मुख्य मंत्री--------- जारी

अगर आप किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के बारे में बताएंगे तो मैं उस संदर्भ में सभा पटल पर जानकारी रख दूंगा। ...(व्यवधान) ब्यास नदी बहुत लम्बी है। यह नदी मनाली से लेकर नूरपुर तक जाती है। ...(व्यवधान) अगर आप पर्टिकुलर बताएंगे तो मैं उस बारे में सभा पटल पर सूचना रख दूंगा। ...(व्यवधान) वैसे तो आपका सवाल इस प्रश्न से कोई सम्बंध

नहीं रखता। ...(व्यवधान) मैं ड्रेज़िंग की बात कर रहा हूं। ...(व्यवधान) अगर कहीं पर ड्रेज़िंग के नाम पर किया होगा तो उसके बारे में पता करके जांच करवा लेंगे।

30.03.2026/1435/av/as/2

प्रश्न संख्या : 4185

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखी गई सूचना के 'क' भाग में कहा गया है कि गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा प्रदेश में 16 इंडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके 'ख' भाग के उत्तर में इन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से स्वीकृति तो 16 इंडोर स्टेडियम की दी गई है परंतु उसमें से 3 ही इंडोर स्टेडियम के कार्य शुरू हुए हैं जिनका मैं यहां पर नाम लेना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि जिला चम्बा में पुलिस मैदान चम्बा में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य 2.97 करोड़ रुपये से होगा और इसके लिए 1.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिसका अभी तक 10 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। दूसरा इसमें जिला किन्नौर में इंडोर स्टेडियम कल्पा का विस्तार, संशोधन और सौंदर्यीकरण के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी जिसमें से 70 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं और इसका भी अभी 10 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है। तीसरा इसमें कहा गया है कि इंडोर बहुउद्देश्यीय खेल परिसर खरीडी, नदौन का निर्माण कार्य 1,28,89,86,000/- रुपये से पूर्ण होगा। जिसके लिए 74.90 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है और इसका कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 16 स्वीकृत कार्यों में से जो अभी तक 13 कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं, इनके लिए बजट का प्रावधान करके इनका कार्य कब शुरू किया जाएगा? इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर के आशीर्वाद से लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत से एक इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा था। पूर्व सरकार के कार्यकाल में उसका काम शुरू हो गया था और वर्तमान में उसका आधा कार्य हो चुका है। लेकिन जब से यह व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार बनी है वहां पर पैसा न देने के कारण ठेकेदार भाग गया है। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन रहेगा कि क्या आप डिग्री कॉलेज बाशा के इंडोर स्टेडियम के

लिए भी पैसे का प्रबंध करेंगे ताकि डिग्री कॉलेज बाशा और सराउंडिंग के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। तीसरा, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में शायद नदौन का पहला

30.03.2026/1435/av/as/3

इंडोर बहुउद्देश्यीय खेल परिसर बन रहा है, क्या आने वाले समय में आप इसी तरह से जिला मण्डी में बहुउद्देश्यीय खेल परिसर बनाने का विचार रखते हैं।

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू की सरकार के कार्यकाल के तीन वर्षों के भीतर हमारे 16 प्रोजैक्ट सैंक्शन हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि प्रदेश के हर जिला के लिए ये प्रोजैक्ट सैंक्शन हुए हैं।

टी सी द्वारा जारी

30.03.2026/1440/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
प्रश्न संख्या : 4185 क्रमागत्
आयुष मंत्री .... जारी

जहां तक यह प्रश्न है कि अभी 16 में से केवल 3 प्रोजैक्ट का कार्य ही प्रारम्भ हुआ है, उसके पीछे कारण यह है कि उन स्थानों पर इसके भूमि उपलब्ध थी और सभी विभागीय एन0ओ0सी0 भी प्राप्त हो चुकी थीं।

आपने इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर खरीड़ी, नदौन के निर्माण की बात भी की है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह इंडोर स्टेडियम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। भविष्य में अन्य जिलों में भी इसी तर्ज पर जिला स्तर पर ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। जहां तक 13 लंबित मामलों की बात है, कांगड़ा जिला के देहरा और घुमारवीं सहित अन्य

स्थानों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। वर्तमान में विभागीय और कागजी कार्रवाई चल रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण होगी, इनका कार्य भी प्रारम्भ कर दिया जाएगा। जहां तक नाचन विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है, यह यहां सूची में नहीं दर्शाया गया है। इसके संबंध में मैं अवश्य जानकारी प्राप्त करूंगा और जैसे ही जानकारी उपलब्ध होगी, डिग्री कॉलेज के स्टेडियम हेतु बजट आबंटित कर दिया जाएगा।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, प्रायोरिटी नंबर 3 में मेरे शाहपुर विधान सभा क्षेत्र का चंबी मैदान आता है। चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो, इस मैदान का सदुपयोग अक्सर होता रहा है। माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री, दो बार गृह मंत्री और पूर्व विधि मंत्री सहित विभिन्न सरकारों द्वारा यहां रैलियां आयोजित की गई हैं। इसलिए यह एक ऐतिहासिक मैदान है। अध्यक्ष महोदय, जब स्पोर्ट्स विभाग द्वारा प्रारम्भिक प्लानिंग की मीटिंग हुई थी, तब मैंने इस मैदान के लिए सिंथेटिक ट्रैक का प्रस्ताव एम0एल0ए0 प्रायोरिटी के अंतर्गत दिया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

इसके अतिरिक्त मैंने चवाड़ी मैदान का भी कई बार उल्लेख किया है। यह भी कई चुनावों के दौरान एक प्रमुख मुद्दा रहा है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि चंबी और चवाड़ी दोनों मैदानों के विकास के लिए विभाग की क्या योजना है? मंत्री महोदय ने कहा कि इसकी डी0पी0आर0 बन चुकी है लेकिन डी0पी0आर0 तो वर्ष 1984-85 से भी पहले से

बनती आ रही है। तब मैं छात्र राजनीति में था। तब से लेकर चाहे पार्टी कोई भी रही हो यहां पर प्रधानमंत्री और सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएं हैं। जब केजरीवाल जी मुख्य मंत्री थे तो वे भी यहां आए थे। इसलिए इन मैदानों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जान जाए।

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि शाहपुर में लगभग एक करोड़ रुपये की राशि सरकार और विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है। मैं स्वयं माननीय विधायक के साथ वहां का दौरा भी कर चुका हूं। पहले

वहां फोर लेन का प्रस्ताव था जिसके कारण उसका कार्य लंबित हुआ। अब उसमें आवश्यक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की गई है। जहां तक चंबी मैदान का संबंध है, यह वास्तव में एक उत्कृष्ट और खुला मैदान है। स्पोर्ट्स विभाग द्वारा भारत सरकार को खेलो इंडिया के माध्यम से सिंथेटिक ट्रैक के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। **खेलो इंडिया 2.0 अप्रैल माह से प्रारम्भ होगा। हमने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि शाहपुर मैदान के लिए सिंथेटिक ट्रैक का प्रस्ताव निश्चित रूप से भेजा जाएगा।** चवाड़ी मैदान का संबंध माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र से है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में अवगत करवाया था कि यह मामला एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस के लिए भेजा गया है। जैसे ही क्लीयरेंस प्राप्त होगी, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

श्री अनिल शर्मा एन0एस0 द्वारा ... जारी

30-3-2026/1445/NS-DC/1

प्रश्न संख्या : 4185------ क्रमागत

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मण्डी के पड्डल में इंडोर स्टेडियम की बात कही है। मुख्य मंत्री जी ने रघुनाथ पद्धर में हैल्थ डिपार्टमैंट की जगह को ट्रांसफर करने के लिए कहा था और मैं लगातार तीन वर्षों तक उसकी प्रक्रिया में लगा रहा और जब यह नहीं हुआ तो मुझे पड्डल में इसकी डी0पी0आर0 बनवानी पड़ी। सभा जानते हैं कि पड्डल ग्राउंड में शिवरात्रि मेले की वजह से इंडोर स्टेडियम बनाना संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसी कड़ी के अंदर मैंने रघुनाथ के पद्धर में हैल्थ डिपार्टमैंट की जगह जो 60 वर्षों से पहले प्राइवेट जमीन थी, वह हैल्थ डिपार्टमैंट के नाम थी और उसको एक्वायर करने के लिए केस मंत्री जी के विभाग को भेजा था तथा उसकी वैल्यू 1.45 करोड़ रुपये थी। क्या लैंड एक्वायर करने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा और लैंड एक्वायर की जाएगी? हमने जो डी0पी0आर0 आपको भेजी है उसको पड्डल न भेज कर हम उसको रघुनाथ पद्धर में बना सकते हैं। शहर के अंदर उस जमीन की वैल्यू लगभग 20 करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह लैंड हैल्थ डिपार्टमैंट के कब्जे में है। नेगोशिएशन की वजह

से वे उस जमीन को 1.45 करोड़ रुपये में देने के लिए तैयार हो गए थे। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या आप उसको एक्वायर करेंगे? दूसरा, जो खेलो इंडिया-2.0 में है तो क्या आप पड्डुल खेल मैदान के लिए भी प्रपोजल भेजेंगे? तीसरा, मुख्य मंत्री जी ने बजट में कहा था कि अगर कोई जमीन मिलती है तो हम वहां पर स्पोर्ट्स हब बनाएंगे जैसा हमीरपुर में बना रहे हैं। मण्डी में नस्लोह के पास रेवेन्यू डिपार्टमैंट की 65 बीघे जमीन है। मैंने हैल्थ डिपार्टमैंट की जमीन छोड़ दी और मैं उसकी प्रोसैस के लिए 4 वर्षों तक लगा रहा तथा यह जमीन मुख्य मंत्री जी के बोलने के बावजूद भी ट्रांसफर नहीं हो पाई। मेरा अनुरोध रहेगा कि 65 बीघे जमीन नस्लोह में जो मण्डी के नजदीक है तो क्या विभाग के नाम उस जमीन को ट्रांसफर करने के लिए आदेश दिए जाएंगे क्योंकि यह वन भूमि नहीं है? मेरा आपसे यही प्रश्न है कि क्या आप उस जमीन को विभाग के नाम पर ट्रांसफर करने आदेश देंगे? दूसरा, 1.45 करोड़ रुपये की जमीन को भी एक्वायर करने के आदेश दिए जाएं?

30-3-2026/1445/NS-DC/2

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय अनिल शर्मा जी ने प्रस्तावित मैदान के बारे में कहा है तो मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि निःसंदेह आपने उसके ऊपर विस्तृत रूप से एक्सरसाइज की थी। वहां पर कुछ ऑब्जैक्शन्ज स्थानीय लोगों के भी आ रहे थे और वहां पर संघर्ष समिति के द्वारा भी कुछ ऑब्जैक्शन्ज भेजे गए थे। आपने सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है कि वहां पर लैंड एक्वायर की जाए ताकि वहां पर भव्य इंडोर स्टेडियम बन सके। **मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हम भविष्य में इसके ऊपर विचार करेंगे।** दूसरा आपने कहा कि खेलो इंडिया-2.0 की शुरुआत भारत सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में करेगी। भारत सरकार ने अभी हमें उसकी गाइडलाइन्ज जारी नहीं की है और अगले महीने भारत सरकार के साथ इस बारे में मीटिंग होगी। **जैसे ही प्रस्तावित मीटिंग होगी तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर मण्डी जिला में जमीन की उपलब्धतता होगी तो**

उनको एक प्रस्ताव भेजा जाएगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से स्पोर्ट्स कम्पलैक्स बनाया जाए।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि प्रदेश में कितने इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। माननीय मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र जसवां-प्रागपुर में इंडोर स्टेडियम प्रागपुर में बन रहा है लेकिन उस स्टेडियम का इसमें नाम ही नहीं है। क्या आपके विभाग को उस इंडोर स्टेडियम के बारे में मालूम ही नहीं है और वहां से कुछ पेमैंट्स हो गई हैं लेकिन अभी भी कुछ पेंडेंसी है और वहां से ठेकेदार काम छोड़ कर भाग गया है। क्या कारण है कि मेरे प्रागपुर स्टेडियम का इस लिस्ट में नाम नहीं है?

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो बात श्री बिक्रम सिंह जी ने रखी है तो खेल विभाग के पास उसकी कोई डिटेल नहीं है। शायद यह प्रोजैक्ट पहले कंपलीट हो गया होगा और पिछली सरकार में हैंड ओवर हो गया होगा। **माननीय सदस्य ने इसके बारे में कहा है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इसकी पूरी छानबीन करके इसी सत्र में आपको जानकारी दे दूंगा।**

प्रश्न संख्या : 4186 आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

30.03.2026/1450/RKS/HK-1

प्रश्न संख्याः 4186

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का काफी विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया है लेकिन मैंने जो प्वाइंट्स पूछे थे उनका उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि प्रदेश में वर्तमान में कितने नशा निवारण केंद्र तथा नशा उपचार क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं परंतु उत्तर में नशा क्लीनिकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरा, मैंने पिछली बार भी यह प्रश्न किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर पंजाब के लोगों द्वारा जो नशा क्लीनिक चलाए जा रहे हैं उन्हें संचालित करने की अनुमति किसने दी है? इनके विरुद्ध ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए हैं। एस.डी.एम., इंदौरा ने भी लिखित रूप में दिया है कि स्थानीय लोग नहीं चाहते कि यहां नशा क्लीनिक खोले जाएं

क्योंकि उन क्लीनिकों में भी अवैध रूप से नशा बेचा जा रहा है। अतः मेरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे प्रश्न की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। मुझे यह भी बताया जाए कि डमटाल से मिलवां तक जो नशा क्लीनिक संचालित हो रहे हैं उन्हें कब तक बंद करवाया जाएगा? पिछली कैबिनेट बैठक में मेरे विधान सभा क्षेत्र के मलौट में नशा निवारण केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस कार्य को कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा ताकि वहां पंजाब के लोगों द्वारा संचालित नशा निवारण केंद्रों एवं नशा क्लीनिकों को बंद करवाया जा सके क्योंकि वहां अधिकतर पंजाब के लोग ही उपचार के लिए आते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए विभाग द्वारा पूर्ण प्रयास किया गया है। माननीय सदस्य को जो अतिरिक्त डाउट है, वह यह है कि वहां पंजाब के लोगों को नशा निवारण केंद्र और नशा क्लीनिक खोलने की अनुमति दी गई है and these are Private Substance Use Disorders Treatment and Rehabilitation Centre. उनके द्वारा नशा निवारण केंद्र और नशा क्लीनिक खोले जाने पर इन्हें एतराज है। **मैं इस विषय पर गहनता से विचार करूंगा। जब मुझे इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी तो मैं माननीय सदस्य को अवगत करवा दूंगा।** However, his question is very-very important, there is no doubt about it. But as far as these things are being operated and they are under check ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई चैक नहीं करता there are Committees who check all their functions और इसकी रिपोर्ट समय-समय पर आती रहती है।

30.03.2026/1450/RKS/HK-2

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न किया था कि मलौट में नशा निवारण केंद्र कब तक खोला जाएगा?**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, **यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाएगा।**

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के बजट में जो कंडाघाट में एक आदर्श नशा निवारण केंद्र खोलने की घोषणा की थी उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? दूसरा, सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि प्रत्येक जिले में सरकारी स्तर पर एक नशा निवारण केंद्र खोला जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार ने अब तक कितने जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के बजट में जो सिरमौर में एक आदर्श नशा निवारण केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी उसकी अद्यतन स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि वर्ष 2023 के बजट में कंडाघाट में एक आदर्श नशा निवारण केंद्र खोलना प्रस्तावित था। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने नौणी के सामने एक उपयुक्त जगह चिन्हित की है और हम वहीं आदर्श नशा निवारण केंद्र खोलने जा रहे हैं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

30.03.2025/1455/बी.एस./एच.के.-1

प्रश्न संख्याः 4186 क्रमांगत...

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी...

उस जगह मैं दो या तीन बार स्वयं भी गया हूं। मैं समझता हूं कि नशा निवारण केंद्र हमारी सरकार की प्राथमिकता है और जो-जो भी आपने कहा है कि हर जिले में होंगे? वह निश्चित रूप से होंगे। अभी भी आप अगर ध्यान से देखें, क्योंकि जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी है उसके अधीन भी हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं। वह भी चाहते हैं कि हम किसी प्रकार की जो Oral Substitution Therapy है, इनके केंद्र भी खोले जाएं। इसलिए अभी हाल ही में इस प्रकार के ओ0एस0जी0 केंद्र खोले जा रहे हैं। आई0जी0एम0सी0 शिमला से हमीरपुर, नेरचौक मण्डी, जिला सिरमौर, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, बिलासपुर और कुल्लू में खोले जाएंगे। जो हमारा कोटला-बड़ोग वाला है उसमें टेंडर इशू कर दिया गया है। मैं स्वयं इस स्थान पर तीन बार गया हूं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 59 करोड़ से बनने जा रहा है और इसमें 21 करोड़ ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी (लोक

निर्माण) के खाते में डाल भी दिए गए हैं जो माननीय सदस्य को डाउट है कि हर जिले में नहीं खोला जा रहा है, वह गलत है, ये सभी जिलों में खुल रहे हैं। आर0एच0 कुल्लू में ऑलरेडी नशा मुक्ति केंद्र है और जो मेंटल हेल्थ केयर के तहत मंडी में भी रघुनाथ का पधर में 20 बिस्तरों वाला एक मॉडल नशा मुक्ति केंद्र ऑलरेडी ऑपरेशन में है।

इसी प्रकार से टाहलीवाल, अम्ब जो उपग्रह केंद्रों के माध्यम से नशा मुक्ति केंद्र हैं वहां भी हाल ही में एक और ओ0एस0टी0 केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, आई0जी0एम0सी0 सहित 7 स्थानों में भी कार्य किया जा रहा है और सरकार इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रही है।

जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हमारे गैर-सरकारी संगठन हैं वे भी इसमें कार्यरत हैं जिसमें कुल्लू, ऊना और हमीरपुर के पुनर्वास केन्द्र भारत सरकार द्वारा पोषित है। नूरपुर और कुल्लू जो महिलाओं हेतु हमने स्थापित किए हैं वह राज्य सरकार द्वारा

30.03.2025/1455/बी.एस./एच.के.-2

पोषित हैं। मैं नाम भी दे देता हूं, Gunjan Organization For Community Development Dharamshala, इसी की एक शाखा कांगड़ा में भी है और यह 15-15 बिस्तरों का संचालन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो कोटला-बड़ोग में केंद्र बनने जा रहा है यह एक it will be one of the State of Art institution and I assure the Hon'ble Member that we are very much aware about it and we doing lot of works.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो केन्द्र माननीय मंत्री जी ने गिनाए हैं ये तो जो अस्पताल हैं उनमें कुछ बेड उनके लिए रखे गए हैं। अलग से नशा निवारण केंद्र नहीं है। सरकार ने यह घोषणा की थी कि हर जिले में अलग से नशा निवारण केंद्र खोले जाएंगे और बिलासपुर में उसके लिए स्थान भी चयनित हुआ था, स्वारघाट में मिड हिमालयन प्रोजेक्ट की बिल्डिंग भी चयनित हुई थी जो खाली पड़ी थी। परंतु वहां पर अभी तक नशा निवारण केंद्र नहीं खुला। मेरा प्रश्न यह है कि वहां पर सरकार कब तक नशा निवारण केंद्र खोलेगी? और इस तरह के केंद्र अलग से जिलों में खोलने की जो घोषणा की गई है, वह

वास्तव में कब तक पूरी होगी? अस्पताल के बेड मत गिनवाइए वे तो पहले से ही चले आ रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, I am fully agreed with the concern shown by the Hon'ble Member, there are definite needs हमें जरूरत भी है कि **हम हर जिले में एक-एक नशा निवारण केंद्र खोलें और इसके बारे में हमारी आगामी योजना में पूरी संभावना है। जगह को चिन्हित करके सभी जिलों में नशा निवारण केंद्र खोलने का विचार है।**

प्रश्न काल समाप्त

अध्यक्ष : अब शून्य काल में विषय उठाए जाएंगे। मेरे पास 12 विषय आ चुके हैं और मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कम समय में अपना विषय रखें, ताकि सभी विषय शून्य काल में लिए जा सकें।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

30.03.2026/1500/DT/YK -1

अध्यक्ष जारी...

नेता प्रतिपक्ष जी, what is your Point of Order, पहले अपना प्वाइंट आफ आर्डर एक्सप्लेन कर लेना उसके बाद भाषण दीजियेगा।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है कि जो एंट्री टेक्स हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगाया है, उसके कारण प्रदेश का अन्य राज्यों के साथ एक तरह का कंफ्लिक्ट उत्पन्न हो गया है। हिमाचल प्रदेश का जो बार्डर का एरिया है उसमें हिमाचल के लोग भी प्रभावित हैं और प्रभावित होने के साथ वह नाराज हैं, गुस्से में हैं। यह स्थिति ज्यादा तब फलेयर-अप हुई जब पंजाब के वित्त मंत्री ने विधान सभा के अंदर इस प्रकार से बात कही थी की जहां हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर एंट्री टेक्स लगाया है तो हम भी हिमाचल की गाड़ियों पर एंट्री टेक्स लगायेंगे। जगह-जगह प्रदर्शन हो

रहे हैं और जगह-जगह लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। चिंता का विषय यह बना है कि अगर कोई व्यक्ति जो हिमाचल का है और पंजाब जा रहा है वहां पर कानून-व्यवस्था की ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे वहां जाने वाले हिमाचल के लोगों को परेशान किया जाए। यही नहीं अगर उनकी गाड़ियों के साथ कुछ इस तरह की घटना घटित हो गई तो क्या होगा? इसलिए इस तरह की सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार के ऊपर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस मामले का पंजाब की सरकार के साथ टेक-अप करें और दो सरकारें बैठ कर आपस इस विषय का समाधान निकालने कि दिशा में आगे बढें। हिमाचल प्रदेश की टेक्सी यूनियनस जो हैं वे भी नाराज हैं। पर्यटन के सैक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं वह भी नाराज हैं, क्योंकि इसका मेसिव इम्पैक्ट है। इसमें कोई दोराय नहीं कि इससे हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ंगी उस दिशा में यह आवयक है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि इस फैसले के पड़ोसी राज्य के साथ कोई कारण कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जो सही न हो। मेरे कहने का अर्थ है कि कोई ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी असुविधा का सामना करने पड़े। इसीलिए मैं चाहा रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी इस संदर्भ में संज्ञान ले कर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करे और वह कार्यवाही तुरंत करें।

30.03.2026/1500/DT/YK -2

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकर ने कोई नया एंट्री टेक्स नहीं लगाया। एंट्री टेक्स की फीस की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें कुछ ही जगहों में बढ़ोतरी हुई है उस पर केबिनेट ने निर्णय कर लिया है कि उस बढ़ोतरी को राशनालाइज किया जायेगा। क्योंकि जो हमने इसे एन0एच0ए0आई0 के फास्ट टेग के साथ जोड़ा है तो उस कारण कुछ जगह एंट्री टेक्स उसके कारण बढ़ा है। मैंने कहा है कि पांच किलोमीटर के दायरे में कि वहां उस टेक्स में पास के माध्यम से छूट दे दी जायेगी, इस संबंध ने केबिनेट ने फैसला कर लिया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि एंट्री टेक्स कई वर्षों से लगा हुआ है वह कोई नया नहीं है और जो बढ़ोतरी हुई है उसका एक कारण एन0एच0ए0आई0 के द्वारा इसे फास्ट टेग के

साथ अटैच करने के कारण भी ऐसा हुआ है। मैंने कहा है कि जो पंजाब के साथ प्रदेश के बार्डर लगते हैं वहां पर टेक्स की जो बढ़ोतरी हुई है उसको राशनालाईजेशन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब क्या है ...(व्यवधान) नहीं, नहीं। There is no clarification on Point of Order. In fact, this is not covered under the Point of Order. Yet I have given the permission being an important issue, as the same has been raised in this House, not once but many times. This ruling is very important. Before that you say anything, what is the clarification you seek? माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा है कि एन0एच0एच0आई0 के टोल टेक्स बेरियर्ज के फास्ट टेग के साथ लगाया गया है, क्या वह निर्णय हो चुका है? अगर वह निर्णय हो चुका है तो इसका मतलब कल के बाद यानी 31 मार्च के बाद, जो हमारा बार्डर है जहां एन0एच0एच0आई0 का भी टोल-टेक्स बेरियर है और आधे किलोमीटर के बाद हिमाचल प्रदेश

श्री एन0जी0 द्वारा जारी.....

30.03.2026/1505/वाई.के.-एन.जी./1

श्री रणधीर शर्मा..... जारी

का एंट्री टैक्स बैरियर है तो क्या वह बैरियर कल रात के बाद उठ जाएगा? क्या एंट्री टैक्स टोल टैक्स बैरियर पर ही इकट्ठा होगा? दूसरा विषय यह है कि जो एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, उस बढ़ोतरी के आधार पर टेंडर हो चुके हैं और ठेकेदारों ने कल रात 12:00 बजे के बाद वहां पर अपना स्टाफ नियुक्त करने की सारी योजना बना ली है। तो क्या आपने जो रेशनलाइजेशन करनी है, उसमें ठेकेदारों को विश्वास में लिया है? क्योंकि उनकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने तो टेंडर इसलिए ज्यादा रेट का लिया क्योंकि एंट्री टैक्स

में बढ़ोतरी हो गई थी। अभी आप कह रहे हैं कि कम करने का निर्णय हुआ है, तो उससे जो समस्या पैदा होगी, क्या उसका समाधान हो चुका है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कल से बॉर्डर पर पंजाब के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और धमकी दी है कि कल दिनांक 31 मार्च, 2026 की रात्रि 12:00 बजे के बाद वे बॉर्डर सील व जाम कर देंगे और वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह है कि इस विषय पर जो भी करना है उसे तुरंत करें। ठेकेदारों को भी विश्वास में लें और यदि अन्य एन0एच0ए0आई0 से कोई बातचीत करनी है तो उनको भी साथ लेकर इसका समाधान एक ही दिन में निकाला जाए ताकि कल शाम से जो स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है, वह स्थिति उत्पन्न न हो।

30.03.2026/1505/वाई.के.-एन.जी./2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, छोटी गाड़ियों के एंट्री टैक्स में तो कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इनके अलावा जो 10-12 टायर वाले बड़े वाहन हैं, उनकी एंट्री फीस को 130/- रुपये से बढ़ाकर 170/- रुपये किया गया है यानी के 40/- रुपये की बढ़ोतरी की गई है।यह इसलिए भी हुई है क्योंकि नेशनल हाईवे के साथ जो फासटैग अटैच किया है, उनकी भी कुछ फीस इसमें जोड़ी गई है। जो इनके क्षेत्र का मामला है, उसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है कि कल हटेगा या नहीं। मैं जानकारी प्राप्त करके आपको बता दूंगा। अभी मुझे यह जानकारी नहीं है कि आपके वहां जो दो किलोमीटर के आगे एंट्री टैक्स है, वह हट रहा है या नहीं। वैसे हटना चाहिए क्योंकि 2 किलोमीटर पीछे ही है लेकिन इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा।

30.03.2026/1505/वाई.के.-एन.जी./3

(माननीय सदस्य, श्री इन्द्र सिंह द्वारा शून्य काल के दौरान पशु पालन विभाग के अंतर्गत पशु सहायकों को रेगुलर करने और उनकी घटती संख्या से हो रही समस्याओं के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

अध्यक्ष : अब शून्य काल के विषय लिए जाएंगे। पहला विषय माननीय सदस्य श्री इंद्र सिंह का है और वे अपना विषय रख सकते हैं।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। मेरा विषय पशुपालन विभाग से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग में आरोग्य पशुधन योजना के अंतर्गत पशु सहायकों को रखा गया था, जोकि वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक 350 की संख्या में थे। अब यह संख्या घटकर वर्ष 2015 में 143 रह गई है। इनकी भारी कमी के कारण आज गांवों में जो पशुओं का इलाज किया जाता था, उसमें कमी आ रही है। मेरा माननीय कृषि मंत्री से निवेदन है कि जो माननीय कोर्ट द्वारा फैसला हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो 12 साल का सेवा काल पूरा कर चुके हैं, उनको नियमित किया जाए, तो क्या सरकार का ऐसा कोई प्लान है या नहीं? इसके अलावा जो 143 पशु सहायक 7 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, क्या उनको रेगुलर करने की सरकार कोई योजना बना रही है? यह मैं माननीय कृषि मंत्री से जानना चाहता हूं क्योंकि सरकार कहती है कि हम पशुधन को बढ़ावा देंगे और पशुधन से दूध बेचना तथा हमारे बच्चों को रोजगार मिलना, यह इससे जुड़ा हुआ मामला है। मेरा निवेदन रहेगा कि क्या इसमें आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे? धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वैसे तो आपका जो विषय मेरे पास आया था, वह नगर परिषद नेरचौक के डडोर वार्ड नंबर-9 को पंचायत में शामिल करने से संबंधित था।...(व्यवधान) आज आपका एक ही विषय लिस्ट हुआ है। फिर भी आपने जो यह विषय माननीय सदन में

रखा है, इसका संज्ञान माननीय सदन ने लिया है। आपने जो भी विषय उठाया है, उसे संबंधित विभाग से विधान सभा सचिवालय के माध्यम से टेक-अप करेंगे और की गई

30.03.2026/1505/वाई.के.-एन.जी./4

कार्रवाई से आपको और माननीय सदन को हम सूचित भी करेंगे। आपका जो दूसरा विषय है, वह आपने अभी उठाया नहीं है।...(व्यवधान) नहीं, तीन विषय नहीं उठा सकते। अधिकतम दो विषय ही उठाए जा सकते हैं। अभी आप बैठ जाएं, अन्य माननीय सदस्य बोलेंगे और उसके बाद अंत में आपको समय दे सकते हैं। One each, if I have a time I will allow the second issue. अब अगला विषय माननीय सदस्य, श्री अजय सोलंकी का है और वे अपना विषय रख सकते हैं।

(माननीय सदस्य, श्री अजय सोलंकी द्वारा शून्य काल के दौरान वन विभाग की भूमि के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

श्री अजय सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के ध्यान में जो विषय लेकर आया हूं, वह वन विभाग से संबंधित है। वन विभाग की

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

30.03.2026/1510/ए0एस0/ए0पी0-01

श्री अजय सोलंकी जारी .....

जो भूमि यमुनानगर, हरियाणा राज्य में स्थित थी। पिछले साल सितंबर 2022 की कैबिनेट बैठक में उस ज़मीन को मुक्त करने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया था। जबकि यह

ज़मीन वर्ष 1925 से शिमला जिला के चौपाल निवासी श्री मोती राम जी ने यमुनानगर में स्थित भूमि को जुब्बल स्टेट के वन विभाग के नाम लीज पर दी थी। उस समय यह ज़मीन लगभग 30 बीघा कुछ बिस्वा थी। जो बाद में घटकर लगभग 10 बीघा 14 बिस्वा रह गई। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गंभीर विषय है। एक तरफ हम प्रदेश की संपदा को लुटने से बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पिछली सरकार ने, मुझे नहीं मालूम उनके इरादे क्या थे? लेकिन यह एक बड़ा गंभीर विषय है कि प्रदेश की संपदा को साथ लगते राज्य में जो आज भी यमुनानगर में उस भूमि पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस स्थित है और अन्य इमारतें भी वहां मौजूद हैं, जो इस समय जर्जर हालत में है। लेकिन आज भी वहां वन विभाग का चौकीदार कार्यरत है, बिजली का मीटर वन विभाग के नाम पर है। उसका बिल डी0एफ0ओ0 नाहन द्वारा भरा जा रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स भी समय-समय पर दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गंभीर विषय है। सितंबर 2022 में जो निर्णय लिया गया था कि इस ज़मीन को रॉबिन बसीन और विशाल सरोए के नाम मुक्त कर दिया जाए। इसमें कुछ शर्तें भी निर्धारित थीं लेकिन उससे पहले ही उन्होंने 4 करोड़ 60 लाख रुपये विभाग के नाम स्थानांतरित कर इस पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया। आज भी इस मामले को लेकर उनके द्वारा कई न्यायालयों में केस किए गए हैं और विभाग न्यायालय में उनसे लड़ भी रहा है। लेकिन मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है और मैं उनसे जानना भी चाहता हूं कि जब यह विषय हमारे सदन के ध्यान में आ गया है, तो क्या इस पर कोई जांच बैठाने का निर्णय लिया जाएगा? यह ज़मीन यमुनानगर शहर के बीच हार्ट ऑफ द सिटी में स्थित है। पहले यह लगभग 30 बीघा थी। लेकिन अब लगभग 10 बीघा 14 बिस्वा ज़मीन रह गई है और यह अभी भी विभाग के नाम है। इसमें से लगभग 5 बीघा 14 बिस्वा ज़मीन आबादी देह की है जो कभी भी बेची नहीं जा

30.03.2026/1510/ए0एस0/ए0पी0-02

सकती। इसके बावजूद लगभग 100 करोड़ रुपये की कीमत वाली इस ज़मीन को केवल 4 करोड़ 60 लाख रुपये में दे दिया गया। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस पर जांच बिठाने का निर्णय लिया जाएग? धन्यवाद।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर आपने एक महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाया है। । hope the matter is not sub-judice, if it is not sub-judice the विधान सभा सचिवालय इस विषय को संबंधित विभाग के साथ उठाएगा और की गई कार्रवाई से आपको तथा माननीय सदन को सूचित करेगा।

30.03.2026/1510/ए0एस0/ए0पी0-03

दूरदराज़ क्षेत्रों में बंद पड़े बस रूटों को पुनः चालू करने एवं पुरानी बसों की मरम्मत की मांग"

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 13 बस रूट बंद पड़े हैं। जिनमें डलहौजी-भरमौर, भरमौर-तरेला, भरमौर-होली (वाया लामूहिलिंग), सुनारा-चम्बा, राड़ी-चम्बा, चम्बा-अरचू, चम्बा-मेहला, पालमपुर-कुगती, किलाड-चम्बा, किलाड-हलोर, किलाड-चसक शामिल हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे इन दूर-दराज के क्षेत्रों में गरीब लोग रहते हैं। लोगों के पास गाड़ियां नहीं हैं। बस रूट बंद होने के कारण लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उन रूटों को जल्द-से-जल्द सुचारू रूप से चलाया जाए। एक विषय फटाहर-चम्बा नयाग्रां बस का है। इस बस का एक वीडियो कल वायरल हो रहा था। जिसमें बस चालक छाता लेकर बस चला रहा था। मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार बस की स्थिति काफी खराब थी और बस को मरम्मत करवाने की जरूरत थी। परन्तु दुर्भाग्यवश विभाग ने ड्राइवर को तलब किया है और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह कमी विभाग के मैकेनिकल विंग की है, इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। मेरा आग्रह है कि कृपया ड्राइवर पर हुई कार्रवाई को निरस्त किया जाए और पुरानी बसों को जल्द-से-जल्द ठीक करवाया जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर आपने एक महत्वपूर्ण विषय आपने सदन के ध्यान में लाया है। हम विभाग से उपरोक्त विषय के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे और की गई कार्रवाई से आपको तथा माननीय सदन को अवगत करवा दिया जाएगा। अब अगला विषय माननीय सदस्य श्री राम कुमार चौधरी का है।

श्री राम कुमारः (अनुपस्थित)

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

30.03.2026/1515/AT/ AS /01

अध्यक्ष जारी....

अब माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी।

श्री मलेन्द्र राजनः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज बाज़ार में खाद्य पदार्थों में मिलावट और घटिया गुणवत्ता की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। आम आदमी रोज़मर्रा की खाने-पीने की चीज़ें खरीदता है लेकिन उसे यह भरोसा नहीं होता कि वह जो खा रहा है वह शुद्ध है या उसमें किसी प्रकार की मिलावट है। यह सीधे-सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है।

अक्सर देखा गया है कि संबंधित विभाग में स्टाफ की कमी रहती है। जिस प्रकार प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए विभिन्न विभागों को मौके पर जाकर चालान करने की शक्तियां दी गई हैं अध्यक्ष महोदय मैरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह रहेगा कि उसी प्रकार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अधिकृत किया जाए। ताकि मौके पर सैंपल लिए जा सकें और जहां-जहां खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट हो और वहां उस पर कार्रवाई की जा सके। यदि स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, नगर परिषद, रेवेन्यू और पुलिस जैसे विभिन्न विभागों को प्राथमिक जांच

और चालान की शक्तियां दी जाएं तो खाद्य पदार्थों में मिलावट पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त और प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए तथा अवैध खनन की तर्ज पर विभिन्न विभागों को जांच और चालान की शक्तियां देने पर गंभीरता से विचार किया जाए ताकि जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सकें और मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई हो सके। धन्यवाद।

30.03.2026/1515/AT/ AS /02

अध्यक्षः आपने एक महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है। माननीय सदन और विधान सभा सचिवालय इस विषय को संबंधित विभाग के साथ उठाएगा और की गई कार्रवाई से आपको और माननीय सदस्य को सूचित किया जाएगा। अब माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पांवटा विधान सभा क्षेत्र की एक समस्या उठाना चाहता हूं। हमारी ग्राम पंचायत डोगरी सालवाला में, 15 अगस्त 2025 की बरसात के दौरान गांव अंबीवाला में ऊपर से आई बाढ़ के कारण बहुत सारा मलबा नाले में आ गया है। यह मलबा नाले के बीच में जमा हो गया जिससे उसकी ऊंचाई बहुत बढ़ गई। इसके कारण पानी किनारों से बहने लगा और काफी भूमि कटाव हुआ। वहां एक ऐ0सी0 बस्ती है जहां दो-तीन घर भी क्षतिग्रस्त हुए और कुछ पशु भी पानी में बह गए।

मैंने इस विषय पर कई बार सरकार से बात की है लेकिन सरकार द्वारा चैनलाइजेशन के लिए धन की कमी बताई जाती है। अब फिर दो महीने बाद बरसात आने वाली है इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि उस मलबे को हटाने के लिए लोगों को अनुमति दी जाए।

यदि मलबा बीच से हटा दिया जाएगा तो नाला नीचे हो जाएगा और किनारे ऊंचे हो जाएंगे जिससे लोगों के घरों और जमीन का नुकसान नहीं होगा। अन्यथा भविष्य में पूरी

बस्ती बह सकती है। पहले ही दो-तीन घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और आगे और नुकसान हो सकता है। नाले के बीच में जमा मलबा 10-15 फुट तक ऊंचा हो गया है। इसलिए उसे हटाने की अनुमति दी जाए या संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाएं ताकि नाले को साफ करके पानी बीच से बह सके और किनारों की जमीन व घर सुरक्षित रह सकें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्षः निश्चित रूप से आपने एक महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाया है। हम संबंधित विभाग से कहेंगे कि इस विषय का शीघ्र संज्ञान लें और की गई कार्रवाई से विधान सभा और आपको सूचित करें। अब माननीय सदस्य श्री दीप राज जी।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....

30-03-2026/1520/केएस/डीसी/1

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री दीप राज जी अपना विषय उठाएंगे । Let us be very short and brief so that we can take up all the issues.

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक तीर्थस्थल आता है जो कि प्राचीनकाल से करसोग की पहचान रहा है। यहां से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर तत्तापानी स्थित है। मणिकर्ण के बाद हिमाचल प्रदेश में वह दूसरा स्थान है जहां पर गर्म पानी के स्त्रोत हैं और अभी से नहीं कई वर्षों से किन्नौर, रामपुर, सुन्दरनगर तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग तुलादान करवाने के लिए और मकर सक्रांति के समय पर तत्तापानी आते रहे हैं। लेकिन पिछले 10-15 साल से जब से वहां पर डैम बना है, उसके बाद ज्यादा सिल्ट इकट्ठी होने की वजह से जलस्तर ऊपर पहुंच गया है और जो लोग वहां विस्थापित हुए थे, उन्होंने उस स्थान को छोड़कर थोड़ा ऊपर घर बनाए थे लेकिन उनके घरों तथा डंगों में भी अब दरारें आ गई हैं। लोगों में भी रोष उत्पन्न हो गया है। मैं चाहूंगा कि जो सिल्ट भर चुकी है, उसको निकालने के लिए सदन एक नीति बनाने का विचार करे तथा नीति बनाते समय वहां के लैंडलूज़र का भी ध्यान रखा जाए क्योंकि अधिकतर लैंड लूजर्ज़ के घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर वाटर स्पोर्ट्स का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। जब टूरिस्ट शिमला की तरफ आता है तो मुझे नहीं लगता कि शिमला के आसपास कोई अन्य स्थान भी है जहां पर उसको वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा है। सिल्ट बढ़ने की वजह से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी वहां पर कम हो गई हैं। मेरा निवेदन है कि उस सिल्ट को निकाला जाए और उसका कुछ बजट उस क्षेत्र की डवलपमेंट के लिए लगाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने मुझे बताया था कि मेरे उस क्षेत्र में या उससे आगे के क्षेत्रों में मछली पालन के लिए जो बीज डाला जाता है वह भी कामयाब नहीं हो रहा है और सिल्ट की वजह से मछलियां मर रही हैं। उस सुविधा का भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। डैम की वजह से भारी सिल्ट इकट्ठा हो रही है तथा वहां के पुलों का भी और उस क्षेत्र का भी नुकसान हो रहा है। आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी भी वहां आए थे, एक-डेढ़ साल के बाद पुल का उद्घाटन करके गए। लोगों को बड़ी

30-03-2026/1520/केएस/डीसी/2

समस्याओं का सामना करना पड़ा और बस के रूट में भी दिक्कत आती है। तो जहां-जहां ऐसे स्थान हैं जहां पर डैम की वजह से सिल्ट इकट्ठा हो रही है, वहां पर इसके लिए कोई विशेष नीति बनाई जाए। इससे प्रदेश सरकार की आय भी बढ़ेगी । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : दीप राज जी, ज़ीरो आवर के माध्यम से आपने एक महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है और हमने इसका संज्ञान भी लिया है। विभाग से हम कहेंगे कि इसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से माननीय सदन और आपको हम अवगत करवा देंगे।

30-03-2026/1520/केएस/डीसी/3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी अपना विषय उठाएंगे।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं ज़ीरो आवर के माध्यम से सरकार के ध्यान में यह विषय लाना चाहता हूं कि मेरे सदर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपये से एक

सीवरेज ट्रीटमैंट प्लान बन रहा है जिसकी पूरे शहर में लाइन बिछ रही है। तीन वर्ष पहले इस कार्य हेतु पैसा सेंक्शन हुआ था और पिछले दो महीने से उसका कार्य चल रहा है लेकिन उस कार्य की गुणवत्ता बहुत ही पुअर है। दूसरे, बाहर का जो कांट्रेक्टर वह काम कर रहा है, जितनी टाइलें हमारे शहर के अंदर लगी थीं, वे जे0सी0बी0 से उखाड़ दी गई हैं। ना तो वहां मौके पर कोई सुपरवाइज़र है जब भी किसी से बात करें तो कोई कहता है कि कंसल्टेंसी एजेंसी देखेगी। जब आई0पी0एच0 विभाग से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि इसमें हमारी जिम्मेवारी बहुत कम है। तो वहां इतना बड़ा प्रोजैक्ट चल रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी के बारे में कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हम मानते हैं कि प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है लेकिन जो पैसा केंद्र से भी आया है और लग रहा है वह प्रॉपरली लग जाए क्योंकि बिलासपुर एन0बी0टी0 है, न्यू बिलासपुर टाउनशिप है और वर्ष 1960 के आसपास बना है। अब वह सारी सीवरेज व्यवस्था तहस-नहस हो गई है। इसलिए वहां के लिए जो नया प्रोजैक्ट सेंक्शन हुआ है वह प्रॉपर चले। अध्यक्ष महोदय, जब हमने डिपार्टमैंट से इस प्रोजैक्ट के बारे में बात की तो जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आया। पूरे शहर में डस्ट है। जहां से मन करता है, वहां से खोद देते हैं। जब हमने पता किया कि इस कम्पनी का ऑफिस कहां है, कौन लोग इस काम को कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कम्पनी का ऑफिस है वह पूर्व विधायक के घर में है। हमारे लोग वहां जा नहीं सकते । अब वे ही लोग काम कर रहे हैं और वहां पर क्वालिटी का इतना सत्यानाश हो रहा है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

30.03.2026/1525/av/dc/1

श्री त्रिलोक जम्वाल--------- जारी

जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां पर शहर के बीच में यह पैसा लग रहा है और पूरी सड़कें बीच से उखाड़ दी हैं। जब किसी सड़क की मैटलिंग हो रही होती है तो उसकी पहले सोलिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसको पैक करना चाहिए। लेकिन वहां पर केवल एक-एक इंच बजरी डालकर उसको बंद किया जा रहा है जोकि 15-20 दिनों में फिर से उखड़ जाएगी। इसलिए मेरा प्रदेश सरकार से आग्रह है कि जब इतने बड़े प्रोजैक्ट का कार्य हो

रहा है तो उसकी क्वालिटी चैक की जाए और वहां पर लगे स्थानीय ठेकेदारों पर भी लगाम कसी जाए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने निश्चित तौर पर सदन के ध्यान में सिवरेज के काम से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। उस सिवरेज स्कीम के अंतर्गत शहर के बीच सड़कों और गलियों को उखाड़ा गया होगा जिससे स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही होगी। माननीय सदन ने इसका संज्ञान लिया है और **हम चाहते हैं कि इसके बारे में निश्चित समयावधि के अंदर-अंदर कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से हम इस माननीय सदन सहित आपको भी सूचित करेंगे।**

30.03.2026/1525/av/dc/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्या श्रीमती कमलेश ठाकुर अपना विषय उठाएगी।

श्रीमती कमलेश ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे जीरो आवर में अपना विषय उठाने का मौका दिया।

पूर्व उद्योग मंत्री श्री बिक्रम सिंह के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हरिपुर में एक कॉलेज खोला गया था। लेकिन वह क्षेत्र कुछ ऐसा है जहां पर बच्चों को आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है। उस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 100 से घटकर 40-45 रह गई है और वर्तमान में वहां पर केवल एक प्रोफैसर काम कर रहे हैं। अभी सरकार ने संज्ञान लिया है कि जिस-जिस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम होगी उसको बंद किया जाएगा। वह कॉलेज ऐसी जगह बना है जोकि लगभग 25 पंचायतों को कवर करता है और मुझे लगता है कि यहां पर बैठे सभी माननीय विधायकों को यह जानकारी है क्योंकि देहरा विधान सभा क्षेत्र के उप-चुनाव के दौरान मुझे नहीं लगता कि इनमें से वहां कोई गया नहीं होगा। वहां की परिस्थिति के बारे में यहां बैठे सभी माननीय सदस्य जानते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस कॉलेज को बंद न किया जाए क्योंकि मैंने 4-5 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि हमारी सरकार ने वहां के लिए इस बजट में चार वर्षीय ऑनर एवं रिसर्च प्रोग्राम शुरु करने

की घोषणा की है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इसको कंसीडर किया जाए। वहां पर ज्यादा-से-ज्यादा बच्चे आएंगे जिससे हमारा वह शिक्षा संस्थान चलता रहेगा। वह माननीय श्री बिक्रम सिंह का एक ड्रीम प्रोजैक्ट था इसलिए वह कॉलेज चलते रहना चाहिए। उस कॉलेज की बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी बनी है। उसका केवल यह ड्रॉ बैक है कि वह एक इंटीरियर इलाके में खुला है और वहां आने-जाने की दिक्कत है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने निश्चित तौर पर माननीय सदन के ध्यान में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लाया है। **हम इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सरकार व संबंधित विभाग को लिखेंगे तथा की गई कार्रवाई से माननीय सदन व आपको सूचित किया जाएगा।**

30.03.2026/1525/av/dc/3

अध्यक्ष जारी----

अब केवल दो विषय बचे हैं इसलिए हम इसको जल्दी-जल्दी कर लें। The issues of Hon'ble Members Sh. Bhawani Singh Pathania and Sh. Sanjay Awasthy ji are left. I can give relaxation of five minutes. अब माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया अपना विषय उठाएंगे।

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा बहुत छोटा-सा मैटर है और मेरे हिसाब से यह हम सभी को टच करता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो डिवीजन्ज का गठन हुआ है वह चाहे जल शक्ति विभाग या लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत हुआ है या फिर हमारे नये पुलिस थाने बने हैं। अगर मैं अपने फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरी 52 में से 51 पंचायतें एक डिवीजन के अंडर हैं तथा एक पंचायत किसी दूसरी डिवीजन के अंडर है और यह हाल जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग और पुलिस थानों यानी सबका है। अगर मैं पुलिस थानों की बात करूं तो मेरी चार पंचायतें ज्वाली पुलिस थाना के अंडर हैं तथा एक पंचायत नूरपुर पुलिस थाना के अंडर है जिसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होती है।

अगर किसी को वेरीफिकेशन के लिए जाना होता है तो वह पंचायत से उठकर नूरपुर जाएगा जबकि

टी सी द्वारा जारी

30.03.2026/1530/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री भवानी सिंह पठानिया.... जारी

उसके अन्य सभी कार्य फतेहपुर में होते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इनकी रि-एलाइनमैंट की जाए। Instead of we, having to do the paper work, अगर इसकी इंस्ट्रक्शन चली जाए कि भौगोलिक आधार पर एक विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2-2 या 3-3 गांव जो किसी और डिवीजन में पड़ रहे हैं उनकी एलाइनमैंट करके एक ही विधान सभा क्षेत्र में समायोजित कर दिया जाए तो इससे प्रशासनिक सुविधा भी बढ़ेगी और लोगों को भी राहत मिलेगी।

Speaker : Definitely, a very important issue has been raised in the House by the Hon'ble Member. This is regarding the reorganization of the divisions, PWD, Electricity Board & the Jal Shakti Vibhag, wherein the area of whole constitution is to be put under the jurisdiction of a single division. This is an important issue. The Vidhan Sabha has taken a cognizance of this issue and we will be writing to the Government to take necessary steps in this behalf. Whatever the action will be taken, the Vidhan Sabha Secretariat will be informed and further we will inform the Hon'ble Member accordingly. Thank you.

30.03.2026/1530/टी0सी0वी0/एच0के0-2

प्रदेश की संपदा और रेवेन्यू से जुड़ा विषय

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरा विषय प्रदेश की संपदा और प्रदेश के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है। पिछली सरकार के समय, जब नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री थे, सांस्कृतिक केंद्र परियोजना के आधार पर एक भूमि आबंटित की गई थी। यह भूमि मैसर्ज माया नगरी, हिमाचल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर आबंटित की गई थी और इस आबंटन में अनियमितताएं बरती गई थीं। जिस आधार पर यह आबंटन किया गया था उस समय भी इस पर आपत्तियां उठाई गई थीं। कई लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। वर्तमान समय में इस संपत्ति का मूल्य लगभग 300 करोड़ रुपये के करीब है। लगभग 5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इस अवधि में संबंधित पक्ष को प्रति वर्ष 1.5 करोड़ रुपये सरकार को देने थे लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग 2.5 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है और संबंधित पक्ष भूमि पर कब्जा करके बैठा हुआ है। जब यह भूमि आबंटित की गई थी उस समय विधिक सलाह भी नहीं ली गई थी या यदि ली गई थी तो उसका पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त एच0पी0टीडी0सी0 बोर्ड की बैठक में भी इस विषय का संज्ञान लिया गया था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी।

मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का यह प्रयोजन है कि हम प्रदेश की संपदा को न तो लुटने देंगे और न ही लुटाएंगे। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह संपत्ति जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये है, वह सरकार को वापिस आए और जो रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होना है वह वसूल किया जाए। इसके साथ ही जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार को नुकसान हुआ है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर यह एक गंभीर विषय माननीय सदस्य द्वारा माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है। माननीय मंत्री जी इस विषय में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात रखें।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में शून्यकाल के दौरान उठाया है। **इसकी गंभीरता को देखते हुए इस विषय में एक जांच बैठाई जाएगी और यदि इसमें कोई भ्रष्टाचार या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।**

30.03.2026/1530/टी0सी0वी0/एच0के0-3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री इन्द्र सिंह जी, कृपया संक्षेप में अपना विषय रखें।

नगर निगम क्षेत्र को पंचायतों में शामिल करने बारे।

इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय नगर निगम मण्डी के अधीन बैहना जो वार्ड नंबर 14 और धौंदी वार्ड नम्बर 15 से संबंधित है। ये क्षेत्र वर्तमान में नगर निगम के अंतर्गत आते हैं लेकिन स्थानीय लोग चाहते हैं कि इन्हें पंचायत में शामिल किया जाए।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

30-3-2026/1535/NS-HK/1

श्री इन्द्र सिंह-----जारी

मण्डी में हम मुख्य मंत्री जी से इस मामले के बारे में मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन ग्रामीण क्षेत्रों को हम पंचायत में लेंगे और जो शहर के साथ लगता एरिया है उसको हम नगर परिषद् या नगर निगम में लेंगे। मेरा मुख्य मंत्री जी व मंत्री जी से निवेदन है कि वार्ड नम्बरः 9 डडौर को पंचायत में शामिल किया जाए और बैहना व धौंदी को भी पंचायत में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर माननीय सदस्य ने एक गंभीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है which is regarding the exclusion of some areas from the Nagar Panchayat to the Panchayats. I think the Government will take a cognizance of this issue and will definitely take an action. Since the matter has also been represented to the Hon'ble Chief Minister, I hope the Government will take necessary actions/steps in this behalf. Whatever action will be taken by the Government, the Vidhan Sabha Secretariat will be informed accordingly and we will inform the Hon'ble Member about the action taken too. Thank you very much.

Now all the issues under Zero Hour are over. Now, I will take up the next item. ...(व्यवधान) आपका क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। वे तो आज ऐजीटेशन कर रहे हैं। एक मिनट, प्लीज बैठ जाएं। आज बजट पास होगा और गिलोटिन लगेगा इसलिए आज बहुत कार्यसूची है। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, इसके बारे में आप ही स्पष्ट कर दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वे मेरे पास मिलने के लिए आ गए हैं और बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार ने आश्वासन दे दिया है।

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अब मुख्य मंत्री जी, सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

30-3-2026/1535/NS-HK/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो कि इस प्रकार हैः-

सोमवार, 30 /मार्च, 2026	1.शासकीय/विधायी कार्य । 2.बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2026-27 (i) मांगों पर चर्चा एवं मतदान। (ii) विनियोग विधेयक-पुरःस्थापना, विचार-विमर्श-एवं परण।
मंगलवार, 31 /मार्च, 2026	1.शासकीय/विधायी कार्य । 2.गैर सरकारी सदस्य दिवस सामान्य चर्चा।
बुधवार, 01 /अप्रैल, 2026	शासकीय/विधायी कार्य।
वीरवार, 02/ अप्रैल, 2026	शासकीय/विधायी कार्य।

30-3-2026/1535/NS-HK/3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 (वित्त लेखे खण्ड-I एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए (अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार।

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण का वार्षिक प्रतिवेदन, 2024-25;

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2024, जोकि अधिसूचना संख्याः पीसीएच-एचए(1)19/2008-III-1073-1229-लूज, दिनांक द्वारा

23.01.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 28.01.2025 को प्रकाशित;

30-3-2026/1535/NS-HK/4

(iii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2025, जोकि अधिसूचना संख्याः पीसीएच-एचए(1)18/2008-लूज-II-1790-1992, दिनांक द्वारा 11.02.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 15.02.2025 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025, जोकि अधिसूचना संख्याः पीसीएच-ए(1)18/2008 -III-23660-23862, दिनांक द्वारा 14.08.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 18.08.2025 को प्रकाशित; और

(v) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 की उपधारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2026, जोकि अधिसूचना संख्याः पीसीएच-एचए(1)18/2008-III-14731-923, दिनांक द्वारा 21.03.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 23.03.2026 को प्रकाशित।

30-3-2026/1535/NS-HK/5

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की एक- एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कल्याण समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का **48वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्याः 32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;
2. समिति का **49वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्याः 19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और
3. समिति का **50वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्याः 31-जनजातीय विकास विभाग** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

अध्यक्ष : अब श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन कल्याण समिति, जन कल्याण समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगेः-

30-3-2026/1535/NS-HK/6

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, **जन प्रशासन समिति**, (**वर्ष 2025-26**), समिति का **17वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्याः 5-भू-राजस्व व जिला प्रशासन विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित तथा **राजस्व विभाग** से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री संजय अवस्थी, सभापति, मानव विकास समिति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक- एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

30-3-2026/1535/NS-HK/5

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, मानव विकास समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(1) समिति का **34वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्याः 8**-शिक्षा के अन्तर्गत उच्चतर **शिक्षा विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(2) समिति का **35वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्याः 9**-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **आयुष विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

अध्यक्ष : अब श्री केवल सिंह पठानिया, सभापति, सामान्य विकास समिति, सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक- एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

30-3-2026/1535/NS-HK/7

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, सामान्य विकास समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
2. समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्याः 28-नगर एवं ग्राम योजना विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि
मांग संख्याः 10-लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

अध्यक्ष : अब श्री सुख राम चौधरी, सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदनों की एक- एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुख राम चौधरी (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, ग्रामीण नियोजन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का **16वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्याः16** के अन्तर्गत वन और वन्य जीवन विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित **षष्टम् मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

2. समिति का **17वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग** की गतिविधियों/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है;

3. 30-3-2026/1535/NS-HK/8

3. समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्याः 11-कृषि विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

4. समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्याः 14-पशुपालन विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

विधायी कार्य आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

30.03.2026/1540/RKS/YK-1

विधायी कार्य
सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरः स्थापति करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3)को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरः स्थापति करेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3) पुरः स्थापित हुआ।

30.03.2026/1540/RKS/YK-2

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरः स्थापति करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मन्त्री भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरः स्थापति करेंगे।

राजस्व मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) पुरः स्थापित हुआ।

30.03.2026/1540/RKS/YK-3

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान
वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान और पारण होगा। क्योंकि आज चर्चा का अंतिम दिन है इसलिए आज ही विनियोग विधेयक की पुरःस्थापना तथा इस पर विचार-विमर्श एवं पारण भी होगा। सत्तापक्ष व विपक्ष की सहमति के अनुरूप मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम 196-7 के अंतर्गत आज सायं 6.00 बजे गिलोटिन लगा दिया जाएगा। अतः सभी माननीय सदस्यों से मेरा पुनः निवेदन है कि वे कम-से-कम समय में अपनी बात रखें। अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनांक 27.03.2026 को प्रस्तुत मांग संख्याः 9 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर हुई चर्चा का उत्तर क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इंटरवेंशन कर दी है। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी अपना जवाब पूरा करना चाहते हैं इसलिए मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी बात रखें। ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर जी क्या हुआ? ...(व्यवधान) ठाकुर साहब, मैंने आपको बोलने के लिए अलाउ नहीं किया है। ...(व्यवधान)

श्री बी0एस0द्वारा जारी

30.03.2025/1545/बी.एस./वाई.के.-1

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आदरणीय ठाकुर साहब अभी तो मैंने आपको बोलने के लिए अनुमति ही नहीं दी है। ...(व्यवधान)...

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री इससे पहले 25 मिनट तक इस विषय पर बोल चुके हैं और अभी और बोलना चाह रहे हैं।

Speaker : If he wants to supplement the quarries raised by all of you(Hon'ble Member of Opposition) then he can as he is the Leader of the House. He has a privilege. ...(Interruption). Please ठाकुर साहब, कृपया, ऐसी छोटी-छोटी बातों पर मत उठ जाया कीजिए। He is the Leader of the House and he has every right and prerogative to intervene at the relevant stages wherever it is required in the House. माननीय मुख्य मंत्री महोदय। ...(Interruption). I have not allowed Shri Jai Ram Thakur Ji. ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के नाते भी कह रहा हूं,

Speaker : Please, please he is a Medical Education Minister ...(व्यवधान) ऐसा है कि मेडिकल एजुकेशन के इनचार्ज ये हैं। ...(व्यवधान)... ठाकुर साहब, कृपया बैठ जाइए। जब मुख्य मंत्री जी के पास मेडिकल एजुकेशन विभाग है तो उससे संबंधित ही बोल रहे हैं। ज्यादातर जो इश्यू आपने रेज किए हैं those issues pertain to the Medical Education rather than to the Health & Family Welfare Department. मुख्य मंत्री महोदय without taking a note of anybody you just submit whatever you want to submit.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कुछेक चीजें जो विपक्ष के द्वारा रेज की गई है मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं सभा पटल पर तथ्य रखूं और अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर जी बार-बार यह कह रहे हैं कि मैंने 25 मिनट बोला। मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं बोलने उठा था तब सिर्फ 10-12 मिनट थे आप देख सकते हैं।

30.03.2025/1545/बी.एस./वाई.के.-2

श्री विपिन सिंह परमार : मुख्य मंत्री जी आप 18 मिनट बोले हैं।

मुख्य मंत्री : 18 मिनट बोला होगा, मुझे मालूम नहीं। ...(व्यवधान)।

Speaker : It is not a debate and not even discussion on this issue. I have allowed it and I am further allowing it.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। जब कुछ किया न हो और हम फेक्ट्स रखेंगे तो तकलीफ निश्चित है, होगी। (***)मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था, भविष्य में क्या पता कि गर्भ में क्या छुपा है और मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष के नेता बार-बार उठकर कहते हैं कि बोलने नहीं दिया गया जबकि वे हर बात में बोलते हैं। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मैंने उन्हें पहले भी सलाह दी है इस उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब मुख्य मंत्री रहे हों तो वैसे भी तनाव रहता है और उसके बाद विपक्ष के नेता बनें तो पांच गुटों का तनाव और रहता है और टेंशन रहती।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, कृपया आप विषय पर बोलें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जवाब दिया। ...(व्यवधान)...

Speaker: Take it in a lighter way Hon'ble Member Shri Randhir Sharma Ji. ...(Interruption). मुख्य मंत्री जी।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

30.03.2025/1545/बी.एस./वाई.के.-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब वे राजनीतिक बात करते हैं तब मैं करता हूं। वैसे मैं उनका बहुत आदर करता हूं यह सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, हमने 5 एम0आर0आई0 मशीनें खरीदी हैं। एक मशीन नेरचौक पहुंच चुकी है, एक हमीरपुर में पहुंच चुकी है और जल्दी ही टांडा तथा चमियाना में भी लगाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय विपिन सिंह परमार जी की बात का स्पष्टीकरण देने के लिए भी खड़ा हुआ हूं। आपने रोबोटिक सर्जरी की बात की थी। उसमें मंत्रा का मुद्दा आया है। बात को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न भी लगा हुआ था, वह प्रश्न चला गया इसलिए उसका उत्तर भी आज दे दूंगा। हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन द्वारा

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

30.03.2026/1550/डीटी/एएस-1

मुख्य मंत्री जारी....

डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने दिनांक 18.07.2023 को रिबोटिक सर्जरी की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु एक ई- निविदा आमंत्रित की जिसमें दो बोलीदाताओं ने भाग लिया। निविदा प्रस्तुत करने की तिथियां को दो बार बढ़ाया गया। तत्पश्चात् प्रक्रिया को निविदा हेतु 15-09-2023 को सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई। दिनांक 25.09.2023 को दूसरी ई-निविदा जारी की गई जिसमें पुनः उन्हीं दो फर्मों से बोलियां प्राप्त हुई। हिमाचल प्रदेश के जो स्टोर क्रय नियम 2013 के नियम 19 (4) के अंतर्गत सरकार की स्वीकृति के उपरांत तकनीकी बोली की प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा तकनीकी समिति द्वारा मार्च, 2024 में विक्रेता स्थलों पर उपकरणों का निरीक्षण किया गया क्योंकि केवल एक फर्म तकनीक रूप में योग्य पाई गई। अतः सरकार द्वारा दोबारा से इसका टेंडर कॉल किया गया। दिनांक 17.08.2024 को तीसरी ई- निविदा जारी की गई। तीसरी बार दोबार टेंडर कॉल किए गए

जिसमें पुनः उन्हीं दो फर्मों ने भाग लिया। तकनीकी समिति द्वारा दिसंबर, 2000 में रोबोटिक प्रणाली के लाइव प्रदर्शन का निरीक्षण किया गया। मूल्यांकन के आधार पर एक फर्म तकनीकी रूप से योग्य पाई गई। स्टोर क्रय नियम 2013 के नियम 19 (5) के अंतर्गत शासन की स्वीकृति के पश्चात् तकनीकी रूप से योग्य फर्म की वित्तीय बोली 31.12.2024 को खोली गई। जनवरी, 2025 में मूल्य वार्ता की गई तथा कीमतों की तुलना, एम्स दिल्ली तथा आर.सी.सी. तिरुवंतपुरम जैसे प्रमुख स्थानों से की गई। उन्हीं की क्वालिटी, उन्हीं की स्पेसिफिकेशन के आधार पर यह तुलना की गई। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में सी.एम.पी. 19.11.2025 तथा सी0डब्ल्यू0सी01676 में न्याय याचिका दायर की गई। दोनों ही मामलों में हाईकोर्ट ने विभाग के पक्ष में निर्णय देते हुए याचिका निरस्त कर दी। माननीय न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि यह अभिलेखित करना उचित है कि चिकित्सा संस्थानों में स्थापित किए जाने वाले उपकरणों की सुविधा एवं गुणवत्ता के संबंध में निर्णय लेना सरकार अथवा उसके विशेषज्ञों का अधिकार क्षेत्र है तथा रोगियों को शिक्षा उपचार प्रदान किया जा सके।

30.03.2026/1550/डीटी/एएस-2

जब इस तकनीकी फाइनेंस बिड को खोला गया, मैंने उसके आधार पर कहा कि एम्स में कोई चेंजिज तो नहीं आई है। जब उनकी कमेटी से बात की गई और पाया गया कि दा विंसी रिपोर्टिंग सर्जरी की मूल खरीद 16.22 करोड़ रुपये थी। जो कि जी0एस0टी0 मिलाकर 18.17 करोड़ रुपये हो गई। फिर उनके सी.एम.सी. 4.56 करोड रुपये थी। असेसरी से मूल कीमत बढ़ाकर 21.91 करोड़ रुपये थी जोकि 2.91 करोड़ जी .एस.टी. मिलाकर 24. 73 करोड़ रुपये हो गई। एम्स दिल्ली क्योंकि सी.एस.सी. एम्स दिल्ली में भी 5 साल के लिए थी। लेकिन हमने स्पेसिफिकेशन एम्स दिल्ली की रखी है। हिमाचल प्रदेश में मैंने यह दिशा निर्देश दिए हैं कि एम्स दिल्ली में जो भी स्पेसिफिकेशन होगी, जो भी क्वालिटी होगी, जो भी मशीन उस रेट पर खरीदी जाएगी उसके आधार पर हम यहां टेंडर करेंगे या उसी को हम ऑर्डर दे देंगे। मैंने तो यह भी कहा है कि जो एम्स दिल्ली खरीदेगा उसी के आधार पर हम टेंडर दे देंगे। क्योंकि क्वालिटी मशीने खरीदने में काफी समय

लगता है। एम्स दिल्ली में यही मशीनरी थी। ये सब चीजें टेक्निकल है। उसके बाद एम्स दिल्ली में वह मशीन सेम क्वालिटी, सेम स्पेसिफिकेशन , सेम असैसरीज, सेम सी.एम.सी. के साथ 25.91 करोड़ रुपये में खरीदी गई। हमारी कीमत 24.78 करोड़ रुपये है जोकि 1.20 करोड़ रुपये एम्स दिल्ली से कम है। माननीय जय राम ठाकुर जी मशीन खरीदने की बात कर रहे थे। हमने भारत सरकार के उपक्रम द्वारा हाइट वाली 5 मशीनें खरीदनें के ऑर्डर दिए हैं जिसमें 3 खरीद ली गई है। ...(व्यवधान) आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने दो मशीनों को खरीदने के लिए टेंडर किया था। हमने उस टेंडर में लिखा था कि बाद में इसकी वेरिएशन हो सकती है और दो की जगह पांच भी ले सकते हैं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

30.03.2026/1555/ए.एस.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री..... जारी

हमने तीन और रोबोटिक सर्जरी की मशीन के टेंडर करने के ऑर्डर दिए हैं।...(व्यवधान) आप सुन लीजिए। हमने तीन और टेण्डर के ऑर्डर दिए क्योंकि हरेक टेण्डर में कंडीशन थी कि हम दो की जगह एक भी ले सकते हैं और दो की जगह पांच भी ले सकते हैं।...(व्यवधान) बैठ जाइए, पहले सुन लीजिए।...(व्यवधान) बैठ तो जाइए...(व्यवधान) बैठ तो जाइए। आप मुझे बोलने दीजिए।

Speaker : Let the Hon'ble Chief Minister Complete.

मुख्य मंत्री : यह पता नहीं आपको कहां से हो गया कि आपको बोलने का मौका नहीं देते और आप सुनते भी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने उनको बोला कि हमने दो जगह मशीन खरीदनी है। उन्होंने मुझे कहा कि 31 मार्च के बाद इसका रेट अलग है। मैंने पूछा कितना है? अभी ये सारी चीजें जो एम्ज़ और हमारे यहां स्पेसिफिकेशन से खरीदी गई हैं। मैं श्री जय राम ठाकुर जी से कहना चाहूंगा कि हमने तो

बुद्धिमता दिखाई कि हमने उनसे तीन मशीनें रोबोटिक सर्जरी की उसी कीमत पर खरीदी। आज वे उस मशीन को 30 करोड़ रुपये में भी देने को तैयार नहीं हैं। जिस कारण हमें दोबारा टेण्डर करना पड़ रहा है। मैंने कल भी उनसे बात की है। यह जो Da Vinci मशीन है, यह दुनिया की सबसे अच्छी मशीन है। इसे हमने रोबोटिक सर्जरी के लिए इसलिए खरीदा है ताकि मरीजों का अच्छा इलाज हो सके। मेरा खुद रोबोटिक सर्जरी से इलाज हुआ है और मैं उस समय विधायक था। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी चीज खरीदी गई है, ट्रांसपेरेंट तरीके से खरीदी गई है। जहां तक मैडिकल कॉलेज की बात है, मैं विपक्ष के नेता को यह भी बताना चाहता हूं कि जो बाकी मशीनें खरीदी गई हैं, वह दिल्ली की HITE के तहत हमने ऑर्डर दिए हैं।

30.03.2026/1555/ए.एस.-एन.जी./2

पैट स्कैन की मशीन भी **HITE** के तहत ही ली गई है। मैंने कहा कि अभी हमने उनका स्पेसिफिकेशन देख लिया है, आप दोबारा टेण्डर करो ताकि सरकार के खजाने पर ज्यादा दबाव न पड़े।

अध्यक्ष महोदय, हमने क्या-क्या किया और पूर्व सरकार ने क्या-क्या किया, यह मैं बताना चाहता हूं। हमने अभी आई0जी0एम0सी0 के ब्वॉयज़ एण्ड गर्ल्स हॉस्टल के लिए 50 हजार 54 करोड़ रुपये दिए हैं। पैट स्कैन की एक मशीन इंस्टॉल हो गई है और दूसरी हम टांडा में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आपके समय में क्या हुआ? आपने डायग्नोसिस की मशीन नहीं लगाई, आपने इलाज के लिए लिनियर एक्सीलरेटर लगा दिया। अगर आप पहले पैट स्कैन लगाते और उसके बाद लिनियर एक्सीलरेटर लगाते तो और अच्छा होता। हमने वह भी किया। आज ही मैंने एक और फैसला किया कि पी0जी0 की सीटें बढ़ाने के लिए चारों मैडिकल कॉलेज का डी0एम0ई0 कैडर बना दिया है। चाहे वह नेरचौक हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे चम्बा हो और चाहे नाहन हो। इन चारों का हमने आज नोटिफिकेशन करके डी0एम0ई0 कैडर बना दिया। यह भी सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।

अध्यक्ष महोदय, हमने 125 पोस्टें फैकल्टी की क्रिएट की हैं। सैप्रेशन और पैरामेडिकल के बारे में मैंने पूर्व में बता दिया है। हम जायका के माध्यम से मैडिकल कॉलेज में नई टेक्नोलॉजी लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन हमने कहा कि 10-10 साल व 15-15 साल पुरानी एक्स-रे मशीनें हैं। हमारे पास डॉक्टर्स बैस्ट हैं। आई0जी0एम0सी0, टांडा और हिमाचल का कोई भी डॉक्टर बाहर जाता है या जहां भी जाते हैं तो बेस्ट डॉक्टर बन जाता है। लेकिन जब उनके पास यहां पर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वे कैसे काम करेंगे? हमारे जो जोनल हॉस्पिटल हैं, वहां पर 10-10, 12-12, 15-15 साल पुरानी एक्स-रे मशीनें हैं। एम0आर0आई0 मशीन तो दूर की बात है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं है।

30.03.2026/1555/ए.एस.-एन.जी./3

हम डोनेशन के माध्यम से मशीनें ले रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि पहले फेज में हम मैडिकल कॉलेज को मजबूत करेंगे। आने वाले समय में इसमें सुधार की जरूरत है। सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन अगर हम आम नागरिकों को अच्छी सुविधा नहीं दे पाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हम हर जगह आई0सी0यू0 के 40 बेड क्रिएट करने जा रहे हैं ताकि जब कोई मरीज क्रिटिकल स्थिति में आए तो उसे तुरंत आई0सी0यू0 बेड मिल सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चार मैडिकल कॉलेज अभी ढ़ंग से नहीं चल रहे हैं। बेशक हम मशीनें खरीदते रहें लेकिन जब तक हम पैरामेडिकल स्टाफ नहीं भरेंगे, सहायक प्रोफेसर की पोस्टें क्रिएट नहीं करेंगे, पी0जी0 की क्लासिस शुरू नहीं करवाएंगे, एस0आर0 शिप की क्लासेस शुरू नहीं करवाएंगे, जब हम यह सब शुरू करवाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इनकी ऊना में में ई0सी0आई0

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

30.03.2026/1600/डी0सी0/ए0पी0-01

मुख्य मंत्री जारी .....

ऊना में पी0जी0आई0 के सैटेलाइट सेंटर के लिए ई0सी0आई0 नहीं हुई थी। हमारी सरकार आई माननीय श्री सतपाल सत्ती जी ने माननीय सदन में बात उठाई और मैंने खुद पर्सनली उसकी ई0सी0आई0 करवाई, तब जाकर के ऊना में पी0जी0आई0 सैटेलाइट सेंटर का काम शुरू हुआ। हम लोग मेडिकल हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में लगभग तीन हजार करोड़ रुपये जाइका के माध्यम से खर्च करने जा रहे हैं। आप तो पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं। आपको पता है कि 16वें वित्त आयोग द्वारा ही सात-से-आठ हजार करोड़ रुपये ई0ए0पी0 ग्रांट में मिलेगा। आपके समय क्या हुआ, मैं बताना चाहता हूं, लेकिन आप गुस्सा कर जाते हैं,गुस्सा मत कीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट लगवाए, जिनका हमें फायदा नहीं हुआ। जबकि हमें हेल्थ और एजुकेशन में फायदा देना है। आज हम हेल्थ के मामले में धीरे-धीरे सुधार करके आगे बढ़ेंगे। चम्बा को हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया, बिल्डिंग बना दी, लेकिन वहां अभी तक पी0जी0 नहीं है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी पी0जी0 नहीं है। कम-से-कम कुछ कोर्सेज में पी0जी0 शुरू की जाए ताकि हमें सही मायने में पता लगे। आप इस विषय पर कटौती प्रस्ताव लाए, जबकि आपको तो इस विषय पर समर्थन प्रस्ताव लाना चाहिए था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं मानता हूं कि साढ़े तीन साल में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इतना तो आप बोल सकते थे। अध्यक्ष महोदय, अगर में ऑटोमेटिक लैब की बात करूं। मैं एक दिन एम्स में चेक करवाने गया था और वहां एक दिन के लिए एडमिट हुआ। यह बात करीब तीन-चार महीने पहले की है। वहां मैंने ऑटोमेटेड लैब देखी, वहां पर लगभग 25 करोड़ रुपये की लैब कंपनी द्वारा लगाई गई है। जिसमें चार हजार के करीब टेस्ट लगातार होते हैं और हर प्रकार के टेस्ट होते हैं। हमने भी कहा है कि इस तरह की लैब के लिए पैसे की कमी नहीं रखी जाएगी। 25-25 करोड़ के हिसाब से 75 करोड़ रुपये चमियाणा, टांडा और एम्स के लिए रखे गए हैं। आगे नेरचौक, चंबा और नाहन में भी देंगे। आपने कहा कि

तीन के ऑर्डर क्यों दिए, दो के नहीं, इसलिए दिए कि वैरिएशन देखना पड़ेगा। यह सब एक स्ट्रैटेजी के तहत किया

30.03.2026/1600/डी0सी0/ए0पी0-02

जा रहा है कि जेब में कितने पैसे हैं और कितने नहीं, उसी हिसाब से टेंडर लगाए जाते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैंने सिविल सप्लाई की दुकानों में कौन सी दवाइयां बिकती हैं, इस पर मीटिंग ली और कहा कि क्वालिटी मेडिसिन लाई जाए। उदाहरण के तौर पर, जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने लंदन गया था तो वहां मैं तीन पेरासिटामॉल ली और ठीक हो गया। जबकि यहां सात-आठ लेने पर भी ठीक नहीं होता। एंटीबायोटिक और एंटीएलर्जी दवाइयों की भी यही स्थिति है और उनकी कॉस्ट भी ज्यादा है। इसलिए हमने मीटिंग में निर्देश दिए कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की मेडिसिन, जिसे कैबिनेट में पास किया गया है उसे ही स्टॉक में रखा जाए, ताकि लोगों को अच्छी दवाइयां मिलें। मैंने चमियाणा में एम0आर0 (मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव) की एंट्री बंद की क्योंकि वे पूरे दिन मेडिकल कॉलेज में बैठे रहते थे। अब उनके लिए एक दिन फिक्स किया जाएगा ताकि उसी दिन एम0आर0 वहां जाएं। हर प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। टेक्नोलॉजी में भी और पैरामेडिकल स्टाफ में भी हमने बदलाव किया है। पिछले 23 सालों में मेडिकल कॉलेजों से कम लोग निकल रहे थे, आप 18-18 ओ0टी0 (ऑपरेशन थिएटर) लोगों को निकाल रहे थे। अनेस्थेसिया के 18 लोग निकाल रहे थे। लेकिन हमने आई0जी0एम0सी0 और टांडा में संख्या बढ़ाकर 50 कर दी है, क्योंकि वहां पर इन्फ्रास्ट्रकचर है। वर्ष 2028 तक 50 रेडियोग्राफर निकलेंगे और प्रदेश में उनकी भी कमी नहीं रहेगी। पहले आउटसोर्स रेडियोग्राफरों को 13 हजार रुपये मिलते थे। जिसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है ताकि वे नौकरी न छोड़ें। इसी तरह अन्य स्टाफ का वेतन भी 25 हजार तक बढ़ाया गया है। एस0आर0 शिप ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनलों ...(व्यवधान)

Speaker: No disturbance please.

मुख्य मंत्री : मेडिकल कॉलेज में एन0एच0एम0 का पैसा नहीं आया। ...(व्यवधान) मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूa। एन0एच0एम0 की बात माननीय कर्नल धनीराम

शांडिल जी करेंगे, जो हेल्थ देख रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में एस0आर0 शिप 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख 30 हजारी की गई। No, it is not from National Health Mission(NHM) . आपको बता रहा हूं में एन0एच0एम0 का

30.03.2026/1600/डी0सी0/ए0पी0-03

पैसा अलग आ रहा है। हमारी सरकार में पैरामेडिकल स्टाफ को भी अलग किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में 900 स्टाफ नर्सेज की भर्ती हो रही हैं, पैरा मेडिकल के 176 ओ0टी0ए0 स्टाफ की भर्ती हो रही है और लगभग

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

30.03.2026/1605/AT/DC /01

मुख्य मंत्री जारी...

साढ़े तीन सौ डॉक्टरों की भर्ती हो चुकी है और अभी 236 डॉक्टरों की भर्ती का रिजल्ट मई-जून तक आ जाएगा। इसके बाद कहीं भी पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। हमारा आरोग्य स्वास्थ्य संस्थान का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है वहां स्पेशलिस्ट लगाए जा रहे हैं।

दूसरी बात, एसआरशिप पहले 50-50 प्रतिशत होती थी 50 प्रतिशत आउटसाइडर और 50 प्रतिशत इनसाइडर। हमने इसे बढ़ाकर हिमाचल के लोगों को ज्यादा लाभ देने के लिए 55 से बढ़ाकर 66 प्रतिशत कर दिया ताकि वे नौकरियां छोड़कर न जाएं। यह सुधार हमने किए हैं।

मैं यह आपको भी कहना चाहता हूं कि अभी भी मेडिकल कॉलेजों में चाहे आईजीएमसी हो या टांडा मेडिकल कॉलेज हो उनमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा नेरचौक, हमीरपुर, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेज में भी तेजी से सुधार करने की जरूरत है। अगर हम अपने स्थापित मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी और टांडा

को हम ठीक कर लेते हैं तो स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी और बाकी जगहों पर भी सुधार के लिए हम आगे बढ़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रोबोटिक सर्जरी और कैथ लैब की बात करें तो हमने कैथ लैब दी है। लेकिन कई बार हमसे भी गलती हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, हमने हमीरपुर में कैथ लैब दे दी, लेकिन वहां कार्डियोलॉजी विभाग ही नहीं था और न ही कार्डियक डॉक्टर था। बाद में हमने उसके लिए पोस्ट क्रिएट की। इसलिए हमने तय किया है कि जहां भी हमने कैथ लैब दी जाएगी, वहां कार्डियोलॉजी विभाग भी बनाया जाएगा। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कैथ लैब के लिए भी हमने पर्याप्त पैसा दिया है। हमारे पास पैसे की कोई आर्धीक कमी नहीं है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई कमी नहीं है लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी है, जहां सैलरी और अन्य खर्चों में दिक्कत आती

30.03.2026/1605/AT/DC /02

है। हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में हमारी सरकार बेहतरीन संस्थान बनाएगी और हेल्थ टूरिज्म को भी शुरू करेगी।....(व्यवधान) आप सुधार देखिए। आपने डेढ़ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट में भी प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया। माननीय अध्यक्ष महादय, अगर हमारा बजट कम हुआ है तो यह साबित कर दीजिए कि हमने टेक्नोलॉजी और रिफॉर्म के माध्यम से व्यवस्था में सुधार नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ....(व्यवधान) यह सब इन्होंने बोला है आप मान जाओ रणधीर जी....(व्यवधान)माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान) अभी तो 20 मिनट ही हुए हैं....(व्यवधान) अच्छे के लिए तो सुन लिया करें...

Speaker: Please let the Hon'ble Chief Minister complete his reply.

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) हमने पीजी की 275 सीटें क्रिएट की हैं। पिछले 40 वर्षों में क्या 275 सीटें बनी थीं? हमारे एक साल में ही 275 सीटें बनी हैं।....(व्यवधान) आप ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। आपने गलत प्रस्ताव लाया था। मैने सोचा

आप मैरे समर्थन करेंगें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक वर्ष के भीतर इसमें और बड़े बदलाव किए जाएंगे और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हेल्थ हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आने वाले समय में रणधीर जी, आपकी जितनी भी पीएचसी हैं, आप बता दीजिए, वहां डॉक्टर लगा दिए जाएंगे। आप देख लीजिए। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब मैं आग्रह करूंगा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय... (व्यवधान) इसमें स्पष्टीकरण थोड़ा होता है... (व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कुछ भी श्री विपिन सिंह परमार जी के लिए बोला है, तो उसे एक्सपंज कर दो।

अध्यक्षः ठीक है। वह तो अच्छी बात है, आप वहाँ से यहां आए, वह तो अपग्रेडेशन है, डाउनग्रेड थोडी न है... .....(व्यवधान) चलो ठीक है। अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय।...(व्यवधान) He will be briefing very shortly...(व्यवधान) शांडिल साहब, आप उत्तर देंगे या मुख्य मंत्री जी के उत्तर में ही आपका उत्तर सम्मिलित माना जाए।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....

30-03-2026/1610/केएस/एचके/1

अध्यक्ष जारी ...

मुख्य मंत्री जी ने मैडिकल एजुकेशन का जवाब दिया। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का जवाब आएगा। ...(व्यवधान) अगर आप लोग बोलना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन फिर उतना ही आपका टाइम आगे चला जाएगा। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। ठीक है, माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, कट मोशन का समय विपक्ष के विधायकों का होता है।

अध्यक्ष : जवाब भी तो देना पड़ता है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अगर सारी चीजों की सेंक्टिटी इस तरह से खत्म हो जाएगी कि क्लैरिफिकेशन के नाम पर मुख्य मंत्री जी ने 50 मिनट से ऊपर भाषण दे दिया, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष : क्लैरिफिकेशन नहीं थी that is Medical Education Department. मैडिकल एजुकेशन विभाग इनके पास है तो इन्होंने ही उसका जवाब देना था।

श्री जय राम ठाकुर : नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इन्होंने पहले ऐसा बोला होता कि मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं तो हम समझ सकते थे। । अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बहस नहीं करना चाहता। अगर जवाब देना था, व्यवस्था यह बनती है कि पहले मंत्री महोदय जवाब दें और उसके बाद अगर कुछ प्वाइंट्स रह जाते हैं तो उनका जवाब मुख्य मंत्री कभी भी दे सकते हैं। ये कह रहे हैं कि मैडिकल एजुकेशन मेरे पास है तो इस विषय पर अगर पांच या सात मिनट की बात कहते तो बात समझ में आती लेकिन जिस तरह से अभी किया जा रहा है।

अध्यक्ष : ठीक है, अब बात और ज्यादा समझ आ जाएगी। अब हो गया ठाकुर साहब, मैंने इजाज़त दे दी है ।

30-03-2026/1610/केएस/एचके/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष जी, आपसे तो हमें उम्मीद है कि व्यवस्थाएं बनी रहेंगी लेकिन इनकी तरफ से तो हम व्यवस्थाएं तार-तार होने की मान कर चल रहे हैं।

अध्यक्ष : ठीक है, आपकी बात आ गई। मैंने अलाउ किया है, आपको भी अलाउ कर दिया। आपने जो कहना था, वह कह दिया अब कृपया बैठ जाएं।

श्री जय राम ठाकुर : मैं समझता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति हमारा सम्मान है लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अगली डिमांड पर चलना चाहिए।

अध्यक्ष : अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जवाब देंगे । मंत्री जी, प्रतिपक्ष के मित्रों की संतुष्टि हो चुकी है अतः आप संक्षेप में बताएं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैं संक्षेप में ही बोलूंगा। प्रतिपक्ष के नेता ठाकुर जय राम जी ने मांग संख्या : 9 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर चर्चा में भाग लेना आरंभ किया था और उसके बाद जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। उनमें श्री पवन काजल, विपिन सिंह परमार जी जो स्वयं भी इस कार्यभार को देख चुके हैं a very senior Member and has been also in your august Chair. इन्होंने बहुत सार्थक सुझाव दिए हैं। इनके अलावा सर्वश्री सुख राम चौधरी, डॉ0 जनक राज, राकेश जम्वाल, पूर्ण चंद ठाकुर और अंत में माननीय डॉ0 हंस राज जी ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। मैं तो यही कह सकता हूं कि स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील और समाज से सम्बन्ध रखने वाली समस्या पर बोलना और इस गौरवमयी सदन में अपने विचार देना या यहां पर सार्थक सुझाव देना अपने आप में बहुत बड़ा काम है और मैंने उन सभी सुझावों के एक-एक बिंदु को लिखा है। किसी के सुझाव को भी नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे माननीय मुख्य मंत्री कह रहे थे, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वयं भी बहुत रुचि लेते हैं और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

30.03.2026/1615/av/hk/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री--------- जारी

स्वास्थ्य के विषय में बहुत इंटरस्ट लेते हैं। ये चाहते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हों तथा इनका सपना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में एक अग्रणी राज्य बने। मुझे उम्मीद है कि हम अवश्य एक अग्रणी राज्य बनेंगे। माननीय मुख्य मंत्री ने अभी आपके सामने अपने विचार व्यक्त किए हैं and I am extremely and deeply grateful for his continuance guidance which will really help in improving the matter.

हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है ताकि सभी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके, ऐसा हमारी सरकार का प्रयास है। प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य नीति राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत ही काम करती है। कुशल निवारक उपायों के कारण यद्यपि राष्ट्रीय औसत की तुलना में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सूचक बेहतर हैं परंतु फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सुधार के लिए सरकार कृत संकल्प है। The suggestions which are given by all the Hon'ble Members of the Opposition, there suggestions are very valuable and we will be acted upon as time progresses. स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश भर में 111 अस्पताल, 110 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 586 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 16 ई0एस0आईज0 डिस्पेंसरीज और 2115 उप स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। इसके अलावा 6 मेडिकल कॉलेज, एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, Atal Institute of Medical Super Specialities (AIMSS) Chamiyana तथा एक डेंटल कॉलेज प्रदेश में कार्यशील है। प्रदेश में प्रथम चरण में 70 स्वास्थ्य संस्थानों को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जा रहा है।। think it is a path breaking step और मैं समझता हूं क्योंकि जिस-जिस जगह भी मैं जा सका हूं क्योंकि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जहां पर मैं अभी नहीं पहुंच पाया हूं जैसे यहां पर माननीय सदस्य श्री सुख राम कह रहे थे। हालांकि वहां पर हमने बहुत सारे काम किए हैं परंतु मैं वहां पर जा नहीं सका। लेकिन मैं वहां अवश्य जाऊंगा। इसी प्रकार दूसरे विधान सभा क्षेत्र जहां-जहां आदर्श स्वास्थ्य संस्थान काम कर रहे हैं, उनमें बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। खासकर जैसे शिमला, सोलन इत्यादि के ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां से लोग पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ या एम्ज दिल्ली नहीं जा

30.03.2026/1615/av/hk/2

सकते। इसलिए वहां पर 6-6 स्पेशलिस्ट्स होना अपने आप में एक उपलब्धि है और उनको अगर वहीं स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि इनके मार्गदर्शन में बहुत सारे स्वास्थ्य संस्थानों का कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है।

यहां पर माननीय सदस्यों ने कुछेक बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, मैं उन सबका जिक्र नहीं करूंगा they have been all clubbed together यहां पर जैसे माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बढ़ती संख्या के बारे में चिंता व्यक्त की थी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में हाई ब्लड प्रैशर के 232827, डायबिटीज के 2348602, ओरल कैंसर के 414650, ब्रैस्ट कैंसर के 207210 और सर्वाइकल कैंसर के 183576 लोगों की जांच की है। माननीय श्री विपिन सिंह परमार ने कॉक्लियर इम्प्लांट का विषय भी उठाया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आर0बी0एस0के0 के तहत जीरो से दो वर्ष की आयु वाले 13 बच्चों को तीन वर्षों के दौरान कॉक्लियर इम्प्लांट लगाए गए। प्रत्येक पर 5.20 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। माननीय विधायक श्री सुख राम चौधरी ने पी0एस0ए0 ऑक्सीजन प्लांट का विषय भी रखा है। सरकार ने दिनांक 24 फरवरी, 2026 को प्रदेश भर के पी0एम0 केयर के अंतर्गत 17 फंक्शनल प्लांट्स को ए0एम0सी0 और सी0एम0सी0 के तहत 46.61 लाख रुपये की राशि जारी की है। सिविल होस्पिटल पांवटा साहिब में

टी सी द्वारा जारी

30.03.2026/1620/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री .... जारी

100 एल0पी0एम0 के पी0एस0ए0 प्लांट हेतु 4.83 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी ने ब्लड स्टेबिलाइजेशन यूनिट का विषय उठाया। आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में बी0एस0यू0 स्थापित करने के लिए भारत सरकार के उपक्रम एच0एल0एल0 को कार्य आदेश दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है। 26 बी0एस0यू0 स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें मेडिकल ऑफिसर और एल0टी0 को प्रशिक्षित किया गया है और उपकरण भी स्थापित कर दिए गए हैं। न्यू बॉर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट, जिसे एन0बी0एस0यू0 कहा जाता है, प्रदेश में 43 अधिसूचित हैं जिनमें से 14 पूर्ण रूप से फंक्शनल हैं। 16 यूनिट एच0एल0एल0 के माध्यम से स्थापित की जा रहे हैं।

माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी ने स्क्रब टाइफस संक्रमण तथा राज्य स्क्रब टाइफस अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विषय भी उठाया। इसके लिए हमने अपनी स्ट्रेटजी को case-based surveillance with mandatory laboratory confirmation पर आधारित है। रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से कम्युनिटी स्क्रीनिंग के परिणामस्वरूप वर्ष 2022 में 1527 मामलों से घटकर वर्ष 2025 में 605 मामले रह गए और मृत्यु संख्या 26 से घटकर 7 हो गई। स्क्रब टाइफस के टैस्ट जो पहले केवल मेडिकल कॉलेज तक सीमित थे उन्हें अब सभी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क कर दिया गया है।

माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी ने के0एन0एच0 और मेडिकल कॉलेज टांडा में Comprehensive Lactation Management Centre स्थापित करने का विषय भी उठाया। के0एन0एच0 में स्थान की उपलब्धता न होने के कारण इसे आई0जी0एम0सी0 में स्थापित करना प्रस्तावित है। टांडा मेडिकल कॉलेज में स्थापना हेतु 50.37 लाख रुपये लैब इक्विपमैंट के लिए और 20 लाख रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु वर्ष 2026-27 की पी0आई0पी0 में प्रावधान किया गया है।

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा कोविड-19 के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान विभिन्न स्वास्थ्यकर्मियों को आउटसोर्स के आधार पर कोविड सेंटर और सरकारी स्वास्थ्य

30.03.2026/1620/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

संस्थानों में एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। इनकी कुल संख्या 1739 थी जिसमें स्वास्थ्य विभाग में 641 और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में 1098 कर्मचारी शामिल थे। इनमें आवश्यकता के अनुसार स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पी0एस0ए0 प्लांट वर्कर, सेनेटेशन वर्कर और सुरक्षाकर्मी शामिल थे। इनकी नियुक्ति प्रारम्भ में 6 माह के लिए की गई थी, जिसे बाद में आवश्यकता अनुसार 6-6 माह के लिए बढ़ाया गया और यह कार्यकाल दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक जारी रहा। इन कर्मचारियों को कोविड-19 के दौरान संस्थानों में उपलब्ध स्टाफ की सहायता के लिए रखा गया था। इनके लिए ई0सी0आर0पी0 -I (Emergency Covid Response Package-I) के

अंतर्गत लगभग 7 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्टर हैल्थ सर्विसिज और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को उपलब्ध करवाई गई तथा ई0सी0आर0पी0-॥ के अंतर्गत लगभग 33 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके उपरांत एन0एच0एम0 (National Health Missioin) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त धन उपलब्ध न होने की स्थिति में राज्य बजट से लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई। **Mr. Speaker, Sir, I assure you that they have always been considered and wherever there was scope to put them in some outsource, we have done it and we shall still continue to do it.** जहां तक ड्रग मैनेजमैंट और सैंपल फेल होने के मामलों का प्रश्न है, यह विषय भी माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है। यह विषय कई बार अखबारों और सोशल मीडिया में भी आता रहा है।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

30-3-2026/1625/NS-YK/1

Health and Family Welfare Minister continued……

Mr. Speaker, Sir, I would like to submit that Himachal Pradesh is a major pharmaceutical manufacturing hub & contributes more than 30 per cent of domestic production in this regard. During 2024-25, the national (Not of Standard Quality) NSQ percentage was 2.66 per cent, whereas that of Himachal Pradesh was only 0.7 per cent. Mr. Speaker, Sir, during tenure of previous government, 3186 drug samples were reported as not of standard quality whereas during the tenure of present government 2315 samples have been detected as not of standard quality. Out of 2315 NSQ (Not of Standard Quality) cases, 1809 product licenses have been suspended so far. The Department also takes prompt actions such as stop sale, recall, and legal proceedings in such cases. Our present Government is a very-very strict on this issue. The 72 samples pertaining to Himachal in the drug alert of February

month pertained to 55 firms. Joint Risk Based Inspections with CDSCO have been conducted on 32 firms. Stop manufacturing orders were issued to 07 firms and licenses of 02 firms stand cancelled. During period 2018-2023 (previous government's tenure) 10,824 drug samples were tested whereas during just three years period of our Government 16,473 samples have been tested so far. We still have to continue this testing. Our government prioritized and ensured that the Drug Testing Laboratory at Baddi becomes functional. The Drug Testing Laboratory, Baddi was made functional in January, 2025 and so far 7086 samples have been tested at DTL Baddi. Thus, testing of samples have now been intensified. Drug regulation in the State is being effectively enforced under the Drugs and Cosmetics Act, 1940. Approximately 1200-1500 inspections are being conducted per year in manufacturing units annually, and more than 5000 samples are being tested every year. Overall, the State's regulatory system is robust, vigilant, and responsive. Drug sample failure cases are being addressed effectively and all strict actions, then required actions are being taken regularly. मैं यहां एक विषय जो श्री राकेश जम्वाल जी ने उठाया था और

30-3-2026/1625/NS-YK/2

मुझे भी ऐसा लगा and its our responsibility to ensure the cleanliness of our hospitals, चाहे वे प्राइमरी हैल्थ सेंटर्ज, सिविल हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल या चाहे एम्स है या कहीं भी और हॉस्पिटल है। Mr. Speaker, Sir, I feel that this is a joint responsibility and we all have to take this call and really become effective as Legislator also. I will also request you that there my be a small footnote added in the para that whenever there is any Minister moving to an area or visiting an area then all other elected representatives of that respective area are requested to come. So that we can jointly address what is prevalent in that area. हमारी लगातार कोशिशें होती हैं और जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अभी PET Scan is installed in IGMC and trials are underway. For PET Scan machine in Government Medical College Tanda, procurement process is also underway.

Free Dialysis Programme is a very important point, which was brought by many Hon'ble Members. 20 Dialysis Centres are functional, 49 New Dialysis Centres have been approved at Adarsh Swasthya Sansthans, where it will be introduced soon. Work awarded in 29 and will be made operational by June, 2026.

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ------ आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

30.03.2026/1630/RKS/AG-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी.....

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हिमकेयर और मुख्यमंत्री सहारा योजना के प्रति पूरी तरह गंभीर है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार सभी कार्य सुचारु रूप से संचालित हो रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा फरवरी, 2022 से वर्ष 2025 तक 344.47 करोड़ रुपये की निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान की जा चुकी है। मैं पूर्व सरकार के वर्ष 2018 से नवम्बर, 2022 तक के आंकड़ों का भी उल्लेख करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

Speaker : Please, no disturbance. Please order in the House.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय : अध्यक्ष ये संतुष्ट हैं, he is satisfied, I am very happy about it because he is such a senior Member. With your permission, Hon'ble Speaker, Sir, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमने चिकित्सकों के 232 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्विजिशन भेज दी है। ...(व्यवधान) स्टाफ नर्सों के 150 पदों को भरने के लिए भी मांग भेजी गई है। फार्मेसी अधिकारियों के 62 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मैं मानता हूं कि

Hon'ble Chief Minister had already covered it but रेडियोग्राफर के 30 तथा ओ.टी.ए. के 45 पदों को भरने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। इन पदों को भरने हेतु लोगों की काफी मांग रहती है। सी.एच.ओ. के 530 पद आउटसोर्स माध्यम से भरे जाएंगे। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस क्षेत्र में स्वयं रुचि लेते हैं और निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं समझता हूं कि यह न केवल हमारा बल्कि पूरे प्रदेश की जनता का सौभाग्य है that we really blessed with the personality जैसा कि माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया ने कहा था कि यह केवल व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक जुनून है। इनमें सचमुच में एक ऐसी ताकत है क्योंकि जिस प्रकार वाणों की वर्षा होती है उसी प्रकार आप सभी इनसे प्रश्न करते हैं परंतु he never loses his smile and keeps in smiling. That is a big quality of his personality and I can only tell you this much कि यह सब लोगों का ज्वाइंट काम है। यदि हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता

30.03.2026/1630/RKS/AG-2

नहीं होगी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमारे स्वास्थ्य संस्थान स्वच्छ हों। वहां सुंदर फूल लगे हों और उचित साफ-सफाई बनी रहे। मैं समझता हूं कि स्वच्छता से वहां का औरा बहुत अच्छा होगा जिससे मंदिर जैसी पवित्रता का अनुभव होगा। इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा और रोगी भी उपचार के बाद खुशी-खुशी अपने घर जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, there are so much detail which of course I have to tell you but since the time is limited, so I cannot give answer in detail.

Speaker : Hon'ble Minister, you can place it on the Table of the House and that will become a part of the record.

Hon'ble Health & Family Welfare Minister : Hon'ble Speaker, Sir, I will certainly do it because this is a detail reply with me which I want to give. But as desired by you and the House, I place it on the Table of the House. Thank you so much Hon'ble Speaker, Sir and I also thanks to Hon'ble Chief Minister who

had taken pain in making Health and Family Welfare Department where it is today.

With good upbeat mood of the House, I now request to the Members of the Opposition कि आप अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले लें।

30.03.2026/1630/RKS/AG-3

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, केवल बातों से काम नहीं चलेगा। जो कदम उठाए जा रहे हैं वे स्वास्थ्य विभाग को उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां गरीब व्यक्ति के लिए उपचार कराना और भी कठिन हो जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र का यह बजट पिछले बजट की तुलना में लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपये कम है। आप कब तक बातों के सहारे इस क्षेत्र को चलाएंगे? वर्तमान में यह क्षेत्र केवल बातों के भरोसे चल रहा है।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

30.03.2025/1635/बी.एस./ए.जी.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

आखिरकार मैं यही बोलूंगा कि हमनें जो कट मोशन दिए हम वापस नहीं लेंगे लेकिन मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए जो आवश्यक काम करने को हैं उस दिशा में आप काम करें। ऐसी मात्र घोषणा करके काम नहीं चलेगा। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप रोबोटिक सर्जरी की व्यवस्था मत करिए, आप करिए लेकिन यहां बिस्तर पर पड़ा हुआ मरीज उसको बेसिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है उसके बारे में आप कब सोचेंगे? अब आपने जो एजेंडा अपनाया है कि बड़े स्केल पर बड़ी परचेजिस करनी और बड़ी मशीन लानी है, आने वाले समय में यह सारे मुद्दे होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बेसिक स्वास्थ्य की सुविधा देनी चाहिए उस पर काम करने की आवश्यकता थी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रतिपक्ष अपने कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लेना चाहते हैं।

तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री जय राम ठाकुर जी, पवन कुमार काजल जी, विपिन सिंह परमार जी, सुखराम चौधरी जी, विनोद कुमार जी, डॉ0 जनक राज जी, त्रिलोक जम्वाल जी, पूर्ण चंद ठाकुर जी और आदरणीय हंसराज जी माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं?

तो प्रश्न यह है कि यह कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं?

कटौती प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत 27,04,54,01,000 रुपये (राजस्व) और मु0 35,19,14,000 रुपये (पूंजीगत) के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नंबर-3 में दर्शाई गई धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

30.03.2025/1635/बी.एस./ए.जी.-2

प्रस्ताव स्वीकार।

मांग संख्याः 9- स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण पूर्ण रूप से पारित हुई।

30.03.2025/1635/बी.एस./ए.जी.-3

अध्यक्ष : अब मांग संख्याः 10- लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन के ऊपर चर्चा होगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 10 लोक निर्माण-सड़क पुल एवं भवन के अंतर्गत 24,81,76,28,000 (राजस्व) और 11,04,82,00,000 (पूंजी) के निमित्त ऑर्डर पेपर के

कॉलम नंबर 3 में दर्शाई गई धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से दे दी जाएं।

अब मेरे पास जो list of order of priority वह आदरणीय सुख राम चौधरी जी जो भारतीय जनता विधायक दल के सचेतक हैं, उन्होंने दी है और इसमें 7 माननीय सदस्य इस कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेंगे। मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या मैं इन्हें प्रस्तुत हुआ समझूं।

सदस्यगणः इन्हें प्रस्तुत समझा जाए।

मांग संख्याः 10 - **लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन**छ

सदस्य का नाम कटौती प्रस्ताव मांग संख्या-10

नीति का अननुमोदन

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन

की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

1. श्री अनिल शर्मा
2. श्री बिक्रम सिंह
3. श्री जीत राम कटवाल
4. श्री इन्द्र सिंह
5. श्री प्रकाश राणा

1. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण मरम्मत एवं रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की मशीनरी तथा उपकर की नीति का अननुमोदन।

अब मैं माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी से आग्रह करूंगा

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

30.03.2026/1640/डीटी/DC-1

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-10 : लोक निर्माण-सड़क पुल एवं भवन जिसकी चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हुं। आपने मुझे समय दिया आपका धन्यावद। प्रदेश में सबसे महत्पूर्ण विभाग लोक निर्माण विभाग है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री अनिल शर्मा जी एक मिनट रुकिए। अभी 4 बजकर 40 मिनट हो गए हैं और 1 घंटा 20 मिनट के बाद गुलेटिन लग जाएगा तो इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि जल्दी से आप बोलेंगे तो इस मांग पर चर्चा भी हो सकती है और इसका उत्तर भी आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 6 O'clock I will apply the 'Guillotine'. माननीय श्री अनिल शर्मा जी।

श्री अनिल शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे मैंने कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से आगे ले जाने के लिए सड़कों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी जानते हैं हमारा पहाड़ी प्रदेश होने की वजह से हमारा सारा काम जो है क्योंकि ट्रेन व हवाई सुविधाएं हमारे प्रदेश में बिल्कुल कम है इसलिए सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से यदि हमारे प्रदेश को आगे ले जाना है तो उसमें सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है।

(श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए।)

अभी आपने देखा कि चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, चाहे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो, वे तभी मार्केट तक पहुंचेंगे जब हमारी सड़कें दुरूस्त होंगी। सड़कों के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से पैसा चाहे वह पी0एम0जी0एस0वाई0 में आता हो, चाहे नेशनल हाईवे की सड़कों के लिए आता है, वक्त व हालात बदले और यदि हमें मंडी से एयरपोर्ट की ओर जाना हो तो केवल ढाई घंटे में पहुंच जाते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं कि क्या प्रदेश में यह चीज हो सकती थी कि नहीं हो

सकती थी, परंतु संभव हुआ। हालात जो आपने देखे कि प्रदेश के अंदर जब बरसात का मौसम आता है और बरसात के मौसम में हमारी सड़कें टूटती हैं, यातायात का प्रबंध टूटता है, साथ में जो हमारी सारी उम्र की कमाई, जैसे हम कहते हैं कि हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है और जिसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले साल हमारी फसल अच्छी थी परंतु मैं अपने क्षेत्र की नहीं दरंग क्षेत्र की बात करूंगा क्योंकि मेरा वहां पर बगीचा भी है और वह सड़कें तब बनी जब मेरे पिताजी वहां के विधायक हुआ करते थे।

30.03.2026/1640/डीटी/DC-2

वह जगह हमारे एरिया में आती थी और सड़कें बनने के बाद अब हमारे लोक निर्माण मंत्री जोकि नौजवान मंत्री हैं और यह कहते हैं कि हम डी0पी0आर0 भेजते हैं तथा पैसा केन्द्र से आता है। बहुत अच्छी बात करते हैं और मैं इसमें राजनीतिक तौर पर कोई बात नहीं रखना चाहूंगा परंतु यह मानते हैं कि पैसे की कमी नहीं होती। हमारे जो पैसा लगने का काम है, पैसा कैसे लगता है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। ये सड़क नाबार्ड में आई थीं। पनारसा से राहड़ी और पनारसा से ज्वालापुर, ये दो सड़कें हैं और मैं इन सडकों का उदाहरण क्यों देना चाहूंगा क्योंकि लाखों रुपये का सेब हमारे बगीचे में सड़ता रहा। जब तक पी0एम0जी0एस0 वाई0 की सड़क नहीं बन रही थी तब तक कभी भी उस सड़क में लैंडस्लाइड नहीं हुआ। जैसे ही वह सड़क आपग्रेडेएशन में आई उसके बाद से उसकी दुर्गति ऐसी हो गई है कि अभी दो दिन की बारिश में वह सड़क फिर से टूट गई और सारी सड़क बह गई। अभी तो हमारे एप्पल को आने में देरी है परंतु मैं केवल एक उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि इस प्रदेश को यदि हम सड़कों से सारे साल मेहनत करने के बाद भी यदि हम उस प्रोड्यूस को आगे मार्केट में नहीं ले जाएंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि जब हम मनाली की तरफ जाते हैं, हमारे माननीय सदस्य श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी यहां बैठे हैं और वे जानते हैं कि हमारा टूरिज्म इफेक्ट होता है और वह सड़कों की वजह से होता है। गर्मियों के अंदर जो सारा टूरिस्ट मनाली की तरफ जाता है और मंडी से आगे, मंडी तक तो सड़क चलो ठीक है, हम

कहते है कि चंडीगढ़ से मंडी सड़क अच्छी है परंतु उससे आगे के लिए हमें कई बार आपको भी दिखना पड़ता कि हमारी सड़कें टूट जाती हैं और टूरिस्ट फस जाते हैं। वहां पर मुख्य मंत्री जी को जाना पड़ता है और उन्हें निकालने का प्रयास करना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि अब हमारे पास सोचने के लिए क्या है कि हमें क्या एक ही जैसा, मैं इन दो सड़कों की बात कर रहा था कि हमारे अल्टरनेटिव रूट नहीं हैं। अभी जो पी0एम0जी0एस0वाई0 में सड़कें आ रही हैं उसमें आपने जो डी0पी0आर0 बनाई, वह रिजेक्ट हो गई। उनके कारण क्या था कि थ्रू रोड और इसका मतलब

श्री एन0जी0द्वारा जारी....

30.03.2026/1645/डी.सी.-एन.जी./1

श्री अनिल शर्मा..... जारी

यह है कि एक सड़क से दूसरी सड़क को पी0एम0जी0एस0वाई0 में काट दिया और वे सड़कें अब नहीं जुड़ेंगी। चाहे वे 5 किलोमीटर हों या 6 किलोमीटर, परंतु वे सड़कें थ्रू रूट की वजह से पी0एम0जी0एस0वाई0 में कंसिडर नहीं होंगी। वे सभी डी0पी0आर0 रिजेक्ट कर दी गई हैं। हमसे क्या गलती हुई, सड़कों को हम क्यों जोड़ना चाहते हैं और मैं थ्रू रूट की बात क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि अगर एक सड़क बंद होती है तो हमें दूसरी सड़क से निकलने का रास्ता मिल सके। अगर कोई सड़क टूट गई तो आपके पास कोई रास्ता नहीं था कि आप किसी दूसरे रास्ते से निकल सकें।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। एक बार राजा वीरभद्र सिंह जी मेरे साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र का टूर कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि अनिल जी, आप वापिस कहां से जाएंगे? मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र में वापिस नहीं जाते, मेरी गाड़ी हमेशा आगे की ओर चलती है। हम एक तरफ से जाते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें हिमाचल प्रदेश में सड़कों के जाल के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं

डॉक्टर वाई0 एस0 परमार के समय से यानी बचपन से देख रहा हूं कि हमारी सड़कों की हालत बहुत बुरी थी। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि प्रदेश में इस तरह की सड़कें बनेंगी। परंतु फिर भी अगर हम पी0एम0जी0एस0वाई0 की बात करें, मैंने लोक निर्माण मंत्री जी से भी यह बात कही थी कि जब तक हम ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, तब तक समस्या बनी रहेगी। जो सड़कें पी0एम0जी0एस0वाई0 में बनी हैं, साल-डेढ़ साल के अंदर ही उन सड़कों को रिपेयर करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। टारिंग करने के डेढ़-दो साल बाद आपके पास फण्ड नहीं होते। आप कहते हैं कि सड़क बनाने वाला पांच साल तक उस सड़क को मैंटेन करेगा।

30.03.2026/1645/डी.सी.-एन.जी./2

आप यह भी मानते हैं कि यदि हम पी0एम0जी0एस0वाई0 में सड़कें अवार्ड करते हैं तो वे पांच साल सड़कें मैंटेन भी करते हैं, पर क्या वास्तव में वे मैंटेन होती हैं? हमारे ऊपर मानसिक दबाव रहता है कि जब हम नेशनल हाईवे से अपनी सड़कों या पहाड़ी सड़कों की तरफ जाते हैं तो उसमें बहुत मुश्किल आती है। मेरा अनुरोध रहेगा कि सड़कों का बजट तो घटता जा रहा है और रिपेयर के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए जब तक इन सड़कों का रख-रखाव नहीं होगा व ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा नहीं जाएगा तब तक ये सड़कें फुल-प्रूफ नहीं हो सकती हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नाबार्ड में हमारी 10 सड़कें आ रही हैं, कहीं दो सड़कें आ रही हैं। मैं यह बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैंने एक सड़क नाबार्ड में डाली थी और मैं हमारे पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का आभारी हूं क्योंकि एक बार मैं उनके पास गया तो मण्डी में जो विक्टोरिया पुल है, मैंने उस विक्टोरिया पुल के समानांतर एक अन्य पुल बनाने के लिए कहा। उस समय मैंने नाबार्ड के तहत 25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था और वह पैसा मंजूर नहीं हुआ था। फिर भी उसके लिए अन्य मद से पैसा दिया गया और उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। उसके उद्घाटन के समय कहा गया कि इस पुल को बनाने का फायदा क्या है। मैं बताना चाहता

हूं कि एक विधायक की सोच अलग हो सकती है। उद्घाटन करने वाले जरूर कह गए, परंतु मैंने मण्डी बायपास बनाने के लिए कई वर्षों से नाबार्ड में 23 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 और 5 करोड़ रुपये के पुल डाले हुए हैं। वह सैंक्शन अभी तक रुकी हुई है। मैंने जोगिंदर नगर, पालमपुर व बैजनाथ की तरफ देखा कि अभी तक शहर के बीच से होकर ही गुजरना पड़ता है। मैंने मण्डी शहर को थ्रू करने के लिए प्रयास किया ताकि ट्रैफिक शहर के अंदर न जाए। इसके लिए मैंने मण्डी बायपास की योजना सरकार के माध्यम से डाली थी। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की डी0पी0आर0 बनाकर ट्रैफिक को शहर के बाहर ले जाया जाए। हमारा अस्पताल शहर के अंदर है और उसे भी थ्रू करने के लिए हमारा यह प्रयास था कि बायपास बनाया जाए।

30.03.2026/1645/डी.सी.-एन.जी./3

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो यह थ्रू रूट है, यह पी0एम0जी0एस0वाई0 में कैसे जोड़ा जा सकता है? मेरा आग्रह है कि माननीय लोक निर्माण मंत्री केंद्र सरकार से बात करें और 4-5 या 1-2 किलोमीटर के थ्रू रूट छोड़कर जो 5-6 किलोमीटर के थ्रू रूट हैं, उन्हें भी कंसिडर किया जाए। मैं लोक निर्माण मंत्री जी के ध्यान में एक फुट ब्रिज की बात लाना चाहता हूं। पूर्व में राजा वीरभद्र सिंह जी के पास कोई आया और उन्होंने कहा कि पुरानी मण्डी में एक फुट ब्रिज बना दीजिए। उन्होंने इसकी अप्रूवल भी दे दी और लगभग 3.5 करोड़ रुपये का फुट ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके बारे में स्थानीय विधायक को कुछ पता नहीं था कि कैसे वह फुट ब्रिज एम्बुलेंस ब्रिज बन गया। एम्बुलेंस ब्रिज बनने की वजह से आज उसकी लागत लगभग 20 करोड़ रुपये हो गई क्योंकि 10 करोड़ रुपये तो केवल लैंड एक्विजिशन में लग गए। जबकि 100 मीटर की दूरी पर एक ब्रिज है और 150 मीटर की दूरी पर दूसरा ब्रिज है। किसने कहा

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

30.03.2026/1650/एच0के0/ए0पी0-01

श्री अनिल शर्मा जारी .....

कि आप एक एम्बुलेंस रोड के लिए 10-10.5 करोड़ रुपये का भूमि अधिग्रहण करें। इसका मैं जिक्र इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग स्थानीय विधायक से पूछकर काम नहीं करता है। अब आप ही बताइए कि जब उस एम्बुलेंस रोड का कोई औचित्य ही नहीं है, तो वह रोड किसने बना दिया। दूसरा उदाहरण मैं यह देना चाहता हूं कि मंडी शहर के अंदर हम एक एम्बुलेंस रोड बनाने की बात करते हैं। पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने हमें एक रूट बनाने की बात कही थी। ठीक है, उस समय मैं उन चीजों को दे नहीं पाया, परन्तु आज जब मैं देखता हूं कि पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग ने कहा का पैसा कहा पर लगा दिया है। वहां पर पार्किंग का कार्य होना था। उस काम के लिए पांच करोड़ रुपये दिए गए थे। वहां पर अभी पार्किंग का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, वह कार्य भी अधूरा है। आपने पैसा किस लिए दिया और विभाग द्वारा उस पैसे का इस्तेमाल किस लिए किया गया। जब तक इस तरह से काम करते हैं, जो हमारा पुल ट्रेजरी तक बनना था, जो बाईपास बनना था, मैं कहना चाहता हूं कि पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग वाले उस पैसे को किस तरह से लगा रहे हैं। समय कम है और बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए थोड़ी-थोड़ी बात हम सब रखें। मंत्री जी, माननीय सदन में बैठे हैं और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमारा एक पुल आपदा के दौरान बह गया था। मंत्री जी ने उस समय कहा था कि मार्च तक हम इस पुल का काम करके आपको देंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि कई तरह की बातें सरकार को आती हैं, मार्च से अप्रैल भी हो सकता है। परन्तु मैं इस बात को माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं क्योंकि वहां पर एक प्रोजेक्ट और पुल दोबारा उठाया जाना था। आज जो वहां पर पुल बना है, उसे देखकर मैं खुद हैरान हूं कि आपके पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में कैसे लायक इंजीनियर हैं। वे इतने लायक हैं कि उन्होंने हमें कहा कि वैडमेंट है, इसी के ऊपर हम वैली ब्रिज बनाएंगे। परन्तु उस वैली ब्रिज को बनाने के लिए वैडमेंट ऐसी जगह पर बनाई गई है। माननीय श्री प्रकाश राणा जी भी यहीं हैं और वह पुल हमारे दोनों के चुनाव क्षेत्रों को जोड़ता है। जब माननीय श्री पं0 सुख राम जी ने उस पुल के लिए पैसा दिया था तो वहां पर सड़क नहीं होती थी। उस समय वह डबल लेन का पुल बना था।

30.03.2026/1650/एच0के0/ए0पी0-02

परन्तु उस पुल के बनने के बाद आप अपने विभाग से पूछिए, बरसात में वह पुल फिर से बह जाएगा। पहाड़ के दोनों तरफ पत्थर खड़े कर दिए हैं। अगर आपने टेम्परेरी पुल बनाना था, एम्बेडमेंट द्वारा बनाना था तो क्या आप साइट बदल नहीं सकते थे। परन्तु आपके विभाग के लोग दिमाग नहीं लगा सकते। अभी पी0डी0एन0ए0 में पैसा आ रहा है, आप खुद देखिए कि वे किस तरीके से लगाया जा रहा है। 1 करोड़ 40 लाख रुपये एक सड़क के लिए आया है। जब मैंने एस0डी0ओ0 और एक्सईएन को बोला कि यह ग्रेड ठीक नहीं है, आप इसे बदलें, तो विभाग ने कहा कि इसमें कोई प्राइवेट जमीन आती है। जब मैंने पता किया तो वह सरकारी जमीन निकली और अब उसका एफ0आर0ए0 बनाया जा रहा है। आपके विभाग की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम देखें। आप विदेशों का ड्रेनेज सिस्टम देखें, कितना अच्छा है। हमारी कुदरत ने पहाड़ों के अंदर स्लोप दे रखा है। यदि हम सड़कों को स्लोप की तरफ ले जाएं तो ड्रेन भी बन सकती है। मैं पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग को समझाने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा जो हमारी नाबार्ड में सड़कें आ रही हैं, उनमें एन0पी0वी0 हमारे विभाग में पेनल्टी की तरह से आ रहा है। इसके बारे में विभाग को भी पता है। अगर हम इन्हें नाबार्ड में डालते हैं तो सरकार को इसके ऊपर एन0पी0वी0 भरना पड़ेगा। सभापति महोदय, जो प्रदेश में सड़कों के रखरखाव की बात मैं करना चाहता हूं, बहुत सी सड़कें पी0डब्ल्यू0डी0 के माध्यम से बनी हैं। डिवेलपमेंट प्लान के माध्यम से बनीं, नाबार्ड के माध्यम से बनीं हैं और अगर उनमें आपकी बसें नहीं जा सकतीं क्योंकि वहां पर लोगों ने सड़क बनाने के लिए जगह ही नहीं दी। एम्बुलेंस रोड है, उस रोड के आगे नाबार्ड से आपने 5 करोड़ रुपये में बसेवल सड़क बना दी। हमें तो हैरानी है कि विधायक लिखता है कि फलानी से फलानी सड़क तक सड़क होनी चाहिए। क्या डी0पी0आर0 विधायक बनाता है? यह विधायक का काम है? जब डी0पी0आर0 मंजूर होती है तो उसमें जो कमी है, उसको पूरा करने के लिए विभाग को देखना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग काम में किस तरह की क्वालिटी का प्रयोग कर रहा है। मंत्री जी, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर आज टेंडर होता है तो कोई अपनी पत्नी या किसी अन्य नाम से

टेंडर लेता है। लगभग ऐसे 10 लोग टेंडर भर रहे हैं। आप जो टेंडर फ्लोट कर रहे हैं उसका 50 प्रतिशत से कम टेंडर हो रहा है।

…..श्री ए0टी0 द्वारा जारी …..

30.03.2026/1655/AT/HK/01

श्री अनिल शर्मा जारी…

एक करोड़ का काम है उसका 40 लाख रुपये का टेंडर हो गया और वह 60 प्रतिशत डाउन चला गया है। तो इसमें गलती किसकी है? टेंडर बनाने वाले की या टेंडर भरने वाले की? फिर क्वालिटी कहां से बनेगी? प्रश्न इस बात का होता है। क्योंकि पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग बहुत बड़ा विभाग है और इसमें बहुत से काम इसमें हो सकते हैं। मेरा कहना है कि नेशनल हाईवे और पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के बीच में कोई समन्वय नहीं है।

मैं पिछले कल अपने गांव रोपड़ू गया था । वहां पर नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है और वहां वर्टिकल कटिंग कर दी गई ह। नीचे गरीब लोग रह रहे हैं। कुछ दिन पहले दिन के समय ऊपर से पत्थर गिरे हैं। यह तो भगवान का शुक्र है कि वह किसी के घर पर नहीं गिरे। गांव नीचे है और ऊपर नेशनल हाईवे वाले यह किस तरह की कटिंग कर रहें है? क्योंकि यह काम पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के अंतर्गत नहीं है। इसलिए पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग इसे देख नहीं सकता क्योंकि नेशनल हाईवे के लोग उस में काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि दोनों विभागों के बीच समन्वय बनाया जाए। क्योंकि नेशनल हाईवे का काम केंद्र सरकार के मोर्थ के माध्यम से हो रहा है। लेकिन इस में प्रदेश सरकार का भी दायित्व बनता है। आज मंडी से आगे पंडोह के लिए जो टनल बनाई जा रही है पहले आप कहां थे आप? अब कटिंग के कारण वहां स्लाइड शुरू हो गई है और इस बात को मंत्री जी ने भी माना है कि दरिया के साथ उसी जगह पर ही क्रेट कलर्वट लगाए जा रहे हैं। करोड़ों रुपये पहले ही खर्च हो चुका है और फिर इस बरसात में चला जाएगा इसको कोई भी देखने वाला नहीं है और कोई भी पूछने वाला नहीं है कि आप इसको क्यों लगा रहे हैं, एक ही बार में आपका यह रोड बह गया। यह काम सही तरीके से क्यों नहीं किया गया। मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि जो लैंडस्लाइड और डिजास्टर हमारे प्रदेश में हो रहे हैं उनके

लिए हम किस प्रकार बैठकर आगे के लिए फुल-प्रूफ योजना बना सकते हैं, ताकि सड़के सुरक्षित और मजबूत बनें। सबसे बड़ी बात विभाग की क्वालिटी है और उसे कैसे बनाए रखें। हम विधायक कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। हम हर सड़क तक नहीं पहुंच सकते। आपके जे0ई0, सुपरवाइजर और स्टाफ

30.03.2026/1655/AT/HK/02

को देखना चाहिए कि सड़कों का रख-रखाव कैसा है। अगर एक साल के अंदर ही टाइल ऊपर उठ जाती है तो इसका क्या मतलब है?

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है क्योंकि ये महनती हैं और डी0पी0आर0 काफी बनाते हैं यह अच्छी बात है और केंद्र से पैसा मिलना भी अच्छी बात है लेकिन जब तक विभाग को मजबूत नहीं किया जाएगा और उसकी निगरानी नहीं होगी इन सभी बातों के लिए तब तक विभाग में सुधार नहीं होगा।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रदेश में सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वह टूरिज्म के लिए हो या हमारे प्रोड्यूस के लिए हो। इसलिए इनके बेहतर रख-रखाव पर ध्यान देना जरूरी है। इन शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री बिक्रम ठाकुर जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बिक्रम ठाकुर : माननीय सभापति महोदय, डिमांड नंबर-10, लोक निर्माण (सड़क, पुल एवं भवन) पर जो कटौती प्रस्ताव हमने दिया है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सड़कों के विषय में इस सदन में लगातार चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जसवां प्रागपुर विधान सभा क्षेत्र में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है और वर्तमान में जो पद भरे हुए हैं उनमें काफी कमी है। जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की एक ही पोस्ट है और एक ही है, सुपरिंटेंडेंट ग्रेड की एक पोस्ट खाली है,

एस0डी0ओ0 (HDM) की एक पोस्ट खाली है, जे0ओ0ए0 (आई0टी) की दो पोस्ट खाली हैं और जे0ई0 सिविल की दो पोस्ट भी खाली हैं। माननीय मंत्री जी बताएं कि जहां 10 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वहां केवल 4 लोग हैं तो विभाग कैसे काम करेगा? सड़कें कैसे बनेंगी? डी0पी0आर0 कैसे बनेगी? यह केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र की स्थिति नहीं है बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में यही हाल है। अगर डिवीजन में एस0डी0एम0 नहीं है, जे0ओ0ए0 (आई0टी) नहीं है, जे0ई0 नहीं है, तो काम कैसे होगा? सड़कों का रख-रखाव कैसे होगा? मैं पहले भी यह बात आपके ध्यान में ला चुका हूं कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। पैचवर्क तक नहीं हो पा रहा है। अभी जो CAG की रिपोर्ट आई है...

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....

30-03-2026/1700/केएस/वाईके/1

श्री बिक्रम सिंह जारी ---

उसमें उन्होंने पी0डब्ल्यू0डी0 के कामकाज के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सी0आर0आई0एफ0 के तहत 136 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बिना निर्धारित फंड बनाए ही खर्च कर दी गई जिससे सड़क कार्यों की पारदर्शिता और धन के सम्भावित दुरुपयोग पर गम्भीर संदेह है। 1946 करोड़ रुपये की योजना राशि को राज्य बजट और विधान सभा की निगरानी से बाहर रखा गया। ऑडिट ने दुरुपयोग या धोखाधड़ी की जो सम्भावना है, उससे इंकार नहीं किया है। सरकारी सामग्री की चोरी और गबन के मामले निर्माण कार्यों में जमीनी स्तर पर नियंत्रण की कमजोरी उजागर करती है। बड़े पैमाने पर धन का दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर धन का उपयोग ना होना या वापिस करना यह दर्शाता है कि परियोजनाएं कागजों तक ही सीमित हैं। कुल मिलाकर यह जो रिपोर्ट है यह ऐसे तंत्र की ओर इशारा करती है कि यहां धन का ना तो पारदर्शी तरीके से वहां काम हो रहा है और ना उसका सही तरीके से उपयोग हो रहा है जिससे वित्तीय अनुशासन और बुनियादी ढांचा, दोनों पर ही गम्भीर असर पड़ रहा है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर वर्ष 2019 से 2023 तक नाबार्ड के अंतर्गत 3827 लाख रुपये आए हैं और इस सरकार में वर्ष 2023 से 2026 तक 11.54 करोड़ रुपये

आए हैं। सी0आर0एफ0 में वर्ष 2019 से 2023 तक 60.80 करोड़ रुपये और वर्ष 2023 से 2026 तक केवल 6.00 करोड़ रुपये आए हैं। शैड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में तो आपने हद कर दी है। वर्ष 2024-25 में पूरे डिविजन के अंदर इसमें केवल 82 लाख रुपये आए हैं। वर्ष 2025-26 में केवल 1.74 करोड़ रुपये आए हैं। अगर इस प्लान में एक वर्ष के अंदर एक करोड़ या इससे कम पैसा आएगा तो किस प्रकार से सड़कें ठीक होंगी और किस प्रकार उनका रख-रखाव होगा? मैं शैड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में बनने वाली कुछ सड़कों का वर्णन करना चाहता हूं जिनका काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर पैसा नहीं है। जैसे- Link road from Samnoli to Nikala Sawana खर्चा हुआ है 36.54 लाख रुपये जबकि रिक्वायरमेंट 51.53 लाख रुपये की है। Extension of link road Harijan Basti Salui to Kabirpanthi Basti, Gram Panchayat Pir Saloi खर्चा 24.00 लाख रुपये हुआ है जबकि रिक्वायरमेंट 55.00 लाख रुपये की है। इसी तरीके से Construction of link

30-03-2026/1700/केएस/वाईके/2

road from Harbag Puli to Kabirpanthi Basti, Village Bhajnath, Gram Panchayat Uppar Pragpur खर्चा हुआ है 25.00 लाख रुपये जबकि रिक्वायरमेंट 61.00 लाख रुपये की है। Construction of link road from Main Road to the Baryal Bedh खर्चा हुआ है 11.00 लाख रुपये जबकि रिक्वायरमेंट 34.39 लाख रुपये की है। तो इस तरह से काम कैसे पूरा होगा? बजट का आकार आपने घटा दिया, बिल्कुल कम कर दिया। बिल्डिंग्ज़ का भी यही हाल है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर वैटरनरी पोली क्लिनिक बना है। 28.06.2021 को काम शुरू हुआ था और आज वर्ष 2026 आ गया है और आपका काम वहां पर पूरा नहीं हुआ। खर्च वहां पर 2.14 करोड़ रुपये हो गए हैं और जरूरत 2.68 करोड़ रुपये की है। डिग्री कॉलेज रक्कड़ 4.12.2028 का अवार्डिड है और उसके ऊपर खर्चा 9.48 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं जबकि 5.6 करोड़ रुपये के फंड्ज़ की रिक्वायरमेंट है। डिग्री कॉलेज कोटलाबेड़ 29.04.2021 को अवार्ड हुआ है और इसके ऊपर खर्चा 8.51 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और इसको 3.24 करोड़ की जरूरत है। गवर्नमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल जिसके 6 कमरे बनने हैं, दिनांक 26.05.2022 को अवार्ड हुआ है जिस पर केवल 51 लाख रुपये खर्च हुए हैं जबकि ज़रूरत 58 लाख रुपये की है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ..

30.03.2026/1705/av/yk/1

श्री बिक्रम सिंह--------- जारी

गवर्नमैंट हाई स्कूल अप्पर भलवाड़ का काम दिनांक 14.02.2023 को शुरू हुआ जिस पर 20 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं तथा अभी 14.23 लाख रुपये की रिक्वायरमैंट और है। इसी तरीके से जी0एस0एस0एस0 बल्याणा के कमरे बनने हैं। यह काम भी वर्ष 2020 में शुरू हो गया था जिसके लिए 19 लाख रुपये की जरुरत है। गवर्नमैंट मोडल आई0टी0आई0 संसारपुर टैरेस का काम दिनांक 15.01.2020 से चला हुआ है। उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ तथा लगभग 1.75 करोड़ रुपये की अभी और जरूरत है। शैड्यूल्ड कास्ट कम्पोनेंट प्लान के अलावा जो वहां पर बिल्डिंग्ज बन रही हैं, मैं उनके बारे में यह कहना चाहता हूं कि उनके ऊपर ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी मंत्री महोदय के ध्यान में लाया था और यह भी कहा था कि आपसी समन्वय से काम किया कीजिए। मैं जब ऐसी बातें करता हूं तो आपको बुरा लगता है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पहले रियली न्यू स्कीम दो जाती थीं परंतु उसको घटाकर अब एक कर दिया है। हम चाहते हैं कि हर गांव को सड़क जाए तथा हर जगह पुल व कॉजवेज बनें। परंतु वे कहां से बनेंगे जब आप रियली न्यू स्कीम को ही कम कर रहे हैं। मैंने आपसे भारत सरकार को रक्कड़-चपला-अप्पर भरोली-टिक्कर-शांतला सड़क भेजने की बात की थी। उसकी पहली डी0पी0आर0 दिनांक 26.08.2020 को बनी थी जिसके अनुसार उस सड़क पर 1327 लाख रुपये खर्च होने थे। लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। मैं इस बारे में लगातार अनुरोध करता रहा। आदरणीय मुख्य मंत्री ने प्लानिंग की मीटिंग में बोला था कि इस सड़क को हम अभी भेजेंगे तथा सचिव (लोक निर्माण), हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी उस समय सिर हिलाकर हामी भरी थी कि ठीक है। इस सड़क की डी0पी0आर0 दोबारा बनाने के ऑर्डर हुए। फिर दिनांक 07.05.2025 को

इस सड़क की दोबारा से डी0पी0आर0 बनाई गई। इसकी पहली डी0पी0आर0 1327 लाख रुपये की थी परंतु विभाग की लेटलतीफी के कारण अब यह डी0पी0आर0 3139 रुपये की

बनी है यानी पहले से तीन गुणा ज्यादा राशि की बनी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है तथा यह स्पेसिफिक रोड भारत सरकार को क्यों नहीं भेजा गया? मेरा माननीय मंत्री से दोबारा निवेदन है कि इस रोड की डी0पी0आर0 को सी0एस0आर0 के अंतर्गत भेजें नहीं तो एक वर्ष बाद फिर से वहां से फरमान आएगा कि नयी डी0पी0आर0 बनाइए। उसके पश्चात एक वर्ष फिर से डी0पी0आर0 बनाने को लग जाएगा जिसके कारण इसका दो-तीन गुणा खर्चा और बढ़ जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप इस डी0पी0आर0 को जल्दी भेजें।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग के संदर्भ में समय-समय पर जो खबरें आती हैं इनको गम्भीरता पूर्वक लेना चाहिए क्योंकि लोक निर्माण विभाग के कार्यों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। जागरण में दिनांक 20 मार्च, 2026 की रिपोर्ट है कि कुल्लू से आनी उप-मण्डल में गुगरा जाऊं सड़क के ऊपर बनने वाले कंकरीट के डंगों में सीधे पत्थर भरे जा रहे हैं। उस बारे में वीडियो भी वायरल हुआ था। उस बारे में क्या एक्शन हुआ या क्या नहीं हुआ, इस बारे में मंत्री जी जानते होंगे। मण्डी के एक ही ठेकेदार को 66 ठेके दे दिए गए और माननीय हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को इस बारे में कड़ी फटकार लगाई है। कांगड़ा में घटिया निर्माण के कारण पी0एम0जी0एस0वाई0 के 5 प्रोजैक्ट्स रद्द कर दिए गए। इसी प्रकार से लाहौल-स्पिति का मामला भी आया है। जिसमें पोह से डंगर सड़क को चौड़ी करना था और बिना वन विभाग की अनुमति से वह काम शुरू कर दिया गया। जिसके कारण बाद में वह काम रुक गया और उसका पैसा भी रोक दिया गया। हिन्दुस्तान टाइम्स में यह लिखा गया है कि राज्य की सड़कों के नुकसान से 5400 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ और सरकार नई ड्रेनेज पॉलिसी की बात कर रही थी। जिसके बारे में आदरणीय श्री अनिल शर्मा ने डिटेल में बोला है। पहले पत्थर डाला जाता है फिर मैटलिंग व टारिंग होती है और दोनों तरफ चुना भी डाल दिया जाता है। मगर

30.03.2026/1705/av/yk/3

उसके बाद ठेकेदार उसी सड़क में नालियां बनाने का काम शुरू कर देता है जिसके कारण वह सड़क दोबारा से पूरी-की-पूरी टूट जाती है। आपके पास इतने बड़े-बड़े व समझदार इंजीनियर है। उसके बावजूद क्या कारण है जो इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं? यहां पर सड़क के बारे में अच्छे-अच्छे सुझाव आते हैं कि इस-इस तरीके से काम कीजिए ताकि आपकी सड़कें ठीक रहें। मुझे लगता है कि लोक निर्माण विभाग को इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

टी सी द्वारा जारी

30.03.2026/1710/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री बिक्रम सिंह.... जारी

मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए हैं और कुछ प्रोजैक्ट के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का निवेदन किया है। शेड्यूल कास्ट कम्पोनेंट प्लान में भी काफी कटौती की गई है। मेरा निवेदन है कि आदरणीय मंत्री जी इन सभी विषयों को गंभीरता से लेंगे। इसी कारण हमने इस विषय पर कट मोशन प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

30.03.2026/1710/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

सभापति : अब माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल जी अपना विषय उठाएंगे।

श्री जीत राम कटवाल : धन्यवाद सभापति महोदय, मांग संख्या 10 जो कि लोक निर्माण विभाग से संबंधित है, उस पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस सरकार के विकास से संबंधित पैरामीटर्ज अथवा व्यवस्था परिवर्तन और आत्मनिर्भरता की जो फिलॉसफी है, उसके संदर्भ में कुछ बिंदु प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मेरी सरकार द्वारा यह किया गया, मेरी सरकार द्वारा वह किया गया तो यहां यह स्पष्ट है कि एक constitutional violationऔर एक improprietary

होती है। राज्य में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं और उनके नाम से ही कैबिनेट मुख्य मंत्री के नेतृत्व में राज्यपाल महोदय को ऐड और एडवाइज देती है। इस दृष्टि से भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

पिछले 3 वर्षों से व्यवस्था परिवर्तन की बात की जा रही है और यह चौथा बजट है।

इस अवधि में व्यवस्था परिवर्तन का कुछ स्पष्ट प्रभाव दिखाई देना चाहिए था। वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य बनने की बात कही जाती रही है यानी यह कहा जाता है कि वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा जबकि अब उसमें लगभग 9 माह का समय शेष है।

यदि बजट का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो वर्ष 2025-26 का बजट 58,514 करोड़ रुपये का था जबकि वर्तमान बजट 54,928 करोड़ रुपये का है। इसमें इस वर्ष लगभग 3,586 करोड़ रुपये कम हैं और इसका प्रभाव सभी विभागों की गतिविधियों पर स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति भी अपेक्षित स्तर पर दिखाई नहीं देती। एस0सी0डी0पी0 के बजट में, विशेषकर पी0डब्ल्यू0डी0 और जल शक्ति विभाग से हमें बड़ी उम्मीद रहती है। उनका बजट भी न के बराबर है, उसके लिए भी इस बजट में कहीं 5 लाख, 6 लाख या 10 लाख रुपये जैसी सीमित धनराशि ही दी गई है। यदि आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की दिशा में यह एक यात्रा है तो यह लक्ष्य प्राप्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता। यह स्थिति जनता के साथ विश्वासघात और माननीय सदन में उनके साथ किए गए वादों के भी विपरीत है।

30.03.2026/1710/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

जहां तक पी0डब्ल्यू0डी0 के कैपिटल वर्क्स का प्रश्न है जिसमें सड़कों, भवनों और पुलों का निर्माण करना होता है तो उसमें भी पिछले तीन सालों में कमी आई है। राजस्व प्राप्तियों के आंकड़े देखें तो वर्ष 2024-25 में यह 40,672 करोड़ रुपये थी, वर्ष 2025-26 में 42,342 करोड़ रुपये थी और वर्ष 2026-27 में घटकर 40,361 करोड़ रुपये रह गई है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम जो कमिटमैंट्स

जनता के साथ कर रहे हैं क्या हमारे पास इन कमिटमैंट्स को पूरा करने के लिए संसाधन व पैसा उपलब्ध हैं? क्या उनको हम हासिल कर सकते हैं या फिर वे

एन0एस0 द्वारा ... जारी

30-3-2026/1715/NS-AG/1

श्री जीत राम कटवाल-----जारी

कैरी-फॉर्वर्ड सिस्टम में चली हैं कि हर साल वायदे किए गए लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं। इसकी मॉनिटरिंग भी समझ नहीं आती है। वर्ष 2024-25 में केपिटल एक्सपेंडिचर 9,937 करोड़ रुपये था और उसके अंगेस्ट पिछले वर्ष 5,140 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था। इस वर्ष की अभी फाइनल फिग्र्ज नहीं आई है। 31 मार्च तक 8,281 करोड़ रुपये एस्टिमेटिड है और यह भी पूरा नहीं होगा। इस दफा सरकार को गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जैसी परिस्थितियां यहां पर बताई भी गई हैं। विधायक क्षेत्रीय विकास निधि या ट्रेजरी बिलों का पास होना आदि सारी चीजें बाधित रह रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष का करंट प्राइसिस पर केपिटल बजट 60,988 करोड़ रुपये है जोकि पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 20 प्रतिशत कम है। इसमें जब एक्चुअली खर्चे की बात आएगी तो बहुत कम डवलपमैंट वर्क्स होंगे। मैं जब सड़कों, भवनों या पुलों की बात करूंगा तो बताऊंगा कि क्या स्थिति है और किस हालत में चीजें हैं? आप इसे उसका मिस्यूटिलाइजेशन भी कह सकते हैं कि कोई पुल बना है तो डंगे नहीं लगे हैं, कोई सड़क बनी है तो आधी-अधूरी छूटी हुई है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो सेक्टरल डवलपमैंट है और जो प्योरली कंस्ट्रक्शन है वह 4,446 करोड़ रुपये हैं। यह बहुत कम है और उसमें पी0डब्ल्यू0डी और टूरिज्म एंड सिविल एविएशन का 1209 करोड़ रुपये हैं। इससे नहीं लगता है कि हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे या हम इससे अपने कुछ गंतव्य या टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। जैसे कि मैं सड़कों की बात कर रहा था। मैंने पहले भी दो-तीन बार पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की कार्यप्रणाली पर चर्चा की है। मेरे क्षेत्र में 9 पुल बने हैं और उनमें से 4 पुल बिना अप्रोचिज के हैं तथा इनको बने हुए लगभग 4 वर्षों का समय हो गया है। ये अगस्त-सितम्बर, 2022 को बन कर पूरे हो गए थे। मैंने इसके लिए मुख्य मंत्री जी को भी कहा था कि इनको पूरा करवाएं। इस दफा

आपने नाबार्ड की लिमिट 200 करोड़ रुपये से 225 करोड़ रुपये की है और उसमें एक आर0एन0एस0 (Really New Scheme) और 4 स्कीमें रिपेयर वाली शामिल की हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि इसके बारे में गौर करें। कुछ सड़कें पुरानी हैं और उनको हमने रिपेयर में भी डाला है। ज्यादातर सड़कों के ऊपर ही लोगों की मांग रहती है और वे सोचते हैं कि हमारे घर तक सड़क पहुंचे। छोटी-

30-3-2026/1715/NS-AG/2

छोटी सड़कों के लिए भी हमने बार-बार बजट के लिए कहा है। इसके लिए आर0डी0जी0 पर चर्चा हुई। आर0डी0जी0 तो अभी बंद हुई लेकिन पिछले तीन वर्षों में क्या हुआ, यह भी सोचने वाली बात है। हमारे क्षेत्रों में कोई इस तरह की विजिबल डवलपमैंट चाहे सी0आर0आई0एफ0 को लें तो जो काम पहले के थे उन्हीं पर ही काम हुआ है। आप चाहे नाबार्ड के लें तो उनमें भी कोई पैसे नहीं आए। सड़कों के लिए एक भी स्कीम नहीं आई जबकि कुछेक क्षेत्र ऐसे हैं कि पिछले तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। हमारे क्षेत्रों में भी इस तरीके की थोड़ी समस्याएं हैं, लोग अवरूद्ध हुए हैं और उनको 3-3 किलोमीटर पैदल चलकर अपने सिर पर सामान उठाकर घर ले जाना पड़ता है। अपने जीवनयापन के लिए पहले से ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनको सिर्फ यही चाहिए कि सरकार उसके ऊपर काम करे। पी0डी0एन0ए0 के ऊपर बजट आया और उसमें मेरा भी सरकार के ऊपर क्वालिटी का आक्षेप रहेगा कि इस क्वालिटी को देखा जाए। बहुत ही लापरवाही और गड़बड़ वाले काम हो रहे हैं। कई जगहों पर पत्थर भरने के उदाहरण सामने आए हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसको कभी खुद जाकर भी देखें। वहां पर दीवारों में सीधे पत्थर भरे जा रहे हैं। पतली-पतली ब्रेस्ट वॉल या रिटेनिंग वॉल लगा दी गई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक टिहरी-पंजीहण-रछेड़ा नाबार्ड रोड है उस सड़क के लिए

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

30.03.2026/1720/RKS/DC-1

श्री जीत राम कटवाल जारी...

3.99 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। इस सड़क का निर्माण कार्य लगभग 3 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है लेकिन आज तक इसकी तीन बार मरम्मत करवाई जा चुकी है। वर्तमान में सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं इस सड़क का निरीक्षण करें तथा इसकी जांच भी करवाएं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि इस सड़क के निर्माण में कोई भी नियमों का वायलेशन नहीं हुआ है। यदि आवश्यक हो तो मैं इस सड़क की फोटो भी प्रस्तुत कर सकता हूं और मंत्री जी स्वयं भी इसकी वास्तविक स्थिति का जायजा ले सकते हैं। इस सड़क पर लोगों को बड़ी मुश्किल से बस सुविधा उपलब्ध हुई थी लेकिन सड़क की खराब स्थिति के कारण यह लगभग तीन महीनों तक बंद रही। वर्तमान में इस सड़क की मरम्मत के लिए विभाग के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है। इस सड़क का निर्माण कार्य किस प्रकार किया गया कि इतनी जल्दी यह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। मैं दोषारोपण करने के बजाय माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में लंबित विकास कार्यों, विशेषकर छोटी-छोटी सड़कों के निर्माण और रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। विधायक प्राथमिकताओं के अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 16 सड़कों की डी0पी0आर0 भेजी थी लेकिन उनमें एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण यह बताया गया कि कुछ सड़कों के लिंक के कारण वहां की हैबिटेशन को पहले से ही कनेक्टिड माना गया है। साथ ही इन मामलों का प्रेजेंटेशन विभाग द्वारा उचित ढंग से नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के विधायकों से अधिकारी बात करना आवश्यक नहीं समझते। यह जनता का पैसा है और इसका उपयोग सही स्थान पर ऑप्टिमम उपयोग के साथ होना चाहिए। यदि कोई कार्य चार वर्ष में पूरा होने के बजाय समय से पहले पूरा हो जाए तो अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता है। अतः इस विषय पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए। मैंने रिरडो पुल, दसलेड़ा-खमेड़ा कलां पुल, डुग खड्ड पुल तथा बाला देहलवीं पुल के कार्यों का भी उल्लेख किया है। इन पुलों के डंगों का कार्य लगभग पौने चार वर्षों से रुका हुआ है। आचार संहिता लागू होने के बाद से आज तक ये कार्य विधायक प्राथमिकताओं में शामिल नहीं किए गए हैं। इन विषयों को हमने कई बार प्लानिंग की बैठकों में उठाया लेकिन नई डी0पी0आर0 बनना तो दूर पूर्व में दी गई

प्रस्तावनाओं पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि कार्यों को करवाने हेतु आपने किसी एजेंसी को नियुक्त किया है तो उसमें स्थानीय विधायक से भी परामर्श किया जाना चाहिए। अब एजेंसियां पता नहीं किस आधार पर रिपोर्ट तैयार करती हैं और बाद में यह कह दिया जाता है कि वहां भूमि उपलब्ध नहीं है। वास्तव में लोग भूमि देने को तैयार होते हैं लेकिन उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार आवश्यक है। कई बार लोगों को यह कहा जाता है कि जमीन दो अन्यथा सड़क नहीं बनेगी जोकि उचित नहीं है। लोग जमीन देते हैं परंतु उनके साथ तहजीब के साथ बात करनी पड़ती है। मेरे क्षेत्र की लगभग 14 पंचायतें बहुत ही पिछड़ी हुई है। वहां के लोग कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं। आपको ऐसे क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं पुनः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप टीहरी-पंजीरण-रछेड़ा सड़क का स्वयं निरीक्षण करें तथा इसकी जांच के भी आदेश दें। यह सड़क हर वर्ष क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस सड़क की ऊपर-ऊपर से ही मेटलिंग हुई है। जिस वर्ष इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया उसी वर्ष यह सड़क टूट गई। जब लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क का एस्टीमेट तैयार किया गया था तब यह सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी थी कि इस सड़क कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ। अतः जिन सड़कों की मरम्मत हेतु हमने प्रस्ताव दिए हैं उन पर विभाग गंभीरता से विचार करे। हमने बड़ी उम्मीद के साथ ये सड़कें रिपेयर हेतु डाली हैं ताकि हमारे लोगों अच्छी कनेक्टिविटी की सुविधा मिले। इन सड़कों से ग्रामीण गरीबों, विधवाओं और बच्चों को सीधा लाभ मिलता है। बड़ी गाड़ियों वाले तो अपने आप सारी व्यवस्था कर लेते हैं। कोई इधर से आ जाएगा कोई उधर से, उनके लिए व्यवस्था करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, विधवाएं और बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में मुश्किल आती है। उन्हें 3-3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। आप पी0डी0एन0ए0 क्वालिटी चैक पर भी जरूर गौर करें। इस मद में भी ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है। जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम्ज हैं

श्री बी0एस0द्वारा जारी

30.03.2025/1725/बी.एस./डी.सी.-1

श्री जीत राम कटवाल जारी...

और सी0आई0आर0एफ0 जो सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसके तहत भी सरकार हमारी कुछ स्कीमें ले। हमने भी इसमें एक-आध डी0पी0आर0 बनाई हुई है। वह बाघछाल के पुल से शाहतलाई, हमीरपुर के लिए एक सड़क है। इस बारे में मैंने मुख्य मंत्री महोदय को दो-तीन बार अवगत कराया भी है और इन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि मैं उसको करूंगा। वहां से चंडीगढ़ 42 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है अगर ऊना के रास्ते की तुलना करें। आप बड़सर से ऊना होकर जाएंगे तो किरतपुर 42 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा। वह भी एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव लाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रूट है। उसकी डी0पी0आर0 भी 57 करोड़ रुपये के आसपास है। वह दिल्ली गई है, उसके ऊपर भी मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय गौर करें।

यह जो सबसे बड़ा घोटाला है, यह जो माइनस में रिडक्शन पर टेंडर हो रहे हैं। 10 करोड़ रुपये का टेंडर 7-8 करोड़ रुपये में जा रहा है। अभी पता नहीं विभाग का कंसल्टेंट्स जो बेलगाम हैं उनके ऊपर कोई चेक नहीं है। वह कुछ भी बना कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ठेकेदार हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वे अपने तरीके से कंसल्टेंट्स के साथ मिल बैठ कर एस्टीमेट फ्रेम करवा रहे हैं और फिर काम ले रहे हैं। आम आदमी के लिए जो दूसरे स्टैंडर्ड के काम करने वाले ठेकेदार हैं जैसे कैटेगरी ए0बी0सी0डी0 वाइज जैसे भी होते हैं, अच्छे लोग भी हैं पर उनका पता ही नहीं लगता। अभी मेरे यहां सी0आर0एफ0 का एक टेंडर हुआ था। वह पता नहीं 12-14 प्रतिशत कम हुआ है। वह भी देखने वाली बात है कि क्यों कम हुआ, कैसे इसकी डी0पी0आर0 बनी और अगर डी0पी0आर0 में कमी है तो विभाग बैठकर विधायकों के साथ भी चर्चा कर सकता है, अपने अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा कर सकता है, मुख्य मंत्री महोदय के साथ चर्चा कर सकता है। क्योंकि यह पूरे राज्य की समस्या है कि जितना एस्टीमेट है, यदि वह 10 करोड़ रुपये का है तो वह 6-7-8 करोड़ रुपये में भी लिया जा रहा है और यदि किसी काम की प्राथमिकता तय करनी है तो उसके बारे में भी मैं जरूर कहूंगा कि विभाग गौर करे और जो सड़कों का

30.03.2025/1725/बी.एस./डी.सी.-2

एस0सी0डी0पी0 या वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारे चुनाव क्षेत्रों को भी महत्व दिया जाए। उसमें हमारा हिस्सा मिले, हमें भी

30.03.2025/1725/बी.एस./डी.सी.-2

सड़कें मिलें। सारे क्षेत्र बरसात में प्रभावित होते हैं और सभी को अच्छे रोड की जरूरत होती है। हर क्षेत्र ऐसी अपेक्षा करता है।

आज तुलना का जमाना है, लोग धर्मशाला जाते हैं, शिमला जाते हैं और शाम को यही चर्चा होती है कि वहां के रोड बहुत अच्छे हैं, वहां पानी का सिस्टम बहुत अच्छा है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे यहां भी ऐसा होना चाहिए। आपको हर क्षेत्र में ऐसा ही कार्य करना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि हमारे साथ भी न्याय हो रहा है, हमारी बात भी सुनी जा रही है अन्यथा ट्रांसफर का सिस्टम चलता रहता है और उन्हें तो लोग करवा ही लेते हैं। जो डवलपमैंट का इंपैक्ट होता है वह हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए काम करता है। इसके साथ-साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपका बजट कम है और यह नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। यह बजट करंट प्राइस में 4000 करोड़ रुपये पहले से कम हो रहा है और अगर रियल प्राइस में देखें तो 10 प्रतिशत और जोड़ लें तो यह सरकार के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे चुनाव क्षेत्र में भी बजट का आवंटन धैर्य के साथ करें। उन लोगों को साक्षी मानकर करें और सारे क्षेत्र को एक समान ट्रीट करें। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

30.03.2025/1725/बी.एस./डी.सी.-3

साभपति : अब आदरणीय श्री इन्द्र सिंह जी कटौती प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लेंगे।

श्री इन्द्र सिंह : सभापति महोदय, आपने मांग संख्याः 10, लोक निर्माण और सड़क, पुल एवं भवन के लिए मुझे चर्चा के लिए समय दिया आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

30.03.2026/1730/RKS/DC-1

श्री इन्द्र सिंह जारी.....

के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। जो वहां सड़कें, पुल और भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं हर प्लानिंग की बैठक में मुख्य मंत्री जी को मांग पत्र सौंपता हूं लेकिन अधिकारियों द्वारा इस सदन को ठगा जाता है। मेरी एक सड़क घटा-छपडोहल-बह सिंहन, चण्डयाल-घवाल और चंजाल तक जाती है। मैंन प्रश्न लगाया था कि इस सड़क को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है तो विभाग का कहना था कि उस सड़क में बस चल रही है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि उन अधिकारियों की इंक्वायरी की जाए कि क्या इस सड़क में बस चल रही है? यह सड़क मेरे घर से एक किलोमीटर दूर है। मैं वहां हर रोज सैर के लिए जाता हूं। वहां न साइकिल, न मोटर साइकिल और न ही काई गाड़ी चलती है। यह उस सड़क की दशा है। अधिकारियों ने झूठा जवाब दिया है इसलिए मेरा आग्रह है कि उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दूसरी टावां-कूम्मी सड़क है इसमें 300 मीटर के पोर्शन में बरसात की वजह से मैंटलिंग नहीं हुई थी। माननीय मंत्री जी आप मेरी तरफ देखिए मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। मैंने इस बात को कई बार सदन में रखा है। जो इसका 300 मीटर का पोर्शन है यह क्यों नहीं पक्का हो रहा है? अधिकारियों से जब बात की जाती है तो वे कहते हैं कि इसके टेंडर लगाए जा रहे हैं। इसका बजट प्रावधान भी है लेकिन जानबूझकर इस पोर्शन को पक्का नहीं किया जा रहा है। वे अधिकारी लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? इस पोर्शन से हमारी 5-6 पंचायतों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। हमारी कुम्मी, छातड़ू, क्याल, राजगढ़, कैढ़ , रीगड़, ख्यूरी और गागल

इत्यादि पंचायतें इससे लाभांवित होती हैं। लेकिन इसके पोर्शन को ठीक न करने के कारण हमें 5-6 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। मेरा एक चंडयाल-स्याल पुल है और जो पेड़ीपस्ता पुल है इन दोनों पुलों का काम अधूरा पड़ा है। मैं वर्ष 2022 के बाद लगातार इस बात को उठा रहा हूं। मेरा आग्रह है कि इन दोनों पुलों का कार्य पूर्ण किया जाए ताकि लोगों को बरसात में सुविधा मिल सके। आई0टी0आई0 गागल का शिलान्यास श्री जय राम ठाकुर जी ने किया था। इसका कार्य भी वर्ष 2022 के बाद कछुआ चाल में चला है। उस भवन का कार्य अधूरा पड़ा है। वहां पर प्राइवेट भवन में आई0टी0आई0 चलाई जा रही है और उसका लाखों रुपये किराया जा रहा है। अगर यह भवन बन जाए तो इससे सरकार का लाखों

30.03.2026/1730/RKS/DC-2

रुपये बच जाएगा। मेरा आग्रह है कि इस भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पैसा दिया जाए ताकि ठेकदार को पेमेंट दी जा सके और वह सुचारू रूप से काम करें। साइंस लैब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाल पेड़ी भी लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं लेकिन उसके लिए भी पैस का प्रावधान नहीं है। इसका 50 प्रतिशत कार्य अधूरा पड़ा है। मेरा निवेदन है कि इस लैब के लिए भी पैसा दिया जाए ताकि बच्चों को सुविधा मिले। मेरा एक वेटरिनरी होस्पिटल लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। यहां पर पशुपालन मंत्री जी बैठे हैं। इस भवन के वर्ष 2022 में 2 स्लैब पड़ चुके हैं। उसकी खिड़कियां-दरवाजे सड़ गए हैं लेकिन इसकी फर्निशिंग के लिए पैसे नहीं है। उसके खिड़कियां-दरवाजे नहीं लग रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसके कार्य के लिए पैसे दिए जाएं। आप कहते हैं कि पशुधन सबसे बड़ा धन है। इससे युवा और किसानों को रोजगार मिलेगा लेकिन जब तक हमारे पशु औषधालय ठीक नहीं होंगे

श्री एन0जी0द्वारा जारी

30.03.2026/1735/एच.के.-एन.जी./1

श्री इन्द्र सिंह..... जारी

तब तक हम किस तरह से दूध बेचेंगे और किस तरह गऊओं को पाल सकेंगे? यह मेरा आपसे निवेदन है और इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि इस बिल्डिंग को मुकम्मल कीजिए ताकि लोगों को पशुधन के इलाज के लिए सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, हमारे भनौटू अस्पताल के साथ में एक गर्ल्स व ब्वॉयज़ स्कूल है। उनके साथ एक ग्राउंड बनना था और लोक निर्माण विभाग ने उसके लिए पहले पैसे भी दिए गए थे ताकि बाउंड्री वॉल लगाई जा सके। लेकिन आज तक वह ग्राउंड नहीं बन सका क्योंकि उस ग्राऊंड में मेक शिफ्ट अस्पताल बन चुका है। उसके साथ में पशुपालन विभाग की बहुत बड़ी जमीन है, जहां पर पहले भवन भी बने थे और अब वे गिरा दिए गए हैं। मेरा निवेदन है कि उस भूमि को शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाए ताकि बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड मिल सके। वह स्थान हमारे बल्ह क्षेत्र का एक केंद्र बिंदु है और वहां पर सामाजिक संस्थाएं भी कार्यक्रम करती हैं तथा हमारी राजनीतिक पार्टियों की भी वहां पर जनसभाएं होती हैं। इसके अलावा वहां पर बच्चे खेलने के लिए भी आते हैं। हम कहते हैं कि नशा मुक्ति करेंगे, लेकिन नशा मुक्ति तो तभी होगी जब वहां पर बच्चों के पास खेलने के लिए मैदान होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस ग्राउंड को दुरुस्त किया जाए और बच्चों को खेलने के लिए दिया जाए। इसके अलावा वहां पर मेला भी होता था और लोगों को अपनी संस्कृति बनाए रखने के लिए उस मेले को फिर से शुरू किया जाए।

सभापति महोदय, हमारे कती पुल के पास एक ढांगों गांव है और उस पुल के साथ बहुत बड़ा इरोजन हुआ है। मैंने पिछली बार भी और वर्ष 2023 में भी यह बात रखी थी कि श्री धोली राम के घर के पास बहुत बड़ा कटाव हो गया है, जिससे लगभग दस घरों को खतरा बना हुआ है।

30.03.2026/1735/एच.के.-एन.जी./2

इसी तरह हमारे कवाड़ मार के वार्ड नम्बर-9 में भी ऐसी ही स्थिति है, लेकिन लोक निर्माण विभाग इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। वहां पर लोगों को खतरा बना हुआ है। मैंने माननीय लोक निर्माण मंत्री से इस विषय में व्यक्तिगत तौर पर उनके कार्यालय में जाकर निवेदन किया था कि आप इस रोड को जोकि ढांगों से रडौर तक आता है, उसे एस0सी0सी0पी0 के तहत बनाया जाए। मैंने इसका प्रस्ताव भी डाला था, लेकिन आज तक उसके लिए पैसा नहीं आया और न तो उस सड़क का निर्माण हुआ और न ही कोई प्रोटैक्शन वॉल का कार्य शुरू हुआ। मेरा निवेदन है कि आपने 5 हजार रुपये की राशि एस0सी0 कम्पोनेंट प्लान में डाली है, जबकि वहां पर 80 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है। मुझे शर्म आती है कि केवल 5 हजार रुपये एस0सी0सी0पी0 के तहत दिए गए, इससे अच्छा तो न ही देते। मेरा निवेदन है कि अन्य किसी भी धन का उपयोग किया जाए ताकि उस गांव और कस्बे को बचाया जा सके। अन्यथा बरसात आने वाली है और सड़क का पानी सीधे लोगों के घरों की ओर जाएगा।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक मुख्य मंत्री लोक भवन लेदा है, जोकि तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर ने दिया था। वहां पर हमारी 25 ग्राम पंचायतें हैं और उन पंचायतों के लिए कोई भी ऐसा भवन या होटल नहीं है जहां पर ब्याह-शादि या अन्य कार्यक्रम हो सकें। इसलिए श्री जय राम ठाकुर जी ने यह भवन दिया था। लेकिन अब उसकी फिनिशिंग के लिए लगभग 10 लाख रुपये की आवश्यकता है। यह धनराशि मैं अपनी विधायक निधि से दे सकता था, लेकिन अब तो आप लोगों ने वह विधायक निधि भी बंद कर दी है। ऐसे में हम उस भवन का सुधार कैसे करें? वहां पर चिट्टे व शराबियों का प्रच्चलन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री लोक भवन के लिए भी राशि दी जाए ताकि उसका सुधार हो सके और लोगों को वहां कार्यक्रम करने की सुविधा मिल सके।

30.03.2026/1735/एच.के.-एन.जी./3

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की एक ढ़ोकध्वान सड़क है जोकि सरकीधार नैना माता की ओर जाती है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। आप कहते हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जब सड़कें ही खराब होंगी तो बीमार व्यक्ति अस्पताल तक कैसे पहुंचेगा? वह स्वास्थ्य लाभ कैसे ले पाएगा जबकि सड़कों में जगह-जगह एक-एक फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। केवल 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने में एक घंटे का समय लग जाता है तो ऐसे में कोई भी मरीज रास्ते में अपनी जान खो सकता है। इसलिए मेरा माननीय लोक निर्माण मंत्री से निवेदन है कि उस सड़क को दुरुस्त करने और टारिंग आदि करने के लिए धन का प्रावधान किया जाए। दुसरी सड़क, मेरी

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

30.03.2026/1740/वाई0के0/ए0पी0-01

श्री इन्द्र सिंह जारी .....

भियूरा-स्टोह-दौहल क्षेत्र को जोड़ती है, उसके लिए साइड अप्रोच वॉल हेतु पैसा चाहिए, क्योंकि वह सड़क जगह-जगह से टूट गई है। इस तरफ पानी के नाले हैं और सड़क के किनारे कटाव हो गया है। जिससे सड़क लगभग टूट चुकी है। मैं यह नहीं कहता कि ज्यादा पैसा लगेगा, लगभग 10-15 लाख रुपये की राशि लगेगी। साइड में जो हमारी प्रोटेक्शन वॉल बनेगी, उससे हमारे लोगों को सुविधा होगी और सड़क दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह बैहना-रोपा-बाड़ाधार सड़क जो एस0सी0 कॉम्पोनेन्ट में बनी थी। बरसात की वजह से वह सड़क भी जगह-जगह से टूट चूकी है। इस सड़क पर गांडियों का चलना बड़ा मुश्किल है। उस सड़क को भी एस0सी0 कॉम्पोनेन्ट में 25-30 लाख रुपये की राशि चाहिए, ताकि उस सड़क को ठीक किया जा सके। टिक्कर- मलवाणा, मनसा माता मंदिर सड़क और एक जागर नाला है। उस नालें ने सड़क को लगभग तोड़ दिया है। सड़क टूटने के बाद पानी लोगों के खेतों में चला गया और लगभग 40-50 बीघा खेतों में बड़े-बड़े पत्थर, रेत और बजरी भर गई है। अब न तो पी0डब्ल्यू0डी0 उस रेत को उठा रहा है और न ही पत्थरों को हटा रही है। जिससे सड़क की मरम्मत का काम भी रुक गया है। अभी स्थिति यह है कि

बड़ी गाड़ियां किसी तरह निकल जाती हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं है। वहां मनसा माता मंदिर और ऊपर कांडी देव मंदिर भी हैं, जहां पर लोगों को आने-जाने में कठिनाई होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उस सड़क का निर्माण कराया जाए और जागर नाले से आए पत्थर और रेत को हटाने के लिए पी0डब्ल्यू0डी0 को निर्देश दिए जाएं। मैंने उनसे कई बार अनुरोध भी किया है कि सड़क के किनारे पड़े पत्थरों को हटाकर खेतों को दुरुस्त किया जाए ताकि किसान अपनी फसल लगा सकें। सभापति महोदय, मैं अब आपको अपने क्षेत्र में अपर बल्ह की अन्य सड़कों की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। मेरी सड़क, जो रत्ती से लेकर लेदा तक है, वह जगह-जगह चाहे कोठी की बात हो या हमारे सत्संग घर के सड़क की बात हो वह सड़क जगह-जगह टूटी हुई है। उसे लगभग 15-22 किलोमीटर का रास्ता तय

30.03.2026/1740/वाई0के0/ए0पी0-02

करने में ढाई घंटे लगते हैं, क्योंकि सड़क की हालत बहुत खराब है, ड़गे लग नहीं रहे, पैसा आ नहीं रहा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन महत्वपूर्ण सड़कों को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। बच्चों को स्कूल से आने-जाने में भी बहुत परेशानी हो रही है इसलिए सड़कों के किनारे ड़गे और सड़कों को पक्का करना जरूरी है। साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो रिवालसर का क्षेत्र है, वहां पर एक पार्किंग का निर्माण पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग लगभग 1.25 करोड़ रुपये से हो रहा है, लेकिन वह सड़क अधूरी पड़ी है। वहां विभाग के द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जो काम पूरा नहीं हुआ है, उसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाए। इसी तरह, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो रिवालसर का बस स्टैंड, जिसका फाउंडेशन वर्ष 2021 में हुआ था, उसके बाद एक भी काम उसका आगे नहीं बढ़ा है। पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस बिल्डिंग के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि बस स्टैंड तैयार हो सके। अभी लोगों को बस पकड़ने के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि सड़कों और भवनों के लिए उचित बजट का प्रावधान किया जाए ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल

सके। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं भी सुधरेंगी और पानी की व्यवस्था में भी लोगों को आसानी होगी। अंत में, मैं यही कहूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद। मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दें, उसका चिन्तन करें और इन कार्यों को शीघ्र पूरा करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

30.03.2026/1740/वाई0के0/ए0पी0-03

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी।

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, मांग संख्याः 10 (लोक निर्माण – सड़क, पुल एवं भवन) इस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारा प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और हम अधिकतर अपनी सड़कों पर ही निर्भर हैं। यहां रेल और हवाई कनेक्टिविटी का लाभ सभी को नहीं मिल पाता है।....

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

30.03.2026/1745/AT/YK /01

श्री प्रकाश राणा जारी.....

मैं भी यह मानता हूं कि सड़कों के रख-रखाव और निर्माण के लिए अच्छे बजट की आवश्यकता होती है। दूसरा यह भी है कि जो हमारे प्रदेश में लाखों-करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। अगर हमारी सड़कें ठीक नहीं होंगी तो इससे बहुत गलत संदेश पूरे भारत और दुनिया में जयेगा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हम देख रहे है कि हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को तो उनके अपने-अपने विधायक देख रहे है। वह आपने-आपने क्षेत्रों की

बात भी रख रहे हैं। अगर मैं अपने क्षेत्र जोगिंदरनगर की बात करूं तो वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है। हमारा क्षेत्र लगभग 1000-1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

यह उत्तर विभाग द्वारा दिया गया है। यहां कुल 852 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जिनकी संख्या 258 है। इनमें 146 पक्की सड़कें हैं, जिनकी लंबाई 506 किलोमीटर है और 108 कच्ची सड़कें हैं, जिनकी लंबाई 149 किलोमीटर है। इसके अलावा एम0डी0आर0 की 4 पक्की सड़कें हैं जिनकी लंबाई 198 किलोमीटर है। ऐसा नहीं है कि हमें बजट नहीं मिला। मैंने इस विषय पर पहले भी यह बात रखी थी और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया था। जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन इस समय जोगिंदरनगर क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। मैंने एक नहीं, बल्कि 14 प्रश्न लगाए थे, जिनका जवाब भी हमें मिला है और यहां हमारे पास है

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

सर, मैं बहुत जरुरी बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए लगभग 85 किलोमीटर सड़क को खोदा गया। मैंने कई बार इस बारे में बात भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब सड़क को 4-5 फुट गहरा और 3-4 फुट चौड़ा खोदा गया और उस में केबल बिछाया भी गया। यह सही है और सभी को नई तकनीक की जरुरत भी है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जो रोड खोदे गये उस पर कंपनी अपनी केबल बिछाकर और अपना काम पूरा करके चली गई। उसमें पक्की नालियां बननी थी, जो उस कंपनी द्वारा केबल बिछाने के लिए खोदी गई थी। हालांकि कंपनी ने विभाग को 9 करोड़ 56 लाख 80 हजार 481 रुपये का भुगतान

30.03.2026/1745/AT/YK /02

किया। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी 8 करोड़ 23 लाख 28 हजार 252 रुपये उपलब्ध कराए। यह पैसा दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 21 दिसंबर 2023 तक लगभग 8-9 महीनों में हमें 17करोड़ 80 लाख 8 हजार 653 रुपये हमारे चुनाव क्षेत्र को मिला। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि एक्शन पी0डब्ल्यू0डी0 ने जो कार्रवाई करनी थी, वह सही तरीके से नहीं हुई। जहां नालियां बननी चाहिए थीं वहां एक भी ढंग की नाली नहीं बनाई गई। बहुत मुश्किल से 85

किलोमीटर में से 5 किलोमीटर तक भी ड्रेनेज नहीं बनी। परिणाम यह हुआ कि वर्ष-2023 की बरसात में उन खोदी हुई नालियों में पानी भर गया। सड़कें तो खराब हुई ही। लेकिन साथ ही लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ, ड़गे भी प्रभावित हुए और कच्ची जमीन भी बैठ गई।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....

30-03-2026/1750/केएस/एजी/1

श्री प्रकाश राणा जारी ---

जब हमने प्रश्न किया कि यह पैसा कहां गया तो हैरानी की बात है और मैं मंत्री जी के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि इन्होंने 01 अप्रैल, 2023 से ले कर 31 दिसम्बर, 2023 तक 7-8 महीनों के अंदर 2088 टेंडर लगाए। सोचने की बात तो यह है कि उसमें यह पूरा पैसा खर्च कर दिया गया। टेंडर भी कैसे लगे? मैंने उसके बारे में कहा भी था कि कम से कम जो नालियां बनाने के लिए पैसा आया था उससे नालियां बना देते तो इतना नुकसान ना होता। अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात है कि आज हमारा 85 किलोमीटर रोड इतना खराब हो गया है कि उसमें यह भी पता नहीं चल रहा है कि सड़क गड्ढों में है या गड्ढे सड़क में हैं? अगर वे नालियां बन जातीं तो हमारे रोड तो बहुत अच्छे थे। हम तो यह कह रहे हैं कि हमें नया नहीं दो परंतु जो हमारा पुराना सिस्टम है उसे ही सही कर दो। जब हमने यहां इंक्वायरी मांगी तो मैं विभाग का भी और मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इसे इंक्वायरी के लिए डाला। एक्सिअन की इंक्वायरी हुई जो कि शायद वर्ष 2024 से चली। अब वर्ष 2026 चल रहा है लेकिन डेढ़-दो सालों के अंदर यह ही पता नहीं है कि उसका क्या हुआ? एक्सिअन को 3 साल से ज्यादा वहीं पर हो गए जबकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। यह अप्रैल 1 से लेकर दिसम्बर, 2023 तक की बात थी। उसके बाद जनवरी, 2024 से नवम्बर, 2024 तक 8-10 महीनों में भी काफी पैसा आया। उसमें भी ऑफलाइन 710 टेंडर लगे और ऑनलाइन टेंडर 24 लगे। 9.11 करोड़ रुपये ऑनलाइन टेंडर पर खर्च हुए और ऑफलाइन टेंडर पर 14.50 करोड़ रुपये खर्च हुए जो कि नाबार्ड वगैरह के टेंडर थे और यह सारा विवरण जवाब में आया है। अब एक एक्सिअन ने कम से कम 3 हजार से ज्यादा

तो अपने कार्यकाल में टेंडर ही लगा दिए। नालियां बनतीं तो भी हम मानते लेकिन आज हमारी सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, यह मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं। मंत्री जी का कहना था कि सनसनी ना फैलाओ परंतु यह हमारा काम नहीं है। हम तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे सड़कों को सही कर दो। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में आपदा में जो सड़कें खराब हुईं, वर्ष 2023 का काम तो नहीं हुआ लेकिन वर्ष 2024 में जब फिर बारिश आई तो नुकसान और बढ़ गया । उसके बाद वर्ष 2025 में और नुकसान हो गया और आज हालात ये हैं कि ना वहां पर डंगे हैं और ना सड़कें हैं। ऐसा

30-03-2026/1750/केएस/एजी/2

नहीं कि विभाग ने पैसा नहीं दिया है। वर्ष 2024 में 23.61 करोड़ रुपये के लगभग मिले हैं। वर्ष 2023 में 17.80 करोड़ के लगभग पैसा मिला है। कुछ ऑप्टिकल फाइबर कम्पनी ने डायरेक्ट दिया। मैं कहना चाहता हूं कि वह एक एक्सिअन जिसको वहां पर तीन साल हो गए, अगर वहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है तो उसका हल आज तक क्यों नहीं निकला? माननीय मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं, मैं इनसे भी चाहता हूं कि उसका कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। इतना पैसा लगने के बाद फिर सड़कों को क्यों सही नहीं किया गया? पता नहीं कितने शिलान्यास और उद्घाटन वहां पर हो गए। मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, इनकी जानकारी में भी होगा। मैंने इस सम्बन्ध में जो प्रश्न लगाया था उसमें तो दो ही बताए गए। विभाग शिलान्यास और उद्घाटन कर रहा है, वह भी एक ऐसे आदमी के हाथ जिसके पास कोई संवैधानिक पद ही नहीं है। मंत्री जी, क्या आपको इसकी जानकारी है कि कितने शिलान्यास या उद्घाटन हुए? मैं आपको उसकी जानकारी फोटो के साथ डिटेल में दे दूंगा। पता नहीं क्या हो रहा है। हैरानगी की बात तो यह है कि यह उद्घाटन विभाग कर रहा है। सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस है फिर यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? इतना पैसा लगने के बाद, अगर इसका टोटल करते हैं तो 17.80 करोड़ रुपये वर्ष 2023 में लग गए, अभी वर्ष 2025 का तो मैंने देखा ही नहीं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

30.03.2026/1755/av/ag/1

श्री प्रकाश राणा--------- जारी

इसके जो टैण्डर लगे और जो उस बारे में जवाब आया है तथा 40 करोड़ रुपया एक ही सड़क पर लग गया तो आप इसकी जांच करवाइए। हमने पहले कभी इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना कि हम अभी देख रहे हैं। मैंने एक बार मंत्री जी से अनुरोध भी किया था कि आपने जांच करवाई, हम मानते हैं। परंतु डेढ़ महीने के बाद वहां पर वही एक्सियन दोबारा से आ गया। अगर उस एक्सियन की जांच चली है तो वह वहां पर क्यों बैठा है? उस एक्सियन को वहां पर तीन वर्ष हो चुके हैं बाकी जगह तो पता नहीं कितने-कितने चेंज हो गए। वह एक्सियन जब वहां पर डेढ़ महीने के बाद दोबारा आया तो उसने पेपर में भी दिया कि देखो हम फिर से यहां आ गए, मेरे पास उस पेपर की क्लीपिंग भी है। यह अच्छी बात नहीं है और मेरा कहना यह है कि चलो हमें नया न मिले लेकिन हमारे पुराने सिस्टम को ही सही कर दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारी सड़कें बनें। हमारी कई पंचायतें जैसे नैर-घरवासड़ा और मनोह गांव है जहां से बस्सी-मनोह रोड की स्लाइडिंग के कारण पूरा गांव खतरे की जद़ में आ गया। उसको लगभग 20 फीट डंगा लगना था परंतु वह अभी तक नहीं लगा। हमारे रोड़्ज नहीं खुल रहे हैं। यह मैं पिछली आपदा के दौरान हुए नुकसान की बात कर रहा हूं और अभी फिर से बरसात आने वाली है। वहां उस पूरे गांव को खतरा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इसको देखो। ऐसा भी नहीं है कि वहां पैसा नहीं मिला, पैसा तो मिला है। हम पैसे के लिए तो बोल ही नहीं रहे हैं। वहां पैसा आया परंतु लगा या नहीं; इस बारे में एक बार जांच तो कर लीजिए कि वह पैसा कहां और कैसे लगा। मेरा यह अनुरोध है और अब तो माननीय मुख्य मंत्री भी आ गए हैं। मैं तो यह कहता हूं कि हमारे पुराने सिस्टम को ही सही कर दीजिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। माननीय मंत्री, एक बार दौरा करके आप वहां की स्थिति तो देख लीजिए। अगर वहां समय पर नालियां बना दी होतीं तो शायद उधर इतना नुकसान नहीं होता। लोक निर्माण विभाग का कितना बजट है या नहीं है, परंतु जो भी है आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में

सड़कों को ठीक कर दीजिए क्योंकि गांवों की जनता इन सड़कों पर पूरी तरह से निर्भर है। प्रदेश की सड़कें अच्छी होंगी तो यहां पर ज्यादा पर्यटक

30.03.2026/1755/av/ag/2

आएंगे तथा यहां से खुश होकर जाएंगे। पूरे प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए सड़कों के लिए कुछ-न-कुछ कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय की कमी के बावजूद सभी को थोड़ा-थोड़ा बोलने का समय दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

30.03.2026/1755/av/ag/3

अध्यक्ष : अब 06.00 बजने के लिए केवल एक-आधा मिनट शेष रहता है, आधे मिनट में तो अगले माननीय सदस्य बोल नहीं पाएंगे।

इसलिए अब में गिलोटिन अप्लाई करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम न० 3 में दर्शाई गई धनराशियां क्रमशः 4,32,53,23,46,000/-(राजस्व) रुपये व 33,71,46,02,000 (पूंजीगत)/- रुपये संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम न० 3 में दर्शाई गई धनराशियां क्रमशः 4,32,53,23,46,000/-(राजस्व) रुपये व 33,71,46,02,000 रुपये (पूंजीगत) संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

मांगें पूर्ण रूप से पारित हुईं ।

सरकारी विधेयक टी सी द्वारा जारी

30.03.2026/1800/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

अध्यक्ष .... जारी

अब सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा।

विधेयक पर विचार-विमर्श और पारण

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3)पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग ।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार

30.03.2026/1800/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3)को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3)को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

'हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3) पारित हुआ'।

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, 31 मार्च, 2026 के 11.00 बज़े पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **(यश पाल शर्मा)**
दिनांक : 30 मार्च, 2026 **सचिव।**